हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

2 मार्च, 2012

खण्ड - 1, अंक - 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 2 मार्च, 2012

शोक प्रस्ताव	(4)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)2
मेवात क्षेत्र में विकास कार्यों पर अल्प-अवधि चर्चा	(4)19
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(4)21
अति विशिष्ट व्यक्तियों, जिला बार संघ, करनाल के प्रधान एवं सदस्यगण तथा हरियाणा पत्रकार संघ, सिरसा के सदस्यगण का अभिनंदन	(4)65
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(4)65
अध्यक्ष द्वारा घोषणा -	(4)67
अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना	
विभिन्न मामले उठाना	(4)67
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(4)69
वाक आउट	(4)81
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भण)	(4)82
सरकारी संकल्प	(4)84

अध्यक्ष द्वारा घोषणा (4)86

बाबा भीम साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण बारे

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (4)87

बैठक का समय बढ़ाना (4)110

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण) (4)110

वाक आउट (4)112

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण) (4)113

वर्ष 2011-2012 के लिये अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना (4)113

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (4)114

वर्ष 2011-2012 के लिये अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (4)114

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 2 मार्च, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में पूर्वाह्न 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will make the obituary reference.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा की माता श्रीमती कलावती के 1 मार्च, 2012 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्रीमती कलावती एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका जीवन सादगी, सच्चाई एवं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति था। वह एक मृदुभाषी, मिलनसार एवं नेक स्वाभाव की महिला थी। उन्होंने सदैव ही जीवन में नैतिक मूल्यों को अधिमान दिया और सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी गहरी रूची थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वर्गीय दलबीर सिंह जी की अर्धांगिनी के रूप में सामाजिक और राजनैतिक जीवन में एक निर्णायक भूमिक निभाई। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, सदन में पार्लियामैंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें हम भी अपने आपको शामिल करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के नेता की तरफ से केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा की माता श्रीमती कलावती के 1 मार्च, 2012 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। श्रीमती कलावती एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं । उनका जीवन सादगी, सच्चाई एवं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति था। वह एक मृदुभाषी, मिलनसार एवं नेक स्वभाव की महिला थी। उन्होंने सदैव ही जीवन में नैतिक मूल्यों को अधिमान दिया और सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी गहरी रूची थी। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अम्बाला की सांसद एवं केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा की माता श्रीमती कलावती के हुए दु:खद निधन पर अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस शोक प्रस्ताव में अपने आपको शामिल करता हूं। मैं स्वर्गीय श्री दलबीर सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती कलावती के 1 मार्च, 2012 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्रीमती कलावती हमारी केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की माता थी। इनका अपने पति और पुत्री के कारण लोगों से काफी सम्पर्क भी रहा। हमारे भी उनके साथ

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

पारिवारिक संबंध थे। मुझे भी उनसे काफी बार मिलने का अवसर मिला। वे एक मृदुभाषी और सेवा भाव रखने वाली महिला थी। जैसा सबको मालूम है कि वे इस उम्र में भी सदैव हंसमुख रहती थीं। कल उनका निधन हो गया। मैं अपने परिवार की तरफ से तथा पूरे प्रदेश की तरफ से उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by the leader of the House and the other Members of the House. I also deeply feel grieved on the sad demise of Smt. Kalawati W/o Late Ch. Dalbir Singh Ji, Ex-Union Minister and mother of Kumari Selja, Union Minister.

She was a pious religious lady and was dedicated to the cause of upliftment of downtrodden and weaker section of the society and was also a social worker. I pray to almighty to give peace to the departed soul.

I will convey the feelings of this House to the bereaved family. Now I will request you kindly stand up in your seats to pay homage to the departed soul.

(At this stage, the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the questions hour.

New Transport Policy

806. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Haryana Government has notified any new transport policy to bridge the gap between the demand and supply of transport services in Haryana together with the salient features of the policy;

(b) reasons for delay in the implementation of aforesaid policy and the time by which the said policy is likely to be implemented; and

(c) the number of total buses in Haryana Roadways and how many out of these are on road together with the position in March, 2005 ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Sir, a statement is placed on the table of the House.

Statement

(a) Yes Sir, The salient features of the policy are as follows :—

(i) Under the Policy, 2694 permits on 965 routes will be given to private operators. The identified routes will provide connectivity between villages and district/sub divisional headquarters and other important destinations.

(ii) Permit fee of Rs. 10000/- for full body bus and Rs. 5000/- for mini bus will be payable. Besides, passenger tax @ Rs. 25,000/- and Rs. 12,500/- per month in respect of full body bus and mini bus respectively is payable by the permit holders. Motor Vehicle Tax @ Rs. 550/- per seat per year will also be charged.

(iii) Fare structure shall be as per directions issued by the State Government/State Transport Authority/Regional Transport Authorities from time to time.

(iv) Private operators shall be obliged to carry students and other concessional or free pass holders in their buses in the same way as is done by Haryana Roadways buses.

(v) Existing permit holders of 1993 and 2001 approved schemes shall be given preference over the new applicants in the allotment of permits in accordance with the details contained in the scheme.

(vi) Permits shall be granted to Co-operative Transport Societies of un-employed persons registered in Haryana and un-employed persons. The individual applicant and members of the Co-operative Transport Societies should be domicile of the State of Haryana and atleast 10th pass. The applicants shall be more than 18 years and less than 45 years of age.

This eligibility criteria, however, shall not be applicable to the permit holders of 1993 and 2001 schemes.

(b) The policy could not be implemented so far because of pendency of a Civil Writ Petition in Punjab and Haryana High Court. It will be implemented immediately after receipt of the orders of the court or clarity of legal position in the matter.

(c) As on 31-12-2011 Haryana Roadways had a fleet of 3485 buses and almost all were roadworthy. As on 31-3-2005 Haryana Roadways had a fleet of 3294 buses and almost all were roadworthy.

प्रो० सम्पत सिंह : सर, मैंने आज सुबह-सुबह न्यूज़ पढ़ी है जिसके लिए मैं यू०पी०ए० गवर्नमैंट को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं जो कल उन्होंने एक्सीडैंट्स की संख्या को बढ़ते हुए देखकर मोटर व्हीकल एक्ट में काफी सख्ती की है। आज रोड ट्रैफिक किलर ट्रैफिक का रूप धारण करता जा रहा है जिसको रोकने का प्रयास यू०पी०ए० गवर्नमैंट ने किया है। इसके लिए मैं यू०पी०ए० गवर्नमैंट को बधाई देता हूं। हरियाणा प्रदेश का जहां तक सवाल है डिमाण्ड और ट्रांसपोर्ट की सर्विसिज़ की फैसीलिटी के अंतर को कम करने हेतु हरियाणा गवर्नमैंट ने एक बहुत ही बेस्ट पालिसी बनाई है। मैंने भी इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत से सजेशंज़ दिये थे they were included for which I am highly obliged लेकिन अभी तक यह पॉलिसी लागू नहीं हुई है। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो कोर्ट का जिक्र किया है उसमें इन्होंने स्टे के बारे में कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि pendency of the Civil Petition in Punjab and Haryana High Court it will implemented immediately after receipt of the order of the Hon'ble Court or clarity

[प्रो० सम्पत सिंह]

of legal position in the matter. इसका मतलब है कि स्टे है या नहीं यह इसमें क्लीयर नहीं आ रहा है अर्थात् इसमें यह कहा गया है कि कोर्ट से क्लीयरटी आ जायेगी उसके बाद इमीडिएटली इसको लागू कर दिया जायेगा। Sir, it is our need. दूसरी बात, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि हम जो पॉलिसी में ट्रांसपोर्ट सर्विसिज देने जा रहे हैं उसके तहत हमारी कितनी प्राईवेट बसें चलेंगी। जैसे सरकारी बसों के बारे में बता दिया गया कि उनकी संख्या 3400 के आसपास होगी। Speaker Sir, here I would like to quote Kerala. केरल की पापूलेशन हमारे से लगभग 30 परसैंट ज्यादा है और एरिया हमारे से कम है। इसके बावजूद वहां पर सरकारी बसें केवल 2000 हैं और प्राईवेट बसें चलती हैं 32000। जैसा हमारे यहां पर ट्रैफिक हैजर्ड है वहां पर यह बिलकुल भी नहीं है। हमारे यहां पर तो प्राईवेट व्हीकल्स में सवारियों को मार्चर की तरह ले जाया जाता है। कोई बस चल रही है, कोई मैक्सी कैब चल रही है, ऊपर से भरी हुई है, नीचे से भरी हुई है, सवारियां लटक रही हैं और ड्राईवर भी नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि डिमाण्ड बढ़ रही है इसलिए इस पोजीशन को दूर करने के लिए गवर्नमैंट ने बहुत ही एप्रीशियेबल स्टैप्स उठाये हैं। मैं चाहता हूं कि इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाए और कोर्ट के आर्डर के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाये। दूसरी बात मैं इस बारे में यह जानना चाहता हूं कि जो प्राईवेट बसों को रूट दिये गये हैं इन पर कितनी बसें चलेंगी और सरकारी बसों को मिलाकर कुल कितनी बसें हो जायेंगी। क्या इससे हमारी डिमाण्ड पूरी हो जायेगी और अगर नहीं होगी तो फिर उस डिमाण्ड को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौधरी सम्पत सिंह जी ने दो प्रश्न पूछे हैं। अगस्त, 2011 में कुछ लोग सरकार की इस नीति के खिलाफ हाई कोर्ट में गये थे जैसा कि आप भी स्वयं वकील हैं और चौधरी सम्पत सिंह जी भी जानकार हैं। माननीय अदालत ने हमारे काऊंसल को यह निर्देश दिया कि वे हालांकि स्टे आर्डर नहीं इश्यू कर रहे हैं परन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने यह कहा कि आप इस नीति का तब तक क्रियान्वयन मत करिए जब तक इस बारे में हमारा निर्णय नहीं आ जाता। Speaker Sir, Oral direction of the court is also a direction. Our counsel gave in writing to us that this is a direction that has been given by the court without passing a formal order which we Honoured Sir. The judgement is now reserved. We are awaiting the day the judgement would be delivered by the court. We are very hopeful that the policy is legally sound and constitutionally valid and it will be upheld by the court. Moment the judgement comes, we will immediately proceed to implement the policy. As Shri Sampat Singh ji asked, as part of the second question, we are issuing 2694 permits to begin with. These are on 965 routes. So, these many buses will be immediately added. Once this policy comes into force and we give a concession to the earlier permits holders also. There has been a general complaint of earlier permit holders, Sir, and you have also mentioned in earlier sessions that the routes that were given in the two earlier policies were not necessarily very profitable. That is why they do not run buses on the routes that they should be running and they are normally found plying buses elsewhere. Then, they are challaned. So, we are giving them five options of opting for five different routes. 300 such people have also applied to us. We will give them right to choose as a matter of first preference and change their routes so that their routes also become profitable routes. After all, they are also boys and girls who have formed cooperative societies and belong to Haryana. Once all these buses are added, then Government will see how many further routes can be added. At this juncture, it will be difficult for me to

say that after these 965 routes are allotted how many more routes would be added. My learned friend may wait. Let us proceed with this policy implementation. Let thousands of young men and women who have formed cooperative societies, get a chance of employment and livelihood. They should get a means of livelihood and people should get a means of transportation and then we will proceed further as per their demands.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं।

Mr. Speaker : I think he has exhaustively answered your question and there is no need for a second supplementary.

Prof. Sampat Singh : Sir, I want to know because it is an important issue and I am appreciating like anything of this policy. इसमें कोई दो राय नहीं है।

Mr. Speaker : A detailed reply has come.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आती है तब तक जो अनअथॉराईज्ड व्हीकल चल रहे हैं, मैक्सी कैब्स चल रही हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको रोकने का कोई विकल्प ढूंढिये। इसमें देश का औसत रेट 366 का है जबकि हमारा औसत रेट 13 का है जो कि जनसंख्या के अनुपात में 6.5 होना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो अनअथॉराईज्ड जीप, बसिज और मैक्सी कैब्स चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि वे हमें मोर्चरी की तरफ ले जा रही हैं ताकि हरियाणा इस तरह के केसिज के लिए बदनाम न हो।

Mr. Speaker : It is a suggestion Mr. Minister.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, the suggestion is noted. Maxi Cabs are not unauthorized. They have also been given licenses. It is a fact that there are some Maxi Cab Dirvers who do drive in a rash and negligent fashion वे सवारियां भी ऊपर नीचे बैठा लेते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आ जायेगी और जब 2700 नई बसें आ जायेंगी तो मैक्सी कैब वाली समस्या नहीं रहेगी और लोगों को हम और ज्यादा अच्छी परिवहन सुविधा दे सकेंगे।

To open an ITI in Safidon City

***843 Shri Kali Ram Patwari :** Will the Industrial Tranining Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ITI in Safidon City; if so, the time by which aforesaid ITI is likely to be opened ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukal Matanhail) : No, Sir.

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सफीदों जींन्द जिले का काफी बड़ा उप-मण्डल है वहां पर लगभग 25 हजार की आबादी है और वहां पर आसपास कोई भी आई.टी.आई. नहीं है जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि सरकार का आई.टी.आई. खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सफीदों जीन्द जिले का एक ब्लॉक है और जीन्द में काफी आई.टी.आई. चल रही हैं। इस वर्ष को सरकार ने युवाओं के लिये मनाने का फैसला लिया है तथा इसमें हमारा टैक्नीकल एजूकेशन पर पूरा जोर रहेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा तो इस समय जीन्द में भी एक आई.टी.आई. चल रही है और इसके अलावा जीन्द में महिला आई.टी.आई. भी चल रही है। इसमें 184 के करीब इन्टेक कैपेसिटी है। जुलाना में और नरवाना में भी आई.टी.आई. चल रही है। सफीदों में गवर्नमैंट आई.टी.आई. मुआना में है जोकि केवल मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उचाना में डूमर खां में भी एक आई.टी.आई. है और उचाना खुर्द में भी एक आई.टी.आई. है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमने नई-नई आई.टी.आईज. खोलने का पूरा प्रयास किया है। जींद जिले में हमारी कुछ प्राईवेट आई.टी.आईज. भी हैं। ये सारी आई.टी.आईज. जीन्द जिले के जो हमारे बच्चे हैं उनकी एजूकेशन की रिक्वायरमैंटस को पूरा करती हैं। जीन्द जिले में तकरीबन तीन प्राइवेट आई.टी.आईज. हैं। गवर्नमैंट आई.टी.आई. जो मुआना है उसकी इन्टेक कैपेसिटी 68 सीट्स की थी। अब इस आई.टी.आई. की इन्टेक कैपेसिटी को बढ़ाकर 250 किया जा रहा है ताकि हमारे जीन्द जिले के बच्चों को खास तौर से सफीदों शहर के बच्चों को आई.टी.आईज. के माध्यम से पूरी तरह से शिक्षा मिल पाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का हर ब्लॉक में आई.टी.आई. बनाने का प्रयास है और जहां तक इन्होंने आई.टी.आई. खोलने के लिए क्राइटेरिया की बात की है तो मैं इनको बताना चाहूंगी की इसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमैंटस हैं। 400 इन्टेक की सिटिंग कैपेसिटी वाली आई.टी.आई. के लिए तीन से पांच एकड़ लैण्ड की जरूरत होती है। उसकी बिल्डिन्ग्ज, टूल्ज और मशीनरी के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। इसके लिए 70 से 72 का स्टॉफ जरूरी होता है जिस पर रैकरिंग खर्चा तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये का रहता है।

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि मुआना के अन्दर आई.टी.आई. है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुआना की आई.टी.आई. में कितने टीचर्स हैं और वहां कितने बच्चों का एडमिशन है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सैपरेट प्रश्न है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जीन्द जिले की एग्जिस्टिंग आई.टी.आईज. के बारे में मैंने बता ही दिया है। इन्होंने सफीदों की मुआना आई.टी.आई. का जिक्र किया है तो वहां इस समय चल रहे कोर्सिज की लिस्ट के बारे में हम माननीय सदस्य को लिखकर भिजवा देंगें।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय जी ने कहा है कि हर ब्लॉक में आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिला मेवात में पुन्हाना ब्लॉक के अन्दर आई.टी.आई. बनाने का क्या सरकार का कोई विचार है ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर, आई.टी.आई. ने हरियाणा में पिछले साल एक कमेटी नियुक्त की थी उस कमेटी ने पूरे प्रदेश का सर्वे किया था। वह कमेटी पुन्हाना ब्लॉक में भी गई थी । पुन्हाना ब्लॉक में पिनंगवा, पुन्हाना और सिकरावा जोकि एक कस्बा है तीनों जगह इन्होंने सर्वे किया था। इस सर्वे में कमेटी ने यह कहा था कि बहुत जल्दी हम यहां आई.टी.आईज. खोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पुन्हाना ब्लॉक के पुन्हाना हल्का में भी कोई आई.टी.आई. खोलने बारे सरकार का विचार है और यदि है तो कब तक वहां आई.टी.आई. खोल दी जाएगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि मेवात जिले को विशेष तौर से शिक्षा के मामले में जिसको हम पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं। मेवात रीजन में सभी ब्लॉक्स में आई.टी.आई. खोलने का सरकार का प्रावधान है। माननीय सदस्य ने जहां तक आई.टी.आई. पुन्हाना की बात रखी है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि मुबारकपुर जोकि पुन्हाना के पास है वहां पर इसके लिए जगह दी जा रही है और इसकी बिल्डिंग ड्राइंग्ज वगैरह बना ली गई है और अति शीघ्र यह आई.टी.आई. बन जाएगी । (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, यहां बार बार मेवात को पिछड़ा हुआ कहा जाता है। मेवात किस की वजह से पिछड़ा है। मेवात इन लोगों की वजह से पिछड़ा न कि मेवात की लोगों की वजह से। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेवात को बार-बार क्यों पिछड़ा हुआ कहा जाता है ? अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि मेवात को बार-बार पिछड़ा क्षेत्र क्यों कहा जाता है ? इसके साथ-साथ ये यह भी बताएं कि यह किसके कारण पिछड़ा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम गीता भुक्कल जी, आप मेवात को पिछड़ा मत कहो क्योंकि अब तो मेवात के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि पिछड़े हुए मेवात क्षेत्र की तरक्की के लिए इस सरकार ने बहुत कार्य किये हैं। 12th फाईनेंस कमीशन में हमारा तकरीबन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा development of infrastructure for industrial training institute in Mewat region का अलग से प्रोजैक्ट है। मेवात में आई.टी.आई., नूंह जोकि इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें तकरीबन 1072 सीट्स की कैपेसिटी है, आई.टी.आई., पुन्हाना जिसका कार्य हम अतिशीघ्र शुरू करेंगे उसकी 400 की कैपेसिटी होगी। इसके अतिरिक्त आई.टी.आई., पिंगवाना, आई.टी.आई., तावडू, आई.टी.आई., पुन्हाना (दुमैन), आई.टी.आई., फिरोजपुर झिरका (दुमैन), आई.टी.आई., उजीना (दुमैन) इन सभी आई.टी.आईज. में अलग-अलग 125 सीट्स की कैपेसिटी है। इस तरह सरकार ने अलग से 2072 सीट्स की कैपेसिटी के हिसाब से मेवात रिजन के उत्थान के लिये पूरे प्रयास किये हैं।

मास्टर धर्मपाल सिंह ओबरा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रश्न पर चार सप्लीमैंटरिज अलाऊड थी जबकि एक प्रश्न पर केवल दो ही अलाऊड होती हैं (विघ्न)। फिर भी मास्टर जी, बोलिये, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

मास्टर धर्मपाल सिंह ओबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सिवानी खेड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी ने, रामकिशन फौजी जी ने, श्रुति चौधरी जी ने और सोमवीर जी ने मिल कर आई.टी.आई. का शिलान्यास किया था जबकि वहां आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां आई.टी.आई. कब तक बनेगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत जोर देकर जो आई.टी.आई., सिवानी की जो बात रखी है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि पी.पी. पी. मोड के तहत गवर्नमैंट ऑफ इंडिया में आई.टी.आई., सिवानी के लिए प्रपोजल पैंडिंग है जिसकी अप्रूवल आते ही आई.टी.आई., सिवानी का कार्य अतिशीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 865

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम सर्राफ इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Arrangements to Drain out Rainy Water

***1084. Shri Anand Kaushik :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make arrangement to drain out rain water from Faridabad City; if so, the time by which the arrangements for draining out of rain water are likely to be made ?

शहरी स्थानीय निकास राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : हां श्रीमान जी। विवरण अनुबन्ध 'क' पर दिया गया है।

विवरण

अनुबन्ध 'क'

नगर निगम, फरीदाबाद ने फरीदाबाद शहर से बरसाती पानी की निकासी हेतु प्रबन्ध बारे निम्न प्रमुख प्रस्ताव दिए हैं। ये स्कीम या तो पूर्ण हो चुकी है या क्रियान्वित की जानी है। ये सभी परियोजनाएं 31-8-2012 तक पूरी होनी सम्भावित हैं। इन परियोजनाओं की समयबद्ध वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :--

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (राशि करोड़ों में)	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4
1.	पूर्वी पैराफेरी बाईपास रोड नजदीक बुढिया नाला सैक्टर 29 टी प्वाइंट, नजदीक खेडी ब्रिज व सैक्टर 14 पर 4 पम्पिंग स्टेशन्स	25.00	पूर्ण
2.	पाला चौक तथा सैक्टर 64 बाई पास पर 2 अतिरिक्त पम्पिंग स्टेशन	1.70	पूर्ण
3.	सैक्टर 6 व 7, 4-6, 4-7 तथा 7-8 को विभाजित करने वाली रोड पर 3 नालों का निर्माण	3.60	पूर्ण
4.	नवादा चौक से एन०एच०-3 पर भूमिगत नाला व पम्पिंग स्टेशन निर्माण	1.00	30-4-2012

1	2	3	4
5.	पंचायत भवन के नजदीक बल्लबगढ़ में एक पम्पिंग स्टेशन का निर्माण	3.50	30-6-2012
6.	एन०आई०टी० क्षेत्र हेतु गुच्छी नाला पर 4 पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण	3.80	31-8-2012
7.	बौद्ध विहार चौक से हितकारी चौक तक एक नाले का निर्माण	4.00	31-8-2012

इसके अतिरिक्त, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने फरीदाबाद के विभिन्न सैक्टरों से बरसाती पानी की निकासी हेतु निम्न कार्य प्रारम्भ किये हुए हैं :--

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
1.	आंतरिक एवं ब्राह्य स्टॉर्म वाटर निकासी की बरसाती पानी की निकासी सहित की स्कीम सैक्टर 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15ए, 16, 16ए, 17, 19, 21ए, बी, सी, डी, 22, 23, 24, 28, 29, 30 व 31.	सक्रिय तथा नगर निगम, फरीदाबाद को दिनांक 1-4-1992 को सुपुर्द
2.	सैक्टर 45, 46 व 48 के बरसाती पानी की निकासी गुरत्वाकर्षण से बुढिया नाले में फरीदाबाद नाले के माध्यम की जा रही है।	सक्रिय तथा नगर निगम, फरीदाबाद को दिनांक 1-4-1992 को सुपुर्द
3.	आगरा कैनाल के पार सैक्टर 70, 75-89, फरीदाबाद का एक्सटरनल स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल जिसकी अनुमानित राशि 106.16 करोड़ रुपये है, विचाराधीन है।	दिसम्बर, 2014
4.	रिहायशी सैक्टर नं० 2, 55-56, 58-65 फरीदाबाद के एक्सटरनल स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल की स्कीम तैयार की जा रही है।	मार्च, 2015

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, जो (क) कालम में इन्होंने लिखा है "सैक्टर 6-7, 4-6, 4-7, 7-8 को विभाजित करने वाली रोड पर तीन नालों का निर्माण" यहां पर केवल एक नाले का ही निर्माण हुआ है और बाकी तीन नालों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और जिस नाले का निर्माण हुआ है उसमें भी मिट्टी भरी होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त जो यहां का सीवरेज सिस्टम है, उसकी भी अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : कौशिक जी, आप सप्लीमैंटरी पूछिये।

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि ये नाले कब तक साफ होंगे और कब तक इनकी ड्रेनेज बनेगी ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में पैराफरी बाई-पास नजदीक गुडिया नाला, सैक्टर 29 वाईड नजदीक खेड़ी ब्रिज तथा सैक्टर 14 में चार पम्पिंग स्टेशन की जो परियोजनायें हैं ये सभी 25 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी हैं और जो अभी मेरे साथी ने सैक्टर 6-7 के बारे में पूछा यह परियोजना भी करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से पूरी हो चुकी है और अगर किसी नाले में कोई प्राब्लम है तो वह माननीय सदस्य मुझे लिखित में दे दें, मैं उसको चैक करवा लूंगा क्योंकि वहां पर फरीदाबाद के लिये विशेष रूप से मशीनें और पैसा रखा हुआ है।

YMCA University of Technology

***1089. Shri Ajay Singh :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the month and year when the YMCA University of Science & Technology, Faridabad came into existence; and

(b) whether regular Vice-Chancellor and Registrar have been appointed in the aforesaid University, if not, the reasons thereof;

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) वाई.एम. सी. ए. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद 01 दिसम्बर, 2009 को अस्तित्व में आया।

(ख) एक नियमित उप-कुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति कुलपति की सलाह के लिए सरकार के पास विचाराधीन है। इस दौरान विश्वविद्यालय के मामले राज्यपाल के सचिव श्री मोहिन्दर कुमार द्वारा उप-कुलपति के रूप में तथा डॉ० ए० के० शर्मा प्रोफैसर, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं डीन (इंजी० एवं प्रौद्योगिकी) द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में सम्भाले जा रहे हैं।

टिप्पणी

वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के पूर्व तथ्यों की टिप्पणी -

तकनीकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वाई०एम०सी०ए० इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनाया जाये ताकि स्नातकोत्तर कोर्स सुचारू रूप से चलाये जा सकें और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के स्नातक पास छात्र अपनी योग्यता में सुधार करके देश के हित में हों। इसलिए वाई०एम०सी०ए० इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनाया जाये। दिनांक 1-12-2009 से वाई०एम०सी०ए० इंजी. संस्थान, फरीदाबाद से वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद एक्ट नं० 21/2009 के तहत बनाया गया ।

वाई. एम.सी.ए. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में आज की तारीख तक नियमित कुलपति नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि, महामहिम राज्यपाल, हरियाणा ने श्री ए०के० सिंह, आई०ए०एस०, सचिव, महामहिम राज्यपाल, हरियाणा को विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का अतिरिक्त

प्रभार दिनांक 1-12-2009 से सौंपा गया, जब से विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। श्री सिंह के स्थानान्तरण के बाद श्री मोहिन्दर कुमार, आई.ए.एस. को महामहिम राज्यपाल हरियाणा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का अतिरिक्त प्रभार 24-4-2010 से नियमित नियुक्ति होने तक सौंपा गया है। विश्वविद्यालय के अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार उप-कुलपति की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति में है।

वाई०एम०सी०ए० विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति आज की तारीख तक नहीं की गई है। विश्वविद्यालय के गठन के बाद कुलपति द्वारा डा० अशोक कुमार, तत्कालीन निदेशक प्रधानाचार्य, वाई०एम०सी०ए० इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 10-12-2009 से दिनांक 31-5-2010 तक सौंपा गया। इसके बाद डा० ए० के० शर्मा, प्रोफेसर (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं डीन) को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 1-6-2010 से सौंपा गया जो अब तक संभाल रहे हैं। जबकि विश्वविद्यालय के नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति में है।

वाई०एम०सी०ए० इंजी० संस्थान, फरीदाबाद से वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनने तक के पदों /कोर्सों व सीटों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :--

क्रम संख्या	पद का नाम (सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त)	वाई०एम०सी०ए० इंजी० संस्थान, फरीदाबाद से वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनने से पहले (30-11-2009 को)			वाई०एम०सी०ए० इंजी० संस्थान, फरीदाबाद से वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनने से बाद (1-12-2009 को)		
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
1.	प्रोफैसर	20+1 (निदेशक/ प्रधानाचार्य	04	17	21	10	11
2.	एसोसिएट प्रोफैसर	35	22	13	36	23	12
3.	सहायक प्रोफैसर	91	68	23	90	76	14
	कुल	**147**	**94**	**53**	**147**	**109**	**38***

विभिन्न शिक्षण पदों के लिए 9 व 10-1-2012 को साक्षात्कार किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् की 12-3-2012 को होने वाली बैठक के बाद चयनित उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया जाएगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित विभिन्न शाखाओं में इंजी० एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्सों की वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की सूचना :--

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

क्रम संख्या	शाखा का नाम	वाई०एम०सी०ए० इंजी० संस्थान, फरीदाबाद से वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनने से पहले (30-11-2009 को)	वाई०एम०सी०ए० इंजी० संस्थान, फरीदाबाद से वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद बनने के बाद (30-11-2009 को)
1	2	3	4
(ए)	**स्नातक स्तर के कोर्स**		
1.	बी. टैक. मैकेनिकल इंजी.	120	120
2.	बी. टैक. इलैक्ट्रीकल इंजी.	60	60
3.	बी. टैक. कम्प्यूटर इंजी.	60	60
4.	बी. टैक. इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी	60	60
5.	बी. टैक. इन्स्ट्रूमैन्टेशन एवं कन्ट्रोल इंजी.	60	60
6.	बी. टैक. इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजी.	60	60
	उप कुल जोड़	**420**	**420**
7.	लीट के अन्तर्गत दाखिले की प्रवेश क्षमता	द्वितीय वर्ष में कुल प्रवेश क्षमता की 10/सीटें (42)	द्वितीय वर्ष में कुल प्रवेश क्षमता की 20/सीटें (84)
	स्नातक स्तर तक के कोर्सों की कुल प्रवेश क्षमता	**462**	**504**
(बी)	**स्नातकोत्तर स्तर के कोर्स**		
1.	एम. टैक. मैकेनिकल इंजी.	18	18
2.	एम. टैक. इलैक्ट्रीकल इंजी.	18	18
3.	एम. टैक. कम्प्यूटर इंजी.	18	18
4.	एम. टैक. इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी	18	18
5.	एम. टैक. कम्प्यूटर इंजी (नैटवर्किंग)	18	18
6.	एम. टैक. इलैक्ट्रीकल इंजी. (इलैक्ट्रोनिक्स इंजी. में स्पैशीलाईजेशन)	18	18

1	2	3	4
7.	बी.एल.एस.आई. टैक्नोलोजी में एम. टैक.	--	18
8.	एम. टैक. इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजी.	--	18
	कुल एम. टैक. कोर्स	**108**	**144**
(सी)	**अन्य स्नातकोत्तर कोर्स**		
1.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम. सी.ए.)	30	30
2.	एम.बी.ए.	60	60
3.	भौतिकी में स्नातकोत्तर	--	30
4.	गणित में स्नातकोत्तर	--	30
	कुल	**90**	**150**
(डी)	**पी.एच.डी. प्रोग्राम**		वर्ष 2010-11से पी.एच.डी. प्रोग्राम में इलैक्ट्रीकल/ इलैक्ट्रोनिक्स इंजी./ मैकेनिकल इंजी./कम्प्यूटर इंजी./भौतिकी और गणित में निम्न प्रकार से दाखिला किया गया :-- 2010-11 : 40 2011-12 : 60

1. तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियों तथा संपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों का परिचय

(i) उपयुक्त रूप में शिक्षित तकनीकी व व्यावसायिक व्यक्ति, मानव संसाधनों का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संभाग है जोकि किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को निर्देशित करते है। तकनीकी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के अनुरूप राज्य में तकनीकी शिक्षा की योजना बनाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

(ii) विभाग डिप्लोमा संस्थानों (बहुतकनीकी) के लिए आवश्यकतानुसार कोर्स/कार्यक्रम तैयार करता है और पर्याप्त मानव संसाधन और पाठ्यक्रम के वितरण के लिए ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करता है। विभाग छात्रों, पाठ्यक्रमों और संस्थानों के लिए सटीक मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रणाली सुनिश्चित करता है। विभाग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, मानव संसाधन मन्त्रालय, अखिल भारतीय प्रबन्धन सभा, वास्तुकला परिषद्, विश्वविद्यालयों, उद्योग तथा अन्य रोजगार संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है ताकि तकनीकी प्रबंधकों/विज्ञानिकों/अभियंताओं/पर्यवेक्षकों अन्य पेशेवरों को स्नातकोत्तर,

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

पूर्वस्नातक एवं डिप्लोमा संस्थानों के माध्यम से अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, संगणक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, औषध विज्ञान, वास्तुकला, होटल प्रबंधन तथा अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प के क्षेत्र में गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसूचित जातियों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों, ग्रामीण आबादी और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। तकनीकी शिक्षा विभाग छात्रों को उचित एवं लाभप्रद/अर्जक नौकरी दिलाने के अलावा जीवन वृत्ति सलाह सेवा भी उपलब्ध करवाता है।

(iii) वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय प्रदेश में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाएं, जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त थे एवं एकमात्र इंजीनियरिंग कालेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरुक्षेत्र में था, जिसमें 1341 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। शैक्षणिक सत्र 2010-11 में संस्थाओं की संख्या बढ़कर 596 तथा छात्र प्रवेश क्षमता 1,24,705 थी। शैक्षणिक सत्र 2011-12 में संस्थाओं की संख्या और भी बढ़कर 640 तथा छात्र प्रवेश क्षमता 142226 हो गई है।

(iv) विभाग तीन विश्वविद्यालयों गुरू जम्भेश्वर साईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, हिसार (1995), दीनबन्धु छोटूराम साईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, मुरथल (2006) तथा यंग मैनज़ करिस्चियन एसोसिएशन (वाई०एम०सी०ए०) साईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (2009) का भी प्रशासन चलाता है।

2. वर्ष 2011-12 में विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियां

(i) तकनीकी शिक्षा विभाग ने फैशन एवं डिजाईन, फिल्म एवं टेलीविज़न तथा ललित कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली प्रदान करने के लिए एक ही परिसर में स्टेट आफ आर्ट्स संस्थानों को स्थापित किया। शैक्षणिक सत्र 2011-12 में तीन संस्थान 99 दाखिलों के साथ कार्यशील हो गए।

(ii) भारत सरकार द्वारा ग्राम सुनारिया, जिला रोहतक में आई०आई०एम०, रोहतक की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2010-11 से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के प्रांगण में अतिथि कक्षाएं 50 दाखिलों के साथ प्रारम्भ की जा चुकी है और वर्ष 2011-12 में 124 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

(iii) राजकीय बहुतकनीकी, मानेसर, जिला गुड़गांव में 'हरियाणा इग्नू सामुदायिक कालेज' एवं 'शिक्षक योग्यता एडवांसमैन्ट संस्थान' ने 'हरियाणा इग्नू सामुदायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति' के प्रबंधन के तहत सितम्बर, 2011 में अपना कार्य शुरू किया।

(iv) वर्ष 2009-10 में दो राजकीय बहुतकनीकियों क्रमशः चीका (जिला कैथल) तथा लिसाना (जिला रिवाड़ी) की स्थापना की गई।

(v) वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न राजकीय बहुतकनीकियों में 10 महिला छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2010-11 में

राजकीय बहुतकनीकी नाथूसरी चौपटा में अनुसूचित जाति महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्ष 2011-12 में राजकीय महिला बहुतकनीकी, अम्बाला शहर, राजकीय बहुतकनीकी, सिरसा, राजकीय बहुतकनीकी, हिसार, राजकीय बहुतकनीकी, मंडी आदमपुर, राजकीय बहुतकनीकी, झज्जर, राजकीय बहुतकनीकी, सोनीपत, राजकीय बहुतकनीकी अम्बाला शहर में अनुसूचित जाति महिला छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजकीय बहुतकनीकी लोहारू तथा राजकीय बहुतकनीकी उटावड़ में अनुसूचित जाति महिला छात्रावासों का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

3. **विभाग द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं और अवधारणाओं का प्रक्षेपण**

(i) वर्ष 2012-13 में पांच बहुतकनीकियों, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा सिंचाई एवं पावर इंजी. संस्थान, हथनीकुण्ड (यमुनानगर), राजकीय बहुतकनीकी, उमरी (कुरुक्षेत्र), राजकीय बहुतकनीकी, जाट्टल (पानीपत), राजकीय बहुतकनीकी, ढांगर (फतेहाबाद) और राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुर (पंचकूला) का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

(ii) सैन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी (सी.आई.पी.ई.टी.) मुरथल (जिला सोनीपत) में अपने नए 10 एकड़ परिसर में जुलाई, 2012 से अपना कार्यान्वयन आरम्भ करेगा।

(iii) ग्राम किलोड़, जिला सोनीपत में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना के लिए पी.पी.पी. मोड में प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। वर्ष 2012-13 तक निजी भागीदार का चयन होना सम्भावित है।

(iv) उद्योगों द्वारा कुशल कर्मियों की रोजगार की सम्भावनाओं में सुधार करने के लिए और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है।

4. **वित्तीय परिव्यय**

(i) 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के वित्तीय परिव्यय में विभाग के लिए राशि रुपये 67,300 लाख, जिसमें 414 लाख रुपये बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना सहित स्वीकृत किए गए हैं तथा वार्षिक योजना 2011-12 के लिए रुपये 7,100 लाख स्वीकृत किए गए। इसे अब संशोधित प्लान सिलिंग वर्ष 2011-12 के लिए 35,100 लाख रुपये अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें 7,500 लाख रुपये एन.सी.आर.पी.बी., रुपये 7,000 लाख ए.सी.ए. तथा 2,200 लाख एस.सी.एस.पी. स्कीम के सम्मलित हैं।

(ii) 12वीं ड्राफ्ट पंचवर्षीय योजना (2012-17) के वित्तीय परिव्यय के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा के लिए 1,50,000लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा ड्राफ्ट वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 20,000 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिसमें एस.सी.एस.पी. के लिए 2,400 लाख, एन.सी.आर.पी.बी. के लिए 2,000 लाख तथा सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम (सी.एस.एस.) के लिए 3,800 लाख रुपये 75 : 25 केन्द्र एवं राज्य सरकार के शेयर शामिल हैं।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वाई०एम०सी०ए०, जोकि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीच्यूट था और जिसमें 300 परसैंट से ज्यादा प्लेसमैंट होती थी उसमें रैगुलर बी.सी. न लगने से यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट्स की प्लेसमैंट में क्या फर्क पड़ा है। दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी बनने के बाद रैगुलर टीचर और अन्य स्टॉफ की कितनी अप्वायंटमैंट हुई है, कितने पद भरे गये हैं और कितने खाली हैं ?

Mr. Speaker : Yes, Hon'ble Minister please.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो सवाल किया है और उसके माध्यम से जानना चाहा है कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद बी. सी. के न लगने से स्टूडैंट्स की ऐडमीशन या पढ़ाई पर असर पड़ा है, मैं बताना चाहूंगा कि 2009 से पहले जब कालेज था उस समय स्वीकृत पदों की संख्या 94 थी और वर्ष 2009 में यूनिवर्सिटी बनने के बाद उन पदों की संख्या 109 हो गई है, इस प्रकार 15 भर्तियां उसके बाद हुई हैं। उनमें से कुछ के इंटरव्यू वगैरह अभी हुऐ हैं, उन पदों को भी भरा जा रहा है। बी.सी. के न होने से ऐडमीशंज पर पड़े फर्क की जो बात ये कह रहे हैं उस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो स्नातक स्तर का कोर्स है उसकी टोटल ऐडमीशंज इससे पूर्व 462 थीं जो कि 2009 के बाद 504 हो गई है उनमें से इस वक्त भरी हुई सीट्स 494 हैं, सिर्फ 10 सीटें खाली हैं । इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट में पहले 108 स्टूडैंट्स थे, अब 144 हो गए हैं। सारी सीटें भरी हैं, अन्य जो कोर्सिज थे उनमें 90 स्टूडैंट्स थे, नये कोर्सिज शुरू होने के बाद यह 150 तक हो गए हैं। (विघ्न)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्लेसमैंट की बात पूछ रहा हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, he has asked question regarding placement.

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां पर मंत्री जी ने बताई हैं थे तो रिप्लाई में ही दी हुई हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : जहां तक प्लेसमैंट के फर्क की बात पूछी गई है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद ऐडमीशंज में काफी इजाफा हुआ है और स्टूडैंट्स की संख्या बढ़कर 660 से 858 हो गई है।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि स्टूडैंट्स में या सीट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यह तो सरकार की मर्जी पर निर्भर है कि कितनी भी सीटें बढ़ा दे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Give a separate question in this regard.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्लेसमैंट पूरी है। जो नयी इंडस्ट्रीज आ रही हैं वे खुद ही आकर स्टूडैंट्स को ले जाती हैं। तकरीबन 100 परसैंट प्लेसमैंट हो रही है। प्लेसमैंट में कहीं कोई कमी नहीं आई है।

Total Staff of M.D.A.

***1105. Shri Naseem Ahmed :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the post-wise number of officers and officials working in the Mewat Development Agency ?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : महोदय, स्टेटमैन्ट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैन्ट

मेवात विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का पदवार विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए	रिक्त
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1	1	-
2.	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1	-	1
3.	ओ.एस.डी. मेवात विकास एजैंसी	1	-	1
4.	प्रोजैक्ट इक्नोमिस्ट	1	-	1
5.	लेखा अधिकारी	1	1	-
6.	प्रोजैक्ट अधिकारी	1	1	-
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-
8.	फील्ड को-आरडीनेटर	1	1	-
9.	उप अधीक्षक	1	1	-
10.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	1	-
11.	निजी सहायक	1	-	1
12.	सांख्यिकीय सहायक	2	1	1
13.	लेखाकार	2	2	-
14.	जूनियर स्केल-स्टैनोग्राफर	1	1	-
15.	स्टैनो-टाईपिस्ट	2	2	-
16.	लिपिक	4	4	-
17.	चालक	3	3	-
18.	सेवादार	5	5	-
19.	चौकीदार	1	1	-
	कुल	**31**	**26**	**05**

मेवात विकास अभिकरण को सशक्त बनाए रखने के लिए कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	प्रोजैक्ट प्रबन्धक (एन एम डी एफ सी)	1
2.	सुपरवाईजर (कृषि एवं बागवानी)	1
	कुल	**2**

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, एम.डी.ए. का सालाना बजट 20 करोड़ रुपये है इसके अलावा इसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट से भी बजट आता है। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले वर्षों 2009-10 और 2010-11 में कितना पैसा इस पर खर्च किया गया है और 20 करोड़ रुपये की राशि में से कितना पैसा बचा हुआ है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे बोर्ड के गठन का जो असल उद्देश्य था वह मेवात क्षेत्र के विकास के बारे में था जोकि काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये आपको यह बात नहीं कहने देंगे क्योंकि इनका मानना है कि अब मेवात क्षेत्र में काफी डिवैल्पमैंट हो गई है और इतनी डिवैल्पमैंट के बाद आप उसे पिछड़ा क्षेत्र नहीं कह सकते हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सर, मेरे कहने का उद्देश्य यही था कि आर्थिक दृष्टि से मेवात क्षेत्र पिछड़ा ही रहा है। उस दृष्टि से ही विशेषतौर पर बोर्ड का गठन किया गया था। सरकार द्वारा बोर्ड के अधीन विभिन्न स्कीमें मेवात क्षेत्र के लिए बिलाई गईं। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेवात क्षेत्र अभी पिछड़ा नहीं है, अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो आज भी मेवात पिछड़ा क्षेत्र ही है। पिछड़ा क्षेत्र न कहने से तो जिन स्कीमों का पैसा मिलता है वह पैसा नहीं मिलेगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह कहें कि सरकार की कमी की वजह से मेवात क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यह न कहें कि मेवात क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है और मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब भी नहीं आया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की राशि खर्च करने की बात कही गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पहले 690 लाख रुपये के करीब यह बजट एलोकेट हुआ था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 1800 लाख रुपये हो गया है। कितना बजट बढ़ा है इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने साल दर साल वर्ष 2009, 2010 और 2011 के बजट के बारे में सवाल पूछा है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितना बजट एलोकेट हुआ है और जितना खर्च हुआ है उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2008-2009 में 1071.50 लाख रुपये खर्च किये गये, वर्ष 2009-2010 में 1729.63 लाख रुपये खर्च किये गये, वर्ष 2010-2011 में 1135 लाख रुपये खर्च किये गये और वर्ष 2011-2012 दिसम्बर तक 619 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं जबकि कुल 20 करोड़ रुपये का बजट है।

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ठीक है मंत्री जी कह रहे हैं कि मेवात पिछड़ा एरिया है। मैं स्वीकार करता हूं लेकिन जैसा कि भाई नसीम अहमद जी ने सवाल पूछा है कि सरकार ने कितना पैसा इन तीन सालों में खर्च किया था और मेवात एरिया के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? इसके बारे में भी कृपा मंत्री जी बतायें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि किन-किन स्कीमों में कितना-कितना पैसा खर्च किया है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं पहले उनको जवाब तो देने दीजिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन स्कीमों के साथ-साथ दूसरा जो भारत सरकार द्वारा स्पोन्सर्ड स्कीमों का पैसा आता है वह भी खर्च किया गया है। वह बजट भी लगभग 14 करोड़ रुपये से ज्यादा है जो इन स्कीमों पर खर्च किया गया है । इन्होंने कहा है कि किन-किन स्कीमों पर पैसा खर्च किया गया है।

Mr. Speaker : He is satisfied with your answer.

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि किस-किस मद में कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है जिसके कारण मेवात का पिछड़ापन दूर किया गया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मेवात क्षेत्र में सात मेवात मॉडल स्कूल खोले गये हैं। नगीना में गर्ल्ज हॉस्टल बनाया गया है, कस्तूरबा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम नूंह में बनाया गया है और तावडू, नूंह और फिरोजपुर झिरका में बार्डर रूम बनाये गये हैं। मेवात में डिवैल्पमैंट बोर्ड के माध्यम से जो हैल्थ सर्विसिज दी गई हैं उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। बोर्ड के माध्यम से 30 हैल्थ कैम्प, 30 फ्री आई कैम्प, 9 मोबाइल वैन फार एमरजैंसी हैल्थ प्रोग्राम्ज के लिए लगाए गए हैं। 7151 इंस्टीच्यूशंज फार डिलीवरीज के लिए, आउट सोर्सिज दो पी.एच.सीज, उटावड़ और नांगल जाट में और स्टॉफ क्वाटर मांडी खेड़ा और नूंह में बनाए गए हैं। ऐग्रीकल्चर क्षेत्र में डैमोनस्ट्रेशन वैजीटेबल प्लांट 1670 हैक्टेयर में, स्पाइस डिवैल्पमैंट प्लांट 65 एकड़ में लगाए गए हैं। 3000 लीटर कैपेसिटी के 50 प्लास्टिक टैंक इरीगेशन सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, *******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. बैठे बैठे आपको बोलने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं उसके बाद आपको बोलने का मौका देने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि 106 यूनिट अंडरग्राउंड पाइप लाइन फार फार्मर्स, टर्मिनल कंटयूर 1000 एकड़ में, वाटर शैड मैनेजमैंट 7225 हैक्टेयर में, कंस्ट्रक्शन आफ बंध एट विलेज पटखोरी और झिरका में, कंस्ट्रक्शन आफ प्लग विलेज बोंद में लगाए गए हैं। (विघ्न) मैं उन सब कामों के बारे में बता रहा हूं जो जो काम हमने किए हैं।

मेवात क्षेत्र में विकास कार्यों पर अल्प अवधि चर्चा

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों साथी एक जगह मिलकर बात कर लें क्योंकि एक कहता है कि प्रगति नहीं हुई और दूसरा कहता है कि मेवात बैकवर्ड नहीं रहा। मेवात बैकवर्ड तो तभी नहीं रहा होगा अगर वहां डिवैल्पमैंट हो गए होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मेवात का पिछड़ापन और उसको आगे बढ़ाने का विषय बड़ी चिन्ता का विषय है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सम्मानित सदस्य भी इसको लेकर काफी चिंतित है। मेवात में शिक्षा का स्तर बढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर का हर कार्यक्रम हमने मेवात से लांच किया है। विशेष तौर से दस्तके तालीम एक कार्यक्रम है जोकि हमने मेवात से ही शुरू किया है। हमने स्कूल मैनेजमैंट और NGOs के माध्यम से हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी और करीबन 7500 बच्चों में से 5500 बच्चे हम स्कूलों में लेकर आए और हमने ड्राप आउट को कंट्रोल किया। आज राइट टू एजूकेशन ऐक्ट जो आया है उसका उद्देश्य यह है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि उनको भी यह नजर आए कि हम माडल स्कूल, आई.टी.आई़ज़., कस्तूरबा गांधी स्कूल, साइंस स्कूल, मैथ्स स्कूल और साइंस लैब का पूरी तरह से प्रोवीजन कर रहे हैं। मेवात में अलग से स्कूल एजूकेशन के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को कहना चाहूंगी कि वे एक बार हमारे साथ आकर जरूर मीटिंग करें और जानने का प्रयास करें कि शिक्षा के क्षेत्र में हम मेवात में क्या करना चाह रहे हैं और हम इनके सहयोग की भी अपील करते हैं ताकि मेवात जो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको हम शैक्षणिक दृष्टि से भी आगे ला सकें।

श्री नसीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, *********

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी मेरी परमीशन के बिना बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सिर्फ मेवात डिवैल्पमैंट एजैंसी के कार्यों के बारे में जवाब दिया है। जहां तक मेवात के विकास की बात है तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात हो, इन्होंने हर क्षेत्र में कई हजारों करोड़ रुपये का विकास किया है जो अपने आप में एक उदाहरण है। इस चीज को कोई नकारता है तो इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनाकर यह देखने के लिए मेवात का दौरा ही रख दिया जाए कि मेवात में क्या विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : The Government may supply the details of the development works made in the fields of Education, Health, Water Supply, Medical Colleges, Electricity, Roads in Mewat District by next sitting. You may place all these facts on the Table of the House.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I will place all these facts with record on the Table of the House. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इसके बारे में मेरा एक सुझाव है। Government is ready and willing and let the facts come out. Let a short duration discussion on the developmental works undertaken in Mewat be held. Let a short duration discussion be held on the next working day on the developmental works in Mewat. We are ready.

Mr. Speaker : Are you agreed to have a short duration discussion on the development works undertaken in Mewat ?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : Alright.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मेवात में सरकार ने कोई काम नहीं किया (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस बात से सहमत हैं कि सदन में मेवात क्षेत्र के बारे में शॉर्ट डयूरेशन डिस्कशन हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक-दो मिनट का समय दे दिया जाये मैं मेवात की सारी बात बता दूंगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी तथ्यों को सदन में नहीं आने देंगे। इनको डिस्कशन कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक-दो मिनट का समय दे दिया जाये मैं मेवात का पूरा नक्शा खींच दूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, फैसला हो गया। इस पर 7-3-2012 को शॉर्ट डयूरेशन डिस्कशन अलाऊ कर दी है, आप नक्शा उस समय खींचना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर डिस्कशन अलाऊ करने पर भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही तो यह कहने मात्र से कि आज भी मेवात क्षेत्र की डिवल्पमैंट नहीं हुई, यह गलत बात है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No further discussion. On 7-3-2012 immediately after the question hour we will have a short duration discussion on this matter.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

Re-Construction of Bridge

***1068. Shri Phool Singh Kheri :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the bridge on Cheeka to Patiala road over Ghaggar river was constructed in the year 1960 and the said bridge is in a dilapidated condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re-construct the aforesaid bridge alongwith the details thereof ?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, bridge on Ghaggar river crossing Cheeka Patiala road (SH-11) was constructed during 1960-61. This bridge is a high level bridge of 4 span of 18.75 Mtr. each. The width of carriage way of bridge is 7.50 Mtr. This bridge was repaired during 2008 with an expenditure of Rs. 68.86 lacs and is in a good condition. There is no proposal under consideration to reconstruct this bridge in view thereof.

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि घग्गर नदी पर 1960-61 में चीका-पटियाला रोड़ पर पुल बनाया गया था। इसके बाद इस पुल की मुरम्मत 2008 में 68.96 लाख रुपये की लाग से करवाई गई

[श्री फूल सिंह खेड़ी]
और अब यह अच्छी हालत में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो महीने पहले इस पुल में दरार आ गई थी। क्या दरार आने पर उस पुल की रिपेयर करने वाले ठेकेदार या विभागीय अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? क्या चार साल की डयूरेशन एक पुल की होती है क्योंकि 2008 में इसकी रिपेयर की गई थी और उसके बाद आज से लगभग दो महीने पहले इसमें दरार आ गई थी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस पुल में कोई दरार नहीं आई। कल ही इस पुल की फोटोग्राफी करवाई गई थी और मैं माननीय साथी को भी ये फोटो भिजवा देता हूं। ये स्वयं ही देख लें कि इस पुल में कोई दरार है या नहीं है।

श्री फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, फोटो से क्या पता लगेगा। अब वह ठीक करवा दिया होगा। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय साथी को यह भी मंजूर नहीं है तो इस बारे में सदन की एक कमेटी बना दी जाये और वह कमेटी चैक कर ले कि इस पुल में कहीं कोई दरार है या नहीं है। The bridge is absolutely safe. There is no difficulty with the bridge. We have repaired the bridge. अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत हो गई है, ये ऐसे ही सदन को गुमराह करते रहते हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Next question please.

Construction of Parikarma Road

***1072. Shri Jagdish Nayar :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Parikrama Road via village Garhi-Risondh etc. in District Palwal, if so; the details thereof ?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, this road, which already exists, is likely to be repaired by 31-12-2012.

श्री जगदीश नैय्यर : स्पीकर सर, मैं इस जवाब में संतुष्ट नहीं हूं। इससे पहले सैशन में भी मैंने यह कहा था कि यह रोड बना दिया जाये। अगर मंत्री जी को नहीं पता है तो कृपया करके ये बृज परिक्रमा के गांवों के नाम नोट कर लें। हम बृज वासी हैं और लाखों लोग यू०पी० से हमारे क्षेत्र से होकर निकलते हैं। यह रोड होडल से गढ़ी डाडका, बोराका, सोंद, बेचारी, ढकोरा, मरौली, खामी, लिखी, हसनपुर से होता हुआ यू०पी० में जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के लाखों श्रद्धालु यहां से गुजरते हैं। वहां पर यह रोड टूटा पड़ा है, कच्चे रास्ते हैं। बरसात के दिनों में यह परिक्रमा चलती है और बरसात में लोगों का आना-जाना बहुत ज्यादा दूभर हो जाता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस रोड पर कितना पैसा खर्च किया गया है और यह रोड कब तक चालू कर दिया जायेगा ? जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि यह रोड रिपेयर कर दिया गया है मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर कोई रिपेयर नहीं हुई है। आप मंत्री जी को वहां पर बृज परिक्रमा में जाने के लिए कहें मैं इनको वहां पर घुमाकर लाऊंगा। ये वहां की हालत भी देख लेंगे और इसके साथ-साथ इनको पुण्य की भी प्राप्ति हो जायेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरे जवाब को पढ़ा नहीं है या जब मैं पढ़ रहा था तो इन्होंने ठीक से सुना नहीं है। मैंने यहां यह कहा है कि यह रोड 31-12-2012 तक रिपेयर हो जायेगी। ये कह रहे हैं कि रिपेयर हो चुकी है जबकि मैं यह कह रहा हूं कि रिपेयर नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नैय्यर : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नैय्यर जी, आप कृपया बैठिए आपके सवाल का जवाब आ चुका है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1130

(इस समय माननीय सदस्य श्री नरेश सेलवाल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Use of Urea in Ply-wood Industry

***808. Dr. Bishan Lal Saini** : Will the Industries Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that urea fertilizer is being used in the Industries of plywood functioning in District Yamunanagar; and

(b) if so, the quantity of urea used therein togetherwith the source from where the abovesaid urea fertilizer is being obtained by these industries ?

Industries and Commerce Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, sir, except in one case detected during inspections by a District Level Committee constituted for the purpose.

(b) 121 bags of Agricultural Grade Urea was found in one unit *i.e.* M/s. Nagpal plywood, V.P.O. Damla, Jagadhri and FIR has been lodged against the said unit under Essential Commodities Act, 1955 on 9-12-2011. The source of confiscated urea could not be ascertained by the raiding committee/police party.

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर यूरिया की कितनी कमी रही है। यूरिया लेने के लिए लोगों की बड़ी लम्बी-लम्बी लाईनें लगी हैं जबकि इन प्लाई-वुड की इण्डस्ट्रीज के अन्दर यूरिया के ट्रक के ट्रक जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई ऐसी एजेंसी नियुक्त की है जो इनकी जांच कर सके और दूसरी बात यह कि क्या इस एजेंसी ने कोई इस प्रकार की अनियमितताओं के सैम्पल लिये हैं अगर लिये हैं तो कितनी संख्या में सैम्पल लिये गये हैं ?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, शायद यह बात मेरे काबिल साथी को मालूम नहीं है कि जो प्लाई वुड इण्डस्ट्री है इसकी सैम्पलिंग इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट नहीं करता। As far as sampling of plywood industry is concerned, why should we continue to harass the industrialists until and unless we get a complaint. We got a complaint. We checked all the units. On checking all the units, we found one unit using Urea. We registered an FIR. If my learned friend wants that there should be an Inspector Raj over all the units than we are not ready to do. We continue to check. If somebody will misuse urea or any other fertilizer in Plywood Industry, we will take action.

Mr. Speaker : Thank you.

Repair of Road in Kalanwali Mandi

***1119. Shri Charanjit Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the road from Railway crossing to Deshu Malkana crossing in Kalanwali Mandi; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, no such road exists.

श्री चरणजीत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनका एस०डी०ओ०, जे०ई० और एक्स०ई०एन० ये रोड देखकर आये हैं और वे यह मान रहे हैं कि यह हमारी रोड है लेकिन मंत्री जी यह कह रहे हैं कि यहां रोड ही नहीं है। यह रोड कालांवाली फाटक से लेकर देशु मलकाना तक है। क्या मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आने के बाद मैंने अपने एक्स०ई०एन० को मौके पर भेजा था वे माननीय सदस्य जी से मिलकर भी आये हैं और इन्होंने उसको कहा कि यह प्रश्न उनके द्वारा गलती से दिया गया है इसके अलावा उनके मन में कोई और सड़क थी। इस पर मैंने कहा कि माननीय सदस्य उस सड़क के बारे में लिखकर दे दें जो इनके मन में है उसके बारे में फिर जवाब दे देंगे या फिर लिखकर भिजवा देंगे।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, एक सड़क है जो महम से कलानौर, कलानौर से बेरी और बेरी से गुड़गांव जाती है। इस सड़क का जो महम से कलानौर तक का पोर्शन है वह बहुत ज्यादा खराब है। क्या इस पोर्शन को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोई प्रपोज़ल सरकार के विचाराधीन है ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, it is a suggestion. I noted it.

Mr. Speaker : Alright.

तारांकित प्रश्न संख्या 819

(इस समय माननीय सदस्य राव बहादुर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Budget Provision for Independence and Republic Days

***831. Shri Aftab Ahmed :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any separate provision in the Budget to celebrate Independence Day (15th August) and Republic Day (26th January) at district Head Quarters and Sub-division levels; and

(b) if so, the amount earmarked for this august purpose ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) :

(a) Yes sir, there is a financial provision for the district-wise allocation in the budget.

(b) Sir, an amount of ₹ 9,40,000/- (Rupees Nine Lacs Forty Thousand) is earmarked for this august purpose in the Financial Year 2011-2012.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में 21 जिले हैं और सब-डिविजन लैवल पर भी राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) मनाये जाते हैं। इस अगस्त अवसरों के लिए जो राशि आबंटित की गई है यह पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें और वृद्धि की जाये। It should be celebrated in a befitting manner and it should be increased.

Mr. Speaker : Suggestion will be noted.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, 9,40,000/- रुपये की राशि बहुत कम है। इतने रुपये में तो एक या दो जिलों का ही काम चल पायेगा। It means the money is being siphoned from other departments. मेरा सुझाव है कि इस राशि को फिक्स कर दिया जाये ताकि जिला, उप-मण्डल और तहसील स्तर पर उपायुक्त और तहसीलदारों को इसमें कोई दिक्कत न हो।

Mr. Speaker : Suggestion may be noted please.

Number of Posts Lying Vacant

***823. Shri Anil Vij :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state —

(a) the town wise, category-wise number of posts lying vacant in the Municipal Corporations. Municipal Councils and Municipal Committees of the State and since when these posts are likely vacant;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill-up these posts; and

(c) if so, the time by which these posts are likely to be filled-up ?

शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री (श्री गोपाल काण्डा) :

(क) श्रीमान जी, विवरणिका सदन के पटल पर रखी है।

(ख) व (ग) यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

[श्री गोपाल कांडा]

विवरणिका

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	लेखाकार	32
2.	लेखा लिपिक	29
3.	लेखा अधिकारी	3
4.	सहायक	3
5.	सहायक नगर योजनाकर	8
6.	भवन निरीक्षक	7
7.	खजांची	4
8.	मुख्य सफाई निरीक्षक	1
9.	लिपिक	185
10.	विद्युतकार	2
11.	कार्यकारी अभियन्ता	8
12.	कार्यकारी अधिकारी	6
13.	दमकल चालक	32
14.	अग्निशाम	32
15.	गैगमैन/बेलदार	11
16.	मुख्य लिपिक	5
17.	मुख्य प्रारूपकार	7
18.	जीप कार चालक	4
19.	कनिष्ठ अभियन्ता	34
20.	मुख्य अग्निशामक	6
21.	लाईब्रेरियन	2
22.	लाईसेंस निरीक्षक	1
23.	विद्युत निरीक्षक	4
24.	माली कम चौकीदार/हैड माली	50
25.	मैसन	3

1	2	3
26.	पालिका अभियन्ता	32
27.	पटवारी	3
28.	सेवादार	62
29.	पाउंड कीपर	2
30.	सफाई दरोगा	43
31.	सफाई कर्मचारी	891
32.	सफाई निरीक्षक	5
33.	सचिव	12
34.	अनुभाग अधिकारी	1
35.	दमकल केन्द्र अधिकारी	0
36.	आशुलिपिक	5
37.	उप-दमकल केन्द्र अधिकारी	19
38.	अधीक्षक	2
39.	कर निरीक्षक	6
40.	कर अधीक्षक	9
41.	ट्रैक्टर चालक	34
	योग	**1605**

[श्री गोपाल कांडा] **नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची**

क्रम सं०	नगर परिषद्/नगर पालिका का नाम	लिपिक	दमकल चालक	अग्नि शामक	उप दमकल केन्द्र अधिकारी	दमकल केन्द्र अधिकारी	मुख्य अग्नि शमक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नारायणगढ़	4	-	-	-	-	-
2.	थानेसर	8	2	-	1	-	-
3.	शाहबाद	4	-	-	-	-	-
4.	लाडवा	-	-	-	1	-	-
5.	पेहवा	1	-	-	1	-	-
6.	कैथल	12	-	-	-	-	-
7.	पुण्डरी	3	-	-	-	-	-
8.	चीका	3	-	-	-	-	-
9.	कलायत	3	-	-	-	-	-
10.	तरावड़ी	3	-	-	-	-	-
11.	नीलोखेड़ी	2	-	-	-	-	-
12.	घरौंडा	2	-	-	1	-	-
13.	असन्ध	2	-	-	-	-	-
14.	इन्द्री	-	-	-	-	-	-
15.	निसिंग	3	-	-	-	-	-
16.	महम	1	-	-	-	-	-
17.	कलानौर	2	-	-	-	-	-
18.	सांपला	1	-	-	-	-	-
19.	सोनीपत	8	-	-	-	-	-
20.	गोहाना	4	-	-	1	-	-
21.	गन्नौर	3	-	-	1	-	-
22.	खरखौदा	1	-	-	-	-	-
23.	बहादुरगढ़	5	4	-	1	-	-
24.	झज्जर	3	-	-	1	-	3
25.	बेरी	3	-	-	1	-	-
26.	सोहना	3	-	-	-	-	-
27.	हेली मण्डी	3	-	-	-	-	-
28.	पटौदी	3	-	-	-	-	-
29.	फरुखनगर	1	-	-	-	-	-
30.	पलवल	10	-	2	1	-	-
31.	होडल	2	3	1	1	-	-
32.	हथीन	2	-	-	-	-	-
33.	रेवाड़ी	7	-	1	-	-	-

जीप कार चालक	सेवादार	ट्रैक्टर ड्राईवर	पटवारी	सफाई दरोगा	लाईबेरियन	मुख्य लिपिक	भवन निरीक्षक
9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	4	-	3	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-
-	3	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-
-	6	6	1	4	-	-	-
-	2	2	1	1	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-
-	2	1	-	1	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-
-	3	2	-	1	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-
-	3	1	-	4	-	-	1

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची

क्रम सं०	नगर परिषद्/नगर पालिका का नाम	लिपिक	दमकल चालक	अग्नि शामक	उप दमकल अधिकारी	दमकल केन्द्र अधिकारी	मुख्य अग्नि शमक
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	बावल	2	-	-	-	-	-
35.	धारूहेड़ा	3	-	-	-	-	1
36.	नारनौल	9	1	4	1	-	-
37.	महेन्द्रगढ़	1	-	-	1	-	-
38.	कनीना	-	-	-	-	-	-
39.	अटेलीमण्डी	1	-	-	-	-	-
40.	नूँह	2	3	7	1	-	-
41.	फिरोजपुर झिरका	2	3	9	1	-	-
42.	तावडू	1	2	-	-	-	-
43.	पुन्हाना	2	-	4	-	-	-
44.	भिवानी	5	1	-	-	-	-
45.	चरखी दादरी	-	-	-	-	-	-
46.	सिवानी	-	-	-	-	-	1
47.	बवानी खेड़ा	-	-	-	-	-	1
48.	लोहारू	1	-	-	-	-	-
49.	हांसी	5	2	-	1	-	-
50.	नारनौंद	2	-	-	-	-	-
51.	उकलाना	-	-	-	-	-	-
52.	बरवाला	-	-	-	1	-	-
53.	फतेहाबाद	2	-	-	-	-	-
54.	टोहाना	-	1	-	-	-	-
55.	रतिया	1	-	-	1	-	-
56.	भूना	-	-	-	-	-	-
57.	सिरसा	7	4	-	-	-	-
58.	रानियां	-	-	-	-	-	-
59.	कलांवाली	2	-	-	-	-	-
60.	ऐलनाबाद	2	-	-	-	-	-
61.	मण्डी डबवाली	8	3	4	1	-	-
62.	जीन्द	3	3	-	-	-	-
63.	नरवाना	5	-	-	-	-	-
64.	सफीदों	4	-	-	-	-	-
65.	उचाना	-	-	-	-	-	-
66.	जुलाना	2	-	-	-	-	-
67.	समालखा	1	-	-	-	-	-
	योग	**185**	**32**	**32**	**19**	**0**	**6**

जीप कार	सेवादार	ट्रैक्टर ड्राईवर	पटवारी	सफाई दरोगा	लाईब्रेरियन	मुख्य लिपिक	भवन निरीक्षक
9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	3	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	1	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1
-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-
-	2	2	-	2	-	-	-
-	-	3	-	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4	**62**	**34**	**3**	**43**	**2**	**0**	**7**

[श्री गोपाल कांडा] **नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची**

क्रम सं०	नगर परिषद्/ नगर पालिका का नाम	माली कम चौकीदार/ हैड माली	लेखा/ लिपिक	सफाई कर्मचारी	सफाई निरीक्षक	आशु लिपिक	खजांची
1	2	17	18	19	20	21	22
1.	नारायणगढ़	1	-	11	-	-	-
2.	थानेसर	5	2	59	-	-	-
3.	शाहबाद	-	-	28	1	-	-
4.	लाडवा	-	1	15	-	-	-
5.	पेहवा	-	-	27	-	-	-
6.	कैथल	5	1	73	-	-	-
7.	पुण्डरी	1	-	15	-	-	-
8.	वीका	-	-	-	-	-	-
9.	कलायत	-	-	-	-	-	-
10.	तरावड़ी	-	-	2	-	-	-
11.	नीलोखेड़ी	1	-	-	-	-	-
12.	घरौंडा	-	1	14	1	-	-
13.	असन्ध	-	-	8	-	-	-
14.	इन्द्री	-	-	3	-	-	-
15.	निसिंग	1	1	-	-	-	-
16.	मेहम	-	1	4	-	-	-
17.	कलानौर	1	1	-	-	-	-
18.	सांपला	1	-	24	-	-	-
19.	सोनीपत	3	-	59	-	1	-
20.	गोहाना	-	-	20	-	-	1
21.	गन्नौर	1	-	11	-	-	-
22.	खरखौदा	-	-	-	-	-	-
23.	बहादुरगढ़	4	-	37	-	1	-
24.	झज्जर	1	4	23	-	-	-
25.	बेरी	1	-	-	-	-	-
26.	सोहना	1	-	10	-	-	-
27.	हेली मण्डी	1	1	8	-	-	-
28.	पटौदी	-	-	-	-	-	-
29.	फरुखनगर	1	-	-	-	-	-
30.	पलवल	1	-	26	-	-	-
31.	होडल	1	-	-	-	-	-
32.	हथीन	-	-	-	-	-	-
33.	रेवाड़ी	1	-	33	-	-	-

लाईसेंस निरीक्षक	विद्युतकार	सहायक	पाउंड कीपर	गैसन	मुख्य प्रारूपकार	विद्युत निरीक्षक	कर निरीक्षक	गैंगमैन/ बेलदार
23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1

[श्री गोपाल कांडा] **नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची**

क्रम सं०	नगर परिषद्/ नगर पालिका का नाम	माली कम चौकीदार/ हैड माली	लेखा/ लिपिक	सफाई कर्मचारी	सफाई निरीक्षक	आशु लिपिक	खजांची
1	2	17	18	19	20	21	22
34.	बावल	1	-	-	-	-	-
35.	धारूहेड़ा	-	-	-	-	-	-
36.	करनाल	-	-	-	-	-	-
37.	महेन्द्रगढ़	-	1	-	-	-	-
38.	कनीना	-	1	-	-	-	-
39.	अटेलीमण्डी	-	-	-	-	-	-
40.	नूंह	1	-	7	-	-	-
41.	फिरोजपुर झिरका	-	-	-	-	-	-
42.	तावडू	-	-	9	-	-	-
43.	पुण्हाना	1	-	-	-	-	-
44.	भिवानी	1	1	10	-	1	-
45.	चरखी दादरी	2	-	-	-	-	-
46.	सिवानी	1	-	-	-	-	-
47.	बवानी खेड़ा	-	-	-	-	-	-
48.	लोहारू	-	-	-	-	-	-
49.	हांसी	1	2	54	-	1	1
50.	नारनौंद	-	1	-	-	-	-
51.	उकलाना	-	-	-	-	-	-
52.	बरवाला	-	1	10	-	-	-
53.	फतेहाबाद	-	2	-	-	-	-
54.	टोहाना	-	2	20	-	-	-
55.	रतिया	-	1	-	-	-	-
56.	भूना	-	-	-	-	-	-
57.	सिरसा	-	2	53	1	1	1
58.	रानियां	-	-	4	-	-	-
59.	कलांवाली	-	-	-	-	-	-
60.	ऐलनाबाद	1	-	-	-	-	-
61.	मण्डी डबवाली	1	-	13	1	-	1
62.	जीन्द	6	2	58	-	-	-
63.	नरवाना	-	-	12	-	-	-
64.	सफीदों	-	1	-	-	-	-
65.	उचाना	1	-	-	-	-	-
66.	जुलाना	1	-	-	-	-	-
67.	समालखा	-	1	9	-	-	-
	योग	**50**	**29**	**891**	**5**	**5**	**4**

लाईसैंस निरीक्षक	विद्युतकार	सहायक	पाउंड कीपर	गैसन	मुख्य प्रारूपकार	विद्युत निरीक्षक	कर निरीक्षक	गैंगमैन/ बेलदार
23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**2**	**3**	**2**	**3**	**7**	**4**	**6**	**11**

[श्री गोपाल कांडा]

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची

क्रम सं०	नगर परिषद्/ नगर पालिका का नाम	लेखाकार	लेखा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	अधीक्षक
1	2	32	33	34	35
1.	नारायणगढ़	-	-	-	-
2.	थानेसर	1	-	-	-
3.	शाहबाद	-	-	-	-
4.	लाडवा	1	-	-	-
5.	पेहवा	-	-	-	-
6.	कैथल	1	1	-	-
7.	पुण्डरी	-	-	-	-
8.	चीका	-	-	-	-
9.	कलायत	-	-	-	-
10.	तरावड़ी	-	-	-	-
11.	नीलोखेड़ी	-	-	-	-
12.	घरौंडा	-	-	-	-
13.	असन्ध	-	-	-	-
14.	इन्द्री	-	-	-	-
15.	निसिंग	-	-	-	-
16.	महम	-	-	-	-
17.	कलानौर	-	-	-	-
18.	सांपला	-	-	-	-
19.	सोनीपत	1	-	-	-
20.	गोहाना	-	-	-	-
21.	गन्नौर	-	-	-	-
22.	खरखौदा	-	-	-	-
23.	बहादुरगढ़	-	-	-	-
24.	झज्जर	-	-	-	-
25.	बेरी	1	-	-	-
26.	सोहना	-	-	-	-
27.	हेली मण्डी	1	-	-	-
28.	पटौदी	1	-	-	-
29.	फरुखनगर	-	-	-	-
30.	पलवल	-	-	-	-
31.	होडल	-	-	-	-
32.	हथीन	-	-	-	-
33.	रेवाड़ी	-	-	-	-

कर अधीक्षक	मुख्य सफाई निरीक्षक	कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी अभियन्ता	सहायक योजनाकार	नगर सचिव	कनिष्ठ अभियन्ता	पालिका अभियन्ता
36	37	38	39	40	41	42	43
"	"	-	-	-	-	"	"
1	"	"	"	-	-	1	-
-	"	"	"	"	-	-	-
-	-	-	"	"	"	-	1
-	-	"	"	"	-	-	-
-	1	"	"	"	-	-	1
"	"	"	-	-	-	-	-
-	"	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	"	"
-	-	-	-	-	-	1	"
-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	"	"	"
-	-	-	"	"	"	-	-
-	"	"	"	-	-	-	-
"	-	-	-	-	-	"	1
-	-	-	-	-	"	"	1
-	-	-	"	"	"	-	-
-	-	-	1	1	"	-	-
-	-	-	"	"	"	-	-
-	-	-	-	"	-	-	-
-	-	"	"	"	"	-	-
"	"	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	"	"	"
-	-	"	"	"	-	-	1
"	"	"	"	-	-	-	1
"	"	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	"	"	-
-	-	-	-	"	"	-	1
1	-	1	1	"	"	-	-
-	-	"	"	-	-	"	-
-	"	-	-	-	"	"	-
"	-	-	-	"	-	-	-

[श्री गोपाल कांडा] **नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची**

क्रम सं०	नगर परिषद्/ नगर पालिका का नाम	लेखाकार	लेखा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	अधीक्षक
1	2	32	33	34	35
34.	बावल	-	-	-	-
35.	धारूहेड़ा	1	-	-	-
36.	करनाल	1	1	1	1
37.	महेन्द्रगढ़	-	-	-	-
38.	कनीना	1	-	-	-
39.	अटेलीमण्डी	-	-	-	-
40.	नूंह	1	-	-	-
41.	फिरोजपुर झिरका	1	-	-	-
42.	तावडू	1	-	-	-
43.	पुन्हाना	1	-	-	-
44.	भिवानी	1	-	-	-
45.	चरखी दादरी	1	-	-	-
46.	सिवानी	1	-	-	-
47.	बवानी खेड़ा	1	-	-	-
48.	लोहारू	1	-	-	-
49.	हांसी	-	-	-	-
50.	नारनौंद	-	-	-	-
51.	उकलाना	-	-	-	-
52.	बरवाला	-	-	-	-
53.	फतेहाबाद	1	-	-	-
54.	टोहाना	-	-	-	-
55.	रतिया	1	-	-	-
56.	भूना	-	-	-	-
57.	सिरसा	1	-	-	-
58.	रानियां	-	-	-	-
59.	कलांवाली	1	-	-	-
60.	ऐलनाबाद	-	-	-	-
61.	मण्डी डबवाली	-	-	-	-
62.	जीन्द	-	1	-	1
63.	नरवाना	-	-	-	-
64.	सफीदों	-	-	-	-
65.	उचाना	-	-	-	-
66.	जुलाना	-	-	-	-
67.	समालखा	-	-	-	-
	योग	**27**	**3**	**1**	**2**

कर अधीक्षक	मुख्य सफाई निरीक्षक	कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी अभियन्ता	सहायक योजनाकार	नगर सचिव	कनिष्ठ अभियन्ता	पालिका अभियन्ता
36	37	38	39	40	41	42	43
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	1	1	-	1	1
1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	1	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	2	1
1	-	1	1	1	-	3	-
-	-	1	-	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1
9	**2**	**6**	**8**	**3**	**10**	**36**	**35**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	सहायक जिला न्यायवादी	12
2.	लेखाकार	15
3.	लेखा लिपिक	10
4.	लेखा अधिकारी	2
5.	अतिरिक्त आयुक्त	2
6.	ए.डी.एफ.ओ.	2
7.	एन्टी मलेरिया कुली	4
8.	वास्तुकार	1
9.	वास्तुकार सहायक	1
10.	सहायक	13
11.	सहायक लेखाकार	3
12.	सहायक वास्तुकार	8
13.	सहायक अभियन्ता विद्युत	6
14.	सहायक मैनेजर आई.टी.	15
15.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	6
16.	सहायक नगर योजनाकार	13
17.	सहायक पशु चिकित्सक	6
18.	सहायक डिवीजनल फायर आफिसर	2
19.	सहायक सफाई निरीक्षक	22
20.	बिल वितरक	19
21.	नाविक	1
22.	नाव लिपिक	1
23.	कार्ट मैन	2
24.	मुख्य लेखा अधिकारी	1

1	2	3
25.	मुख्य अभियन्ता	1
26.	क्लीनर	2
27.	लिपिक	135
28.	आयुक्त	6
29.	डाटा एन्ट्री आप्रेटर	21
30.	उप-निगमायुक्त	3
31.	विद्युत सहायक	5
32.	विद्युतकार	4
33.	कार्यकारी अभियन्ता	7
34.	फैरा प्रिंटर	1
35.	दमकल चालक	46
36.	अग्निशामक	71
37.	फीटर	1
38.	बागबानी पर्यवेक्षक	1
39.	मुख्य लिपिक	3
40.	सहायक ट्यूबवैल आप्रेटर	407
41.	उद्यान निरीक्षक	2
42.	निरीक्षक कराधान लेखाकार	5
43.	संयुक्त आयुक्त	7
44.	कनिष्ठ आशुटंकक	6
45.	कनिष्ठ अभियन्ता	36
46.	कानूनगो	7
47.	की मैन	3
48.	खलासी	3
49.	लैब असिस्टैंट	1
50.	महिला वार्ड परिचारक	1

1	2	3
51.	भूमि/लाईसैंस सहायक	15
52.	मुख्य अग्निशामक	11
53.	विधि सहायक	15
54.	पुस्तकाध्यक्ष	2
55.	एम.एम.ओ.एच.	1
56.	माली-कम-चौकीदार	174
57.	मैनेजर आई.टी.	8
58.	मासकी	1
59.	चिकित्सा अधिकारी	4
60.	मैसन	5
61.	मीटर रीडर	6
62.	पालिका अभियन्ता	13
63.	नायब तहसीलदार	8
64.	नाला गैंगमैन	5
65.	कार्यालय अधीक्षक	12
66.	जन सम्पर्क अधिकारी	1
67.	पटवारी	11
68.	सेवादार	170
69.	निजी सहायक	9
70.	योजनाकार सहायक	2
71.	योजना सहायक	1
72.	पलम्बर फीटर	13
73.	क्रय अधिकारी	2
74.	रोड मार्ट	2
75.	रोड रोलर ड्राईवर	2
76.	सफाई दरोगा	27

1	2	3
77.	सफाई कर्मचारी	530
78.	सफाई निरीक्षक	7
79.	अनुभाग अधिकारी	2
80.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2
81.	वरिष्ठ सफाई निरीक्षक	4
82.	वरिष्ठ वेतनमान आशुटंकक	6
83.	सीवर मैन	68
84.	सीवरेज अभियन्ता ड्रा	3
85.	सीवरेज निरीक्षक	1
86.	समाज शिक्षा सेवक	1
87.	दमकल केन्द्र अधिकारी	5
88.	आशुटंकक	7
89.	स्टेनोग्राफर	1
90.	उप-दमकल केन्द्र अधिकारी	8
91.	अधीक्षक अभियन्ता	1
92.	स्विच आप्रेटर	1
93.	कर निरीक्षक	10
94.	कर अधीक्षक	6
95.	तहसीलदार	2
96.	टेलीफोन आप्रेटर	1
97.	ट्रेसर	1
98.	ट्यूबवैल आप्रेटर	67
99.	वाहन चालक	20
100.	पशु चिकित्सक	5
101.	वाटर मोटर मैकेनिक	1
102.	एक्सरे अटैन्डैंट	1
103.	क्षेत्रीय कर अधिकारी	7
	कुल योग	**2246**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगरनिगम का नाम	लिपिक	दमकल चालक	अग्नि शामक	उप-दमकल केन्द्र अधिकारी	दमकल केन्द्र अधिकारी	मुख्य अग्नि-शामक	ए.डी. एफ.ओ.	सेवादार	सफाई दरोगा	पटवारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पंचकुला	3	7	9	-	-	3	-	-	1	2
2.	अम्बाला	22	-	-	-	1	-	-	30	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	5	-	7	-	-	1	-	4	1	-
5.	गुड़गांव	15	22	45	1	2	4	-	49	1	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	फरीदाबाद	62	9	8	4	2	-	2	35	-	9
8.	यमुनानगर	14	2	2	1	-	1	-	34	18	-
9.	रोहतक	14	6	-	2	-	2	-	18	5	-
	कुल योग	**135**	**46**	**71**	**8**	**5**	**11**	**2**	**170**	**27**	**11**

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	मुख्य लिपिक	पुस्तकाध्यक्ष	माली-कम-चौकीदार	लेखा लिपिक	सफाई कर्मचारी	सफाई निरीक्षक	अधीक्षक अभियन्ता	योजना सहायक	वास्तुकार	तहसीलदार
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	पंचकुला	-	-	2	2	15	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	3	-	-	-	36	1	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	14	-	-	4	-	1	1	1
6.	हिसार	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	2	151	-	391	1	1	-	-	1
8.	यमुनानगर	-	-	5	-	32	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	2	-	56	1	-	-	-	-
	कुल योग	**3**	**2**	**174**	**10**	**530**	**7**	**1**	**1**	**1**	**2**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	मुख्य लेखा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	जिला न्यायवादी	कनिष्ठ आशुटंकक	क्रय अधिकारी	जन सम्पर्क अधिकारी	फीटर	कुली	सफाई पर्यवेक्षक	आयुक्त
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	गुड़गांव	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	फरीदाबाद	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग	**1**	-	-	**6**	**2**	**1**	**1**	-	-	**6**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	संयुक्त आयुक्त	उप-निगमा-युक्त	सहायक अभियन्ता विद्युत	सहायक वास्तुकार	नायब तहसील-दार	कानूनगो	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	चिकित्सा अधिकारी	सहायक सफाई निरीक्षक	पशु चिकित्सक	कर अधीक्षक
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	अम्बाला	1	1	1	1	1	1	-	1	4	1	-
3.	पानीपत	1	-	1	1	1	1	1	-	3	1	1
4.	करनाल	1	-	1	1	1	1	-	1	4	1	1
5.	गुड़गांव	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
6.	हिसार	1	1	1	1	1	1	-	1	4	1	-
7.	फरीदाबाद	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8.	यमुनानगर	1	1	1	1	1	1	-	1	4	1	2
9.	रोहतक	1	-	1	1	1	1	1	-	3	-	1
	कुल योग	**7**	**3**	**6**	**8**	**8**	**7**	**2**	**4**	**22**	**5**	**6**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	लेखाकार	लेखा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	अधीक्षक	मुख्य सफाई निरीक्षक	कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी अभियन्ता	सहायक नगर योजनाकार	सचिव	क्षेत्रीय कर अधिकारी
1	2	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
3.	पानीपत	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1
4.	करनाल	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5.	गुड़गांव	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6.	हिसार	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-
7.	फरीदाबाद	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2
8.	यमुनानगर	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2
9.	रोहतक	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	कुल योग	**15**	**2**	**2**	-	-	-	**7**	**13**	**-**	**7**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता	पालिका अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता बागवानी	सहायक अभियन्ता सिविल	सहायक अभियन्ता यांत्रिक	सहायक अभियन्ता बागवानी	स्थापना अधिकारी	समाज कल्याण अधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	सड़क निरीक्षक	निजी सचिव
1	2	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1.	पंचकुला	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	यमुनानगर	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	**36**	**13**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	सहायक पशु चिकित्सक	सहायक जिला न्यायवादी	कार्यालय अधीक्षक	विधि सहायक	निजी सहायक	स्टेनोग्राफर	मैनेजर आई.टी.	सहायक मैनेजर आई.टी.	कर निरीक्षक	भूमि/ लाईसैंस सहायक
1	2	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	1	1	2	2	1	1	1	2	-	2
3.	पानीपत	1	1	2	2	1	-	1	2	2	2
4.	करनाल	1	1	-	2	1	-	1	2	2	2
5.	गुड़गांव	-	2	4	3	3	-	2	3	3	3
6.	हिसार	1	1	2	2	1	-	1	2	-	2
7.	फरीदाबाद	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	यमुनानगर	1	1	-	2	1	-	1	2	1	2
9.	रोहतक	1	1	2	2	1	-	1	2	2	2
	कुल योग	**6**	**12**	**12**	**15**	**9**	**1**	**8**	**15**	**10**	**15**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	सहायक जन सम्पर्क	सहायक लेखाकार	डाटा एन्ट्री आप्रेटर	हैंड पम्प मिस्त्री	मलेरिया बेलदार	पार्क बेलदार	फार्मासिस्ट	रोड बेलदार	वर्क मिस्त्री	कर निरीक्षक	मुख्य अभियन्ता
1	2	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	यमुनानगर	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग	**6**	**3**	**21**	-	-	-	-	-	-	-	**1**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	एम.एम. ओ.एच.	वरिष्ठ सफाई निरीक्षक	समाज शिक्षा सेवक	उद्यान पर्यवेक्षक	मैसन	नाव लिपिक	नाविक	फीटर
1	2	86	87	88	89	90	91	92	93
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	1	-	1	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	2	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	2	-	-	5	-	-	-
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	1	-	1	1	-	1	-	-
	कुल योग	**1**	**4**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	-

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	एन्टी मलेरिया	कार्टमैन	प्लेग कुली	नाला गैंगमैन	मासकी	वरिष्ठ आशुलिपिक	आशुटंकण	अतिरिक्त आयुक्त	ट्रेसर
1	2	94	95	96	97	98	99	100	101	102
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	4	5	2	-
8.	यमुनानगर	4	2	-	5	1	1	1	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	कुल योग	**4**	**2**	-	**5**	**1**	**6**	**7**	**2**	-

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	सहायक पशु चिकित्सक	निरीक्षक जिला न्यायवादी	टेलीफोन अधीक्षक	मीटर सहायक	कम्प्यूटर सहायक	रेडियो	लैब आई.टी.	बहुउद्देशीय मैनेजर आई.टी.
1	2	103	104	1-5	106	107	108	109	110
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	13	5	1	6	-	-	1	-
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	13	5	1	6	-	-	1	-

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	महिला वार्ड परिचारक	वाहन चालक	विद्युत सहायक	बागवानी निरीक्षक	बिल वितरक	शिकायत परिचारक	रोड मार्ट	सहायक वैलडर	रोड रोलर चालक	खलासी	सहायक मजदूर
1	2	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	1	20	5	2	19	-	2	-	2	3	-
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	**1**	**20**	**5**	**2**	**19**	-	**2**	-	**2**	**3**	-

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	क्लीनर	वाहन निरीक्षक	ए.डी.एफ.ओ.	विद्युतकार	बढ़ई	प्लम्बर फीटर
1	2	122	123	124	125	126	127
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	2	-	2	4	-	18
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	2	-	2	4	-	18

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	प्लानर सहायक	वास्तुकार सहायक	सर्वेयर	ट्रेसर	फैरो ग्रिन्टर	सिवरेज निरीक्षक	सिवरेज इंजीनियर	सिवरेज इंजीनियर ड्रा.	मुख्य सीवरमैन
1	2	128	129	130	131	132	133	134	135	136
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	2	1	-	1	1	1	-	3	-
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	**2**	**1**	**-**	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**-**

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	-	-	-	-	-	ट्यूबवैल क्लीनर	वाटर मीटर मैकेनिक
1	2	137	138	139	140	141	142	143
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	1
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	-	-	-	-	-	1

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	डीजल इंजीनियर मैकेनिक	मोटर मैकेनिक	जनरेटर आप्रेटर	वाटरमैन	पैट्रोलमैन	आयल मैन	की मैन	क्राफ्ट ट्रेसर	एक्सरे अटैण्डैंट
1	2	144	145	146	147	148	149	150	151	152
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	3	-	1
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	-	-	-	-	-	3	-	1

नगर निगमों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नगर निगम का नाम	डीजल इंजन	पैंटर	सिक्च आप्रेटर	लाईट आप्रेटर	मेट	पौंड	मलेरिया मेट	मलेरिया मैगमैन बेलदार	सफाई जमादार
1	2	153	154	155	156	157	158	159	160	161
1.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अम्बाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पानीपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुड़गांव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	फरीदाबाद	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8.	यमुनानगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	रोहतक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I am asking my supplementary. I want to point out a serious irregularity in the papers placed on the Table of the House. Sir, I want to take your cognizance of it and take action against the earring officials. Sir, my question was The town wise, category wise number of posts lying vacant in the Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees of the State and since when ? Since when quote upquote Sir. Since when ? जो रिप्लाई सबमिट किया गया है उसमें पोस्ट तो खाली बता दी लेकिन उसमें since when का कहीं जिक्र नहीं है कि कब से वेकेन्ट हैं। हिन्दी में जो ट्रांस्लेशन की गई है उसमें since when को डिलिट कर दिया गया है। आगे नहीं बताया गया है कि ये पोस्टें कब से खाली बड़ी हैं। राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों और म्यूनिसिपल कमेटीज में श्रेणीवार कितने पद खाली पड़े हैं। Sir, this is a scious irregularity.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह सीरियस लैप्स कैसे हो गया बताईये ?

श्री गोपाल गांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। सरकार ने पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 528 कर्मचारी लगाये हैं और 73 कर्मचारियों की डिमांड एच.एस.एस.सी. और एच.पी.एस.सी. के पास भेजी हुई है और कुछ कर्मचारी हमने दैनिक वेतन आधार पर भी लगा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब ने पूछा है कि पद कब से खाली पड़े हैं ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में तो माना है कि पोस्टें खाली हैं।

श्री अध्यक्ष : ये किसी चीज को खाली छोड़ते ही नहीं। I Can't believe it. कांडा साहब के रहते हुए कुछ खाली रह जाए ये नहीं हो सकता। OK Ji, thank you very much.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो यह रिप्लाई सबमिट किया गया है इसके हिसाब से म्युनिसिपल कमेटीज की लगभग 1605 और म्युनिसिपल कारपोरेशन की 2246 पोस्टें खाली पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं तो शहरों का क्या हाल होगा।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप सवाल पूछिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये बता दिया कि यह रैगुलर प्रोसैस है। अध्यक्ष महोदय, 6 कारपोरेशंज बनाई गई और उन कारपोरेशंज की सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनमें न कमीशनर लगाया गया, ना ज्वाइंट कमीशनर लगाया गया, ना ही इंजीनियर लगाए गए और न ही चीफ इंजीनियर लगाए गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि डेढ़ साल हो गया है, ये ना चुनाव करा रहे हैं और न अधिकारी लगा रहे हैं। अगर इनके पास लगाने की क्षमता नहीं है तो क्या ये उन कारपोरेशंज को दोबारा कमेटियां बनाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में हमने 528 कर्मचारी लगाए हैं और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमने कोई कर्मचारी नहीं लगाए। हमने जो कर्मचारी लगाए हैं उनमें 72 भवन निरीक्षक हैं और 29 सफाई निरीक्षक हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय साथी पूछ रहे हैं कि जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनके बारे में बताएं कि वे कब भरोगे ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, हमने करीब 73 कर्मचारियों की डिमांड सरकार को भेजी हुई है जिसको हम जल्दी ही भर देंगे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, appointment of Government employees is on going process. It is done statutorily through S.S.C. The requestion is being sent by the concerned authority.

Construction of Roads

***875. Smt. Saroj Mor :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new roads from :—

(a) Village Mohla to Ugalan;

(b) Village Puthi to Mohla;

(c) Village Petwar to Ugalan;

(d) Village Chhoti Kauth to Village Mirchpur;

(e) Village Data to Village Khanpur;

(f) Village Bass to Thurana;

(g) Village Bass to Bhaklana;

(h) Village Bass to Kharbla Khera; and

in Narnaud constituency; if so, the details thereof ?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी नये निर्माण के बारे में भी "नो सर" जवाब दे रहे हैं और रिपेयर के बारे में भी "नो सर" का जवाब दे रहे हैं, पानी के बारे में भी "नो सर" का जवाब दे रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में "नो सर" जवाब दे रहे हैं तो हमारे नारनौंद हल्के को हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए। पिछले दिनों पानी के लिए मुख्यमंत्री जी से पंचायत के लोग मिले थे लेकिन उसका भी उनकी तरफ से ठीक रिस्पोंस नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चौधरी जी, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें। (विघ्न) बहन जी, आपने सप्लीमैंट्री तो पूछी नहीं । (विघ्न)

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, ना को हां में बदलने की बात नहीं है। जब हरेक चीज के लिए इनका जवाब "नो सर" है तो इनका मतलब तो नारनौंद हल्के को हरियाणा से बाहर भेजने का है । (विघ्न)

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरोज मोर विधायक जी ने गलत कहा है। अगर सरकार के बस में काम करना नहीं हैं तो यह सरकार बाहर जाए, हम क्यों बाहर जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्पीच है या प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सुभाष चौधरी जी, आप प्रश्न पूछें।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे हल्के के क्षेत्र की 38 सड़कें कच्ची हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन सड़कों को कब तक बनाया जाएगा खासकर खादर क्षेत्र की सड़क को कब तक बनाया जाएगा ?

Mr. Speaker : Separate question may be asked in this regard.

Construction of Water Treatment Plant at Jind

***849. Shri Hari Chand Midda :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction work of the water treatment plant at Jind has been held up ?

(b) if so, the reasons thereof together with the time by which the aforesaid plant is likely be completed and commissioned ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) :

(a) No, Sir.

(b) The work of water treatment plant is likely to be completed and commissioned by 30-6-2012.

श्री हरिचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, यह निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा और उसके निर्माण को किस कारण से रोका गया है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि 30 जून 2012 तक इसका निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। इसमें से Part of the land के ऊपर लिटीगेशन थी जो अब हमारे पास अवेलेबल है। इस प्रौजैक्ट में मात्र 7 या 8 महीने की डिले है।

श्री हरिचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि जींद के जितने भी विकास कार्य हैं वे सारे के सारे अधूरे पड़े हैं और कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। जींद कि स्थिति ऐसी क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : ये कोई सवाल नहीं है। आप स्पीच दे रहे हो। आप सवाल पूछो। (विघ्न)

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, जी, कृषि से संबंधित एक सवाल मेरा कल भी लगा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : कल वाला नहीं, आज का सवाल पूछो।

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि रेवाड़ी का सीवरेज का गंदा पानी पटौदी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, क्या उसको कहीं दूर रेवाड़ी क्षेत्र में ही रोकने का काम किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : यह सैपरेट प्रश्न है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी का प्रश्न है।

Martial Art and Bad Khalsa Sikh Museum

***1073. Shri Dilbagh Singh :** Will the Archaeology and Museums Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Sh. Guru Gobind Singh Martial Art Museum at Kapal Mochan (Yamuna Nagar) and Bad Khalsa Sikh Museium, Sonipat were constructed to mark the historical event of tercentenary celebrations of birth of Khalsa; if so, whether the money/funds are being spent for this purpose; if so, details thereof; and

(b) whether the Government has provided electricity in the museums as at (a) above; if not, the reasons thereof ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukal) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

An amount of Rs. 295.00 lacs was provided to the Deputy Commissioner, Yamuna Nagar for construction/setting up of the Shri Guru Gobind Singh Martial Art Museum at Kapal Mochan, Yamunanagar district, out of which an amount of Rs. 236.37 lacs has been utilised. The Museum is operational since June 2011.

An amount of Rs. 74.00 lacs was provided to the Deputy Commissioner, Sonipat for construction/setting up of the Bad Khalsa Sikh Museum at Rai, Sonipat district, outof which an amount of Rs. 72.57 lacs has been utilised. The Museum is operational since May, 2011.

(b) Yes, Sir. Electricity connections have been provided to both the Museums.

11.00 बजे अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारा ब्यौरा सदन के पटल पर रखा गया है। यह म्युजियम खालसा पंथ की 300 साल की सैलीब्रेशन में स्थापित किया गया था। मिनिस्टर आफ ह्यूमैन रिसोर्स गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने 366 लाख रुपये की ग्रांट-इन-एड गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा को दे दी है जिसमें से फर्स्ट इंस्टालमैंट का 178 लाख रुपया रिलीज हो चुका है और कल्चरल अफेयर डिपार्टमैंट, हरियाणा ने डी.सी., यमुनानगर को कहकर उसका कार्य करवाया है। आज इसमें 295 लाख रुपये में से 74 लाख रुपये के करीब बलैंस है बाकी हमारा इसमें पैसा खर्च हो ही रहा है। स्पीकर सर, गुरुगोबिन्द सिंह मार्शल आर्ट म्यूजियम, यमुनानगर और बढ़खालसा म्यूजियम, राई (सोनीपत) में भी इसी तरह से खर्चा हुआ है। आर्कैलोजी डिपार्टमैंट ने मई, 2011 के बाद श्री गुरु गोबिन्द सिंह मार्शल आर्ट म्यूजियम, यमुनानगर में टोटल 9,16,000 रुपये खर्च किये हैं और बढ़खालसा म्यूजियम, सोनीपत में भी करीबन 22.47 लाख खर्च किये गये हैं।

श्री दिलबाग सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पैसा केन्द्र सरकार ने दिया था उस पैसे में से कितना खर्च किया गया और कितना बच गया और बचा है तो क्यों बचा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दिलबाग सिंह जी, फिगर्स तो आपको बता दी गई हैं, आप और सवाल पूछिये।

श्री दिलबाग सिंह : स्पीकर सर, दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले पांच सालं में कभी वहां पर पेंट तक भी किया गया है ?

Mr. Speaker : Sorry, this not a question.

श्री दिलबाग सिंह : स्पीकर सर, मेरी पांच छह छोटी-छोटी बातें हैं जिनसे सिख समुदाय की भावनायें जुड़ी हुई हैं। सर यह जो दोनों म्यूजियम हैं वहां बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है बल्कि बिजली तो केवल तब दी जाती है जब कोई प्रोगाम आयोजित होता है उसके बाद कोई बिजली नहीं दी जाती।

Mr. Speaker : Sorry, this is not a question, this is a speech.

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि आर्कोलोजी डिपार्टमैंट ने गुरू गोबन्द सिंह मार्शल आर्ट, यमुनानगर को जून, 2011 में टेक ओवर किया था। वहां पर इलैक्ट्रिक कनैक्शंस हो गये हैं आप जरूर वहां पर विजिट करके आयें और देखें कि सरकार ने वहां पर क्या-क्या कार्य किये हैं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों, जिला बार संघ, करनाल के प्रधान एवं सदस्यगण तथा हरियाणा पत्रकार संघ, सिरसा के सदस्यगण का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डाक्टर राम प्रकाश, राज्य सभा सदस्य, श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, पूर्व मिनिस्टर हरियाणा जो स्पीकर गैलरी तथा डिस्ट्रिक्ट बार एसोशिएशन, करनाल अपने अध्यक्ष और 13 सदस्यों के साथ एवं हरियाणा जर्नलिस्ट एसोशिएशन, सिरसा अपने 30 सदस्यों के साथ दर्शक दीर्घा में विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

Supply of Fertilizers

***867. Master Dharam Pal Obra :** Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the fertilizers, particularly urea, is not being made available as per demand in Loharu Constituency;

(b) whether it is also a fact that farmers have to pay more price for the same than the fixed rate due to the black marketing; and

(c) if so, the steps being taken by the Government to check black marketing and to ensure proper supply of fertilizers ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) :

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The Department of Agriculture has taken a series of steps to check black marketing of Fertilizers and ensure proper supply of fertilizers. A special quality control coampaign to ensure supply of quality agricultural inputs to the farmers was launched in the State during Rabi 2011-12 season in two phases *i.e.* 1st phase from 1st to 30th November, 2011 (with special emphasis on seeds and fertilizers) and 2nd phase from 1st to 31st December, 2011 (with special emphasis on fertilizers and pesticides). The effective monitoring is evident from the following :

- 50 FIRs were lodged for violation of Fertilizer (Control) Order, 1985 during 2011-12.
- 25 Memorandum of Acknowledgement (Sale Licences) have been cancelled and 8 have been suspended whereas action is being taken in the remaining cases.
- 3,997 samples of fertilizers were collected during 2011-12 upto December, 2011 out of which 50 samples have been found non-standard. Prosecution is being launched/underway against them.

अध्यक्ष महोदय, इस साल हमने 51 एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हैं जो इतनी बड़ी संख्या अब तक कभी नहीं हुई। सरकार की तरफ से पूरी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा जहां पर टैंपरेरी शॉर्टेज है वहां पर हमने खाद पहुंचाई है। जो लाइसैंसधारक कालाबाजारी या इस प्रकार की दूसरी अनियमितताओं में लिप्त पाये गये हैं इस प्रकार के हमने 28 लाइसैंस रद्द किये हैं तथा 17 लाईसैंस सस्पैंड किये हैं।

Re-Construction of Roads

***854. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from Shamlo Kalan to Pillukhhera via Dhingana, Nidana, Chabri, Asan villages by including it under the Pardhan Mantri Sarak Yojna; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be reconstructed ?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का जिक्र किया गया है इस सड़क से होकर के अनाज मंडी, जुलाना और अनाज मंडी, पिल्लूखेड़ा के लिये मेन रास्ता है। हर रोज किसानों को टैक्टर-ट्रालियां लेकर वहां से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते से एक बार में केवल एक टैक्टर ट्राली ही निकल सकती है। कई ऐक्सीडैंट्स ऐसे हो गए जिनमें ट्राली पलट जाती है। इसी सड़क से गन्ना ले जाया जाता है। बहुत कठिनाई का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन लगाया था क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह इनकी डिमांड है और इसको आप पूरा करवाने की कोशिश करें।

Shri Randeep Singh Surjewala : I noted Sir.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने आश्वासन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

Average Rate of Return

***810. Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Finance Minister be pleased to state the details of loans and investments made by the Government as on 1-4-2011 togetherwith the average rate of return on the loans and investments in 2008-09, 2009-10 and 2010-11 ?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, the cumulative amount of Loans and Advances made by the State Government as on 1-4-2011 is Rs. 2982.93 crore and average rate of return in 2008-09, 2009-10 and 2010-11 is 2.81% and 2.94% and 1.83 % respectively.

The cumulative amount of Investment made by the State Government in the Share Capital of different concerns as on 1-4-2011 is Rs. 6376.98 crore and average rate of return in 2008-09, 2009-10 and 2010-11 is 0.16%, 0.17% and 0.04% respectively.

श्री कृष्ण पाल गुज्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नैट मार्जिन क्या है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने कितने परसैंट रेट आफ इंट्रैस्ट पर ऋण दिया है और कितने परसैंट पर लिया है और इस दर को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

Mr. Speaker : Hon'ble Member, Now the questions hour is over.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा –

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker : I am to inform the House that I have received an intimation from S/Shri Raj Pal Bhukhri and Naresh Selwal, MLAs in which they have expressed their inability to attend the sitting of the House today *i.e.* 2nd March, 2012 as they have to attend the cremation of mother of Kumari Selja, Union Minister.

विभिन्न मामले उठाना

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार खाद पर से सब्सिडी खत्म करने जा रही है इससे किसानों पर बहुत आर्थिक भार पड़ेगा। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार इस बारे में एक प्रस्ताव पास करके भेजे कि किसानों को जो खाद पर सब्सिडी दी जाती है उसे खत्म न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

@ सभी अतारांकित प्रश्नों के उत्तर बहुत ज्यादा बड़े होने के कारण हरियाणा विधान सभा पुस्तकालय में रखे गए हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, खाद की सब्सिडी केन्द्र सरकार खत्म करने जा रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हरियाणा विधान सभा में सर्वसम्मति से इस बारे में प्रस्ताव पारित किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं करनी होती तो ये मोशन देते ही क्यों हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह खाद से जुड़ा हुआ इशू है, किसानों से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर चर्चा और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा जाना अति आवश्यक है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, खाद की सब्सिडी खत्म न की जाए क्योंकि पहले ही खाद के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। पहले इस विषय पर आप हमें बोलने की इजाजत दें।

Mr. Speaker : I will ask the Government. जो बिजनैस पहले लिस्टिड है मैं उस बिजनैस को पहले टेक-अप करूंगा। पहले लीडर ऑफ दि हाउस को आने दीजिए. मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम पूरे प्रदेश के और देश के किसानों की बात कर रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, हमारा कालिंग अटैंशन मोशन ओल्ड एज पैंशन के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, यह आपका ही कालिंग अटैंशन मोशन है, उसमें श्री अशोक कुमार अरोड़ा, श्री अजय सिंह चौटाला जी और श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने बोलना है। इसका मतलब आप ओल्ड ऐज पैंशन पर बोलना नहीं चाहते Everybody please sit down. (Interruption) Don't record anything which is said without my permission, (Interruption) Nothing should be said while you are sitting.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना यही है कि यह इश्यू पहले टेक-अप किया जाए।

Mr. Speaker : Honble Members old age pension is a very important issue. Although the mover of the Calling Attention Motion is not present in the House for the reasons already told you. So, I have allowed next Member. Shri Ajay Chautala, Shri Ashok Arora, Shri Rampal Majra and Shri Perminder Singh Dhull and others have also moved this motion, so, we want to discuss this issue. Let Mr. Batra start. (Interruption) Should I think that this is not important ? अरोड़ा साहब, क्या मैं यह समझूं कि आप इसको कोई महत्व नहीं देते। आप ओल्ड एज पैंशन पर डिसकशन हो जाए इस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम हर चीज को महत्व दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ओल्ड ऐज पैंशन के विषय को महत्व नहीं दे रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हाउस में सर्वसम्मति द्वारा खाद की सब्सिडी के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं इस विषय को ओल्ड ऐज पैंशन के विषय के बाद सुनूंगा। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हाकी प्लेयर्स ने आज ओलम्पिक गेम्ज के लिए क्वालिफाई करके बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करे। इसी प्रकार से मेरा राईट टू ऐजूकेशन का मोशन था।

Mr. Speaker : Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, the Hon'ble Member wants that the hockey team of India has done a commendable job by qualifying for the Olympics in Landon, 2012. He wants that the House should pass a resolution commending their effort and appreciating their victory. So, are you ready to move such a resolution ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, absolutely no difficulty and I join the sentiments expressed by my learned friend and immediately after this I will bring a short motion commending the hockey team wishing them well as also what the Government proposes to do for the hockey team and the players.

Mr. Speaker : Other than this, I have also fixed the discussion on the sports policy which is coming upon 6th March. Now the Hon'ble Member may please read.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 6 regarding anomalies in distribution of old age pension in Haryana. Since he is not present in the House. I allow Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. to read out this notice. Shri Ram Pal Majra and two other MLAs (namely; S/Shri Ashok Kumar Arora and Parmender Dhull) have also given Calling Attention Notice on the similar subject. Shri Ram Pal Majra, M.L.A. the first signatory is also allowed to raise supplementary. Shri Ashok Kumar Arora, M.L.A. and two other M.L.As (namely ; S/Shri Ram Pal Majra and Ajay Chautala) have also given notice under Rule 73-A on the similar subject. Shri Ashok Kumar Arora, M.L.A. and Shri Ajay Chautala, M.L.A. are also allowed to raise supplementary. Now, Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. may read the notice.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-6

@ श्री राज पाल भूखड़ी : इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि राज्य के वृद्ध व्यक्तियों में वृद्धावस्था पेंशन तथा इसका वितरण बहुत चिन्ता का विषय है। जनता द्वारा अनुभव की गई बहुत ज्यादा वितरण विसंगतियों को, उन राष्ट्रीकृत तथा निजी बैंकों द्वारा, जिनको गांवों में बहुत अधिक संख्या में रह रहे लोगों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेश योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा पेंशन के वितरण का कार्य सौंपा गया था, समुचित ढंग से समाधान नहीं किया गया है।

अत: वह सरकार से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करते हैं :--

(i) 1 अप्रैल, 1999 से आज तक पेंशन की दरें तथा पेंशन की श्रेणियां/पात्रता क्या है;

@ Read by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA

[श्री राज पाल भूखड़ी]

(ii) 1 अप्रैल, 1999 से आज तक राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना को केन्द्रीय सरकार का अंशदान;

(iii) वित्तीय वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2010-11 तक राज्य में वर्षवार लाभानुभोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(iv) राज्य में पेंशन वितरण का ढंग तथा बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण द्वारा वित्तीय समावेश की योजना का ब्यौरा क्या है; तथा

(v) क्या पेंशन के वितरण के इस नये ढंग में सरकार द्वारा कोई परिवर्तन प्रस्तावित है।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : उपाध्यक्ष महोदय, इन बिन्दुओं का उत्तर निम्न अनुसार है :

(i) 1 अप्रैल, 1999 से आज तक पेंशन की दरें तथा पेंशन की श्रेणियां/पात्रता क्या है;

1 अप्रैल, 1999 से आज तक पेंशन की दरें तथा पेंशन की श्रेणियां/पात्रता निम्न अनुसार हैं :

बढ़ौतरी की तिथि	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की बढ़ी हुई दरें
17-6-1987	100/-
1-11-1999	200/-
1-11-2004	300/-
1-3-2009	▸ 700/- (01-03-1999 या इससे पूर्व पंजीकृत सभी लाभपात्रों के लिए)
	▸ 500/- (अन्य के लिए)
1-4-2011	▸ 700/- (01-03-1999 या इससे पूर्व पंजीकृत सभी लाभपात्रों के लिए)
	▸ 550/- (01-04-2010 या इससे पूर्व पंजीकृत सभी लाभपात्रों के लिए)
1-4-2012	▸ 700/- (01-03-1999 या इससे पूर्व पंजीकृत सभी लाभपात्रों के लिए)
	▸ 550/- (01-04-2010 या इससे पूर्व पंजीकृत सभी लाभपात्रों के लिए)
	▸ 500/- (अन्य के लिए) और नए पेंशनर्स के लिए

पात्रता की शर्तें

अधिसूचना संख्या 1957-स०क० (3)-92, दिनांक 13 अगस्त, 1992

(i) वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए यह व्यक्ति योग्य है जो :

(क) 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो;

(ख) हरियाणा राज्य का अधिवासी हो; और

(ग) 100/- रुपये मासिक या इससे अधिक पेंशन प्राप्त न कर रहा हो।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

(क) आवेदक की स्वयं, उसके पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों सहित एकत्रित सिंचित भूमि 5 एकड़ तथा असंचित भूमि 10 एकड़ से अधिक न हो।

(ख) आवेदक की स्वयं, उसके पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों की सभी साधनों से एकत्रित आय 10,000/- रुपये वार्षिक से अधिक न हो (भूमिहीन आवेदकों के मामले में)।

(iii) शहरी क्षेत्रों के लिए

आवेदक की स्वयं, उसके पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों की सभी साधनों से एकत्रित आय 10,000/- रुपये वार्षिक से अधिक न हो ।

(iv) (क) यदि पति और पत्नी दोनों पेंशन के योग्य हों तो दोनों अलग-अलग पेंशन प्राप्ति के हकदार होंगे।

(ख) यदि भूतपूर्व सैनिक सेना से 100/- रुपये मासिक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो उसकी पत्नी पेंशन की हकदार होगी, यदि वह अन्यथा योग्य हो तो।

(v) निम्न व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे :

(क) यदि वे स्वयं या उनके बच्चे बिक्रीकर दाता हों।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चे राज्य सरकार की सेवा में श्रेणी-I/श्रेणी-II के राजपत्रित अधिकारी हों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में उसके समकक्ष पद पर नियुक्त हों अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत हों और श्रेणी-II के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष वेतन प्राप्त कर रहे हों (न्यूनतम 4,000/- रुपये मासिक)।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चे व्यवसायी हों जैसे (क) डाक्टर, (ख) वकील, (ग) चार्टर्ड अकाऊंटैंट, (ध) आयकर परामर्शी, (ङ) दंत चिकित्सक, (च) अभियंता या वास्तुकार (छ) ठेकेदार इत्यादि (यह केवल उदाहरणार्थ हैं और इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय भी इसमें सम्मिलित किये जा सकते हैं)।

(घ) जिनके बच्चे आयकर दाता हों।

(ङ) ऐसे व्यक्ति जो स्वयं/उनके बच्चे भूतपूर्व सांसद/विधायक/बोर्ड/निगम के अध्यक्ष हों।

अधिसूचना संख्या 2828-सं०क० (4) - 2001, दिनांक 19 सितम्बर, 2001

उप-धारायें (ii) तथा (iii) अर्थात् भूमि सीमा व आय सीमा के मानदण्ड 2001 में हटा दिये गये थे।

अधिसूचना संख्या 458-सं०क० (4) - 2011, दिनांक 10 जून, 2011 जो इस समय पेंशन दी जा रही है।

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृति के लिये पात्र है, यदि

(i) उसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हैं; तथा

(ii) वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और हरियाणा में रह रहा है; तथा

(iii) उसकी स्वयं व पति/पत्नी सहित सभी साधनों से आय 50,000/- रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है।

नोट : आय सीमा में वृद्धि 50,000 से 2 लाख रुपये किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

अपवर्जन :

उपरोक्त के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा / रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्त का पात्र नहीं होगा/होगी। जो दूसरी बात कालिंग अटेंशन में पूछी गई है वह रिप्लाई इस प्रकार है :--

(ii) **1 अप्रैल, 1999 से आज तक राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना को केन्द्रीय सरकार का अंशदान :**

1 अप्रैल, 1999 से आज तक राज्य सरकारी की वृद्धावस्था पेंशन योजना को केन्द्रीय सरकार का अंशदान निम्न अनुसार है :

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंशदान (रुपये लाखों में)
1999-2000	515.20
2000-2001	515.20
2001-2002	515.20
2022-2003	545.08
2003-2004	566.15
2004-2005	862.20
2005-2006	862.20
2006-2007	2,846.23
2007-2008	3,127.34
2008-2009	3,127.34
2009-2010	3,127.34
2010-2011	3,127.34
2011-2012	3,127.34

(iii) **वित्तीय वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2010-11 तक राज्य में वर्षवार लाभानुभोगियों की कुल संख्या कितनी है :**

वित्तीय वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2010-11 तक राज्य में वर्षवार लाभानुभोगियों की कुल संख्या

कितनी है :

वर्ष	लाभपात्रों की संख्या
1999-2000	9,87,634
2000-2001	9,63,849
2001-2002	9,10,412
2002-2003	8,45,821
2003-2004	8,94,863
2004-2005	9,94,766
2005-2006	9,40,368
2006-2007	10,62,807
2007-2008	9,95,028
2008-2009	11,25,372
2009-2010	12,50,349
2010-2011	13,86,207

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

(iv) **राज्य में पेंशन वितरण का ढंग तथा बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण द्वारा वित्तीय समावेश की योजना का ब्यौरा क्या है :**

राज्य में पेंशन वितरण प्रणाली तथा बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण सम्बन्धी वित्तीय समावेश योजना के विवरण

उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2006 से पूर्व पेंशन का वितरण मण्डल राजस्व अधिकारियों की देख-रेख में पटवारियों के माध्यम से किया जाता था। वर्ष 2006 में पेंशन वितरण प्रणाली में परिवर्तन करते हुये इसे पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कर दिया गया था। वर्ष 2011 में पेंशन का वितरण बायोमैट्रिक्स आधारित स्मार्ट कार्ड्स के प्रयोग द्वारा बैंकों के माध्यम से ई.बी.टी. प्रणाली से शुरू किया गया था।

गबन को कम करने तथा इच्छित लक्ष्य तक अविलम्ब लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेश योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा पेश किये गैर मगजी बचत खातों का प्रयोग करते हुये व्यापार संवाददाता माडल को माध्यम से पेंशन इलैक्ट्रोनिक माध्यम से लाभपात्रों के बैंक खातों में जमा कराने की प्रणाली का सम्पादन किया गया। सरकार को आशा थी कि लाभ पात्र अन्य बैंक ग्राहकों के समान ही गांव में स्थापित ग्राहक सेवा केन्द्र पर अपने बैंक खाते का संचालन करने के योग्य होगा। इस सन्दर्भ में राज्य भर में लगभग 2 मिलियन खाते खोले गये, जिनमें से 18.2 लाख बैंक खातों का सक्रिय संचालन हुआ। इसके अतिरिक्त विस्तृत क्रियान्वयन दिशा निर्देश "Service Level Perfoemance Standards for Electronic Benefit Transfer through Banks" नामक दस्तावेज में कानून बद्ध किये गये। वित्तीय समावेश में हरियाणा द्वारा की गई प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जिसके लिये राज्य को State of the Year Skoch Financial Inclusion Award- 2012 से सम्मानित किया गया।

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

(v) क्या पेंशन के वितरण के इस नये ढंग में सरकार द्वारा कोई परिवर्तन प्रस्तावित है ?

ऐसा महसूस किया गया कि बैंकों तथा उन द्वारा नियुक्त व्यापार संवाददाताओं की ओर से अपर्याप्त आधार भूत संरचना उपलब्ध कराने के कारण, पेंशनधारकों को अपने बैंक खातों का संचालन करने में कठिनाईयां हो रही थी। इसलिये व्यापार संवाददाताओं की पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध होने तक पेंशन वितरण का कार्य पहले की तरह पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को वापस कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पेंशन वितरण में होने वाली देरी को कम करने के लिये सरकार द्वारा गणना की गई पेंशन राशि को पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में सीधा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से जमा करना का निर्णय लिया गया है। अब बैंकों द्वारा वार्ड-वाईज पर्याप्त आधारभूत संरचना स्थापित किये जाने के बाद शहरी क्षेत्रों में बैंक खातों में पुन: पेंशन राशि जमा कराई जायेगी। पर्याप्त बैंकिंग आधारभूत संरचना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों द्वारा अपने व्यापार संवाददाता एजैन्टों (बी.सी.ए.) की वार्ड-वाईज स्थिति अधिसूचित की जायेगी। इसके अतिरिक्त व्यापार संवाददाता एजैन्टों द्वारा नये पेशनधारकों का एन्रोलमेंट, स्मार्ट काड्र्स का वितरण तथा शुद्धिकरण व ग्राहकों की शिकायत निवारण जैसे कार्य भी किये जायेंगे। सम्बन्धित जिला उपायुक्तों द्वारा व्यापार संवाददाता केन्द्रों का सत्यापन करने के बाद बैंक खातों में पुन: नये सिरे से पेंशन राशि जमा कराई जायेगी। तब तक पहले की तरह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हाथ से पेंशन वितरण का कार्य जारी रहेगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा पर्याप्त आधारभूत संरचना स्थापित किये जाने के बाद गांवों में भी पेंशन राशि नये सिरे से बैंक खातों में डालनी शुरू की जायेगी।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस समय जो आपकी सरकार की स्कीम है उसमें कौन-कौन इलीजिबल हैं। पहले मंत्री जी ने कुछ प्रावधान बताये। फिर इन्होंने बताया कि वर्ष 2001 के अन्दर कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया और उसके बाद 2011 की एक नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि कंसोलीडेटिड आधार पर कौन-कौन से लोग इसके अन्दर आते हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो पेंशन के लिए सरकार ने 60 साल की उम्र रखी है जिस आदमी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है उसकी पेंशन के लिये पात्रता कैसे परखी जाती है। डॉक्टर्ज का सर्टिफिकेट एग्जेक्टली पूरा प्रूफ नहीं है। स्पीकर सर, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेडीकल साईंस के अन्दर एक डॉक्टर एग्जैक्ट डेट असरटेन नहीं कर सकता। क्या इस प्रकार के मामले में गांव के किसी मौजिज आदमी का सर्टिफिकेट भी साथ में कंसीडर किया जाता है कि इस आदमी की उम्र 60 साल है। एक बात मैं और यह पूछना चाहता हूं कि अब जो गवर्नमैंट सरवैंट पेंशन इश्यू कर रहे हैं क्या वह बॉयामैट्रिक सिस्टम से इश्यू कर रहे हैं या वैसे ही आईडैंटीफिकेशन से कर रहे हैं ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें पूछी हैं। एक तो सरकार द्वारा दी जा रही ओल्ड ऐज पेंशन के लिए कि इस समय इस पेंशन के लिए क्या नॉर्म्ज हैं ? इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ओल्ड ऐज पेंशन के लिए 60 साल की उम्र होना अनिवार्य है, दूसरा उसके लिए हरियाणा का मूल निवासी होना भी अति आवश्यक है और तीसरा पति या पत्नी की आय के सभी साधनों से आय दो लाख रुपये वार्षिक हो जो कि पहले 50 हजार रुपये वार्षिक थी जिसको अब बढ़ाकर दो लाख रुपये वार्षिक किया गया है। जो इन शर्तों को फुलफिल करते हैं वे सब लोग इसके लिए इलीजिबल रहेंगे। जो लोग किसी स्थानीय वित्तीय निकाय से सहायता प्राप्त कर रहे हैं या किसी संगठन से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इसमें इलीजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी बात इसमें यह पूछी गई कि अगर किसी के पास 60 साल की उम्र का सर्टिफिकेट नहीं है क्या उसके लिए डॉक्टर्ज का सर्टिफिकेट

मान्य होगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस समय हमने एक सैल्फ अटैसटेशन का सिस्टम शुरू किया है कि जब कोई व्यक्ति अथवा महिला 60 साल के हो जाते हैं वे अपने आयु के किसी भी प्रूफ जैसे वोटर आई.कार्ड या कोई दूसरे आयु के प्रूफ को सैल्फ अटैसटेशन के साथ हमारे द्वारा दिये जाने वाले फार्म को भरकर जमा करवा दें जिसके बाद अपने आप ही सम्बन्धित व्यक्ति/महिला की पेंशन शुरू हो जायेगी। जिन व्यक्तियों/महिलाओं के पास किसी भी प्रकार का आयु प्रमाण-पत्र नहीं है उनके लिए हमने अपने सी.एच.सीज. में एक कमेटी का गठन किया है जिसमें जाकर वे अपना मैडीकल करवाने के बाद आयु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फार्म भरने के बाद पेंशन स्वत: ही शुरू हो जायेगी। इसके अलावा तीसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि जो पहले हमारी पेंशन मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी उसके बाद बैंकों के माध्यम से पेंशन देने का हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया कि बैंक खाते में लाभार्थियों की पेंशन सीधे जाये जिसके लिए हमने बैंकों में 20 लाख खाते खुलवाये और बायोमैट्रिक कार्ड सभी खाताधारकों को दिये गये। पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में कही न कहीं कोई दिक्कत जरूर आई जिसमें अंगूठे का प्रावधान या मिसमैच की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई मांग को ध्यान में रखते हुए और सम्मानजनक बुढ़ापा पेंशन धारक बुजर्गों की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया कि बायोमैट्रिक कार्ड के थ्रू पेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बंद कर दिया। जो हमने बैंक कोरेसपौंडैंट लड़के लगाये थे उनसे कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी इस वजह से हमने उस प्रणाली को बंद करते हुए बैंक्स को कहा कि पहले वे बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से पेंशन वितरण की व्यवस्था की पूर्ण विश्वसनीयता को सुनिश्चित कर लें जिससे हमारे पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमने यह निर्णय लिया है कि ऐसा होने के बाद ही बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से पेंशन वितरित होगी। इसके साथ-साथ हमने बैंकस को यह निर्देश भी दिये हैं कि जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक वे पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युअली ही करेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 1987 में चौधरी देवी लाल ने जब यह सम्मान पेंशन शुरू की तो जो 60 साल का हो गया उन सब बुजुर्गों को 100-100 रुपये सम्मान के रूप में शुरू की थी। उस समय आय का सर्टिफिकेट देने की कोई बात नहीं थी। अब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले 50 हजार रुपये की लिमिट रखी गई थी और अब इसको 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये सालाना किया जा रहा है। इसमें बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आयेगी। इसमें मेरा प्रश्न यह है कि बुजुर्गों को जो 60 साल के हो जायें उनको बिना आय के सर्टिफिकेट के क्या वृद्धावस्था सम्मान पेंशन देंगे ? इसी प्रकार से अंगूठे के चक्कर में भी बहुत से बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 3-3 महीने तक पेंशन नहीं मिलती और ऊपर से यह इन्कम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया तो मैं नहीं समझता कि यह सम्मान पैंशन होगी यह तो अपमान पेंशन होगी। क्या मंत्री जी इस प्रावधान को खत्म करेंगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बुजुर्गों को सम्मान पेंशन देने की बात कही है इस बारे में सरकार ने बुजुर्गों के मान सम्मान को देखते हुये यह प्रावधान किया है। हमारे पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आई थी कि जो बुजुर्ग लाभार्थी हैं उनको पेंशन मिलने की बजाय उनके पोते, बेटे या दोहते आदि पेंशन ले जाते थे या परिवार के दूसरे लोग ले जाते थे। तो हमने यह अंगूठे वाला प्रावधान इसलिए किया था कि यह पेंशन उनको सीधी मिले और उनके साथ कोई धोखा न हो। उसके खाते में पेंशन जाये और चाहे तो यह अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा हमारे कारोसपौंडैंट से निकलवा ले

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

और चाहे पूरी ही निकलवा ले या उसको अपने बचत खाते में पड़ी रहने दे। जहां तक दूसरे सवाल का सम्बन्ध है कि आय लिमिट हटा दी जाये तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इस महान सदन में बैठे हुये हमारे सम्मानित सदस्य भी जो 60 साल से ऊपर के हो गये वे भी इस पेंशन के हकदार हो जायेंगे जबकि उनको दूसरे पेंशन बेनिफिट दिये जाते हैं। वर्ष 2011-12 का जो हमारा जनगणना का डाटा आया है उसमें हमारे राज्य में तकरीबन 19 लाख बुजुर्ग हैं जो कि 60 साल से ऊपर के हैं। 19 लाख में से 13.4 लाख लोग हमारी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन का लाभ उठा रहे हैं बाकि उसमें से तकरीबन 2.06 लाख लोग हमारी विधवा पेंशन या डैस्टीच्यूट वूमैन पेंशन से जुड़े हुये हैं। इस प्रकार 19 लाख में से लगभग साढ़े 15 लाख लोग हमारी सम्मान पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा जो बचे हुये हैं वे या तो सर्विस में थे या उनकी इन्कम बहुत ज्यादा है। इस वजह से उनको पेंशन नहीं दी जा रही है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कालिंग अटेन्शन मोशन सैप्रेट है ये उसमें पूछ सकते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटैन्शन मोशन इसी के साथ क्लब किया गया है इसलिए मैं यह सवाल पूछ रहा हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, अगर क्लब किया गया है तो उसका रिप्लाई भी मैं सदन के पटल पर जरूर पढ़कर सुनाना चाहूंगी ताकि बहुत से संशय जो हैं वे दूर हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक कालिंग अटैन्शन मोशन जो श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की तरफ से आया है उसकी रिप्लाई बिल्कुल सैप्रेट है और मैं समझती हूं कि उसको सदन के पटल पर रखने के बाद बहुत सी भ्रांतियां खुद ही दूर हो जायेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो क्लब किया है उसका भी हमें पता है लेकिन मेरा एक बहुत अहम प्रश्न है । यह तो एक लॉ है कि जो पहले एक पेंशन ले रहा है वह यह वृद्धावस्था पेंशन नहीं ले सकता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है या एम.एल.ए. हैं या जो इन्कम टैक्स पेयी हैं उनको छोड़ कर बाकी जो बुजुर्ग प्रदेश के हैं वे इन्कम सर्टिफिकेट कहां से देंगे। मेरा यह कहना यह है कि 2 लाख की लिमिट हो या 50 हजार की हो यह लिमिट की शर्त उसमें से हटा देनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है। यह मेरा आपसे पर्सनली सुझाव है कि आप इस शर्त को हटाओगे या नहीं हटाओगे।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, सम्मान पेंशन के लिए सालाना इन्कम की लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। उसके बारे में फिलहाल सरकार का उसको कम करने का कोई विचार नहीं है।

Dr. Ajay Singh Chautala : Thank you Speaker Sir, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सभी सम्मानीय सदस्यों की इसमें शायद एक ही राय होगी कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, उन्हें सम्मान मिले। चौधरी देवी लाल जी ने यह पेंशन योजना लागू भी सम्मान के लिये की थी। परन्तु आज हालत यह है कि हमारे बुजुर्ग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। जब वे पेंशन लेने के लिये जाते हैं तो तरह-तरह की डिफिकल्टीज उनके सामने आती हैं। सरकार यह कह रही है कि इस योजना के लिए हमें अवार्ड मिला है। एक तरफ तो सरकार अवार्ड लेने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उस योजना

में खुद ही बदलाव कर रही है, इसलिए यह एक संशय की बात हो जाती है। इस मामले में सरकार को उदार होना चाहिए और जो ये इफ एण्ड बट लगाए जा रहे हैं इन्हें दूर करके समान दृष्टि से सबको सम्मान दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सुझाव है सिर्फ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, बुढ़ापा पेंशन को जिस प्रकार सम्मान के लिए पेंशन बताया गया। आज लोगों को बुढ़ापा पेंशन न मिलने के कारण सड़कों पर जाम लगाने पड़ते हैं। पिछले सात-सात महीने से पेंशन के लिए वो बूढ़े इन्तजार कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो खाट में पड़े हैं या उनकी इतनी खराब हालत है कि वे उठकर बैंक में नहीं जा सकते। उसके बावजूद जो सरकार का प्रतिनिधि है वह बार-बार रिकवैस्ट करने के बाद भी उनके पास गया ही नहीं है। उन पेंशन धारकों का क्या होगा जो सात-आठ महीने से खाट में पड़े हैं। आज हालत यह हो गई समाज कल्याण विभाग द्वारा अगले महीने की पेंशन दे दी जाती है और पिछले पांच-सात महीनों की पेंशन बाकी रह जाती है। बाद में उस पेंशन को विभाग के जो कमिशन एजेंट होते हैं वे हड़प कर जाते हैं। मेरे जिले में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां दो महीने की पेंशन दे दी गई है लेकिन पांच महीने की बकाया पड़ी है। अब उन आदमियों की जिनकी बुढ़ापा पेंशन बकाया पड़ी है उनमें से कुछ की तो डैथ हो चुकी है। जिनकी डैथ जुलाई में हुई है और उनकी पिछले चार महीने की पेंशन बकाया है क्या उनके बाल-बच्चों को उनकी बकाया पेंशन दी जाएगी। यह मेरा एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस एजैंसी को सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिये निर्धारित किया गया था क्या उनकी पेंशन का पूरा पैसा देकर यह आदेश दिए थे कि वह घर-घर जाकर बुढ़ापा पेंशन बांटेगी ? अब उस एजेंसी के पास बुढ़ापा पेंशन का पैसा बकाया है क्या उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आज उस एजेंसी ने जो खाते दिखाए हैं उसमें यह दिखाया है कि आज सात महीने की पेंशन बकाया है जबकि कहीं पर उसने दो महीने की पैंशन बांट दी और कहीं पर नहीं बांटी क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहूंगी कि दो-तीन अलग-अलग मुद्दे हैं जो इस विषय में यहां पर उठाए गए। वैसे तो सदन के पटल पर जो रिप्लाई दी गई है उसमें बहुत सी बाते हैं जो कलियर की गई है। इन्कम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्कम सर्टिफिकेट किसी भी बुजुर्ग को देना लाज़मी नहीं है। केवल एक सैल्फ अटैस्टेशन सर्टिफिकेट ही उनको देना होगा कि वह 60 साल के हो गए हैं और उनकी आय इतनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो 60 साल का बुजुर्ग है और वह इन्कम टैक्स पेयी नहीं है और जो कोई पेंशन नहीं लेता उसको यह बुढ़ापा पेंशन दी जाए। सरकार को यह इन्कम वाली शर्त तो खत्म ही कर देनी चाहिए।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister please continue.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, केवल अपने हाथों से दो लाइन लिखकर देनी है जोकि बहुत ही जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जैसा की हमारे सम्मानित सदस्य ने जींद की समस्या को विशेष तौर से बताया। बैंकों के माध्यम से हमने इस बुढापा पेंशन लेने वाले का बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की है। जींद जिले में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले तकरीबन 85521 बैनीफिशरीज थे और

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

पूरे स्टेट में एक लाख 30 हजार बेनीफिशरीज थे। हर प्रकार की शिकायतें आई हैं कि करीब 7 प्रतिशत बेनीफिशरीज ऐसे रह गए हैं जिनके या तो खाते नहीं खुल पाये या फिर उनकी ऐज सही नहीं लिखी गई थी। जो भी कारण रहे हों जिस कारण से उन्होंने अपने खाते नहीं खुलवाए। जिन भी व्यक्तियों के बैंक में खाते खुले चाहे उनको बैंक से मैनुअल पेंशन की अदायगी हो पाई या नहीं हो पाई सभी के खातों में यह पेंशन गई। जब हमने बैंकों को पेंशन देने का कार्य दिया तो बैंकों ने बैंक कोरस्पोंडैंट्स नियुक्त कर दिये जिनका कार्य प्रत्येक गांव में जाकर ओल्ड ऐज व्यक्ति को सम्मान पेंशन घर पर ही देने के कार्य को सुनिश्चित बनाना था। इस योजना के द्वारा हमारा यह लक्ष्य था कि किसी भी बुजुर्ग को लाईन में खड़ा होकर पेंशन न लेनी पड़े। बैंकों के इस सराहनीय कार्य के फलस्वरूप हमें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जिसमें बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण करने के लिए 20 लाख से ऊपर सेविंग अकाउंट खोले गये। फिनों कम्पनी ने अपने बैंक कोरस्पोंडैंट्स लगाये। हमने विजिट्स संख्या के बारे में जो उनको दिशा-निर्देश दिये थे उन्होंने उन विजिट्स संख्या के दिशा निर्देश पर कोताही बरती। इस कोताही को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गम्भीरता से लिया है। हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों ने भी तथा हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि इस पद्धति में दिक्कत है तो हमने बैंकों के माध्यम से पेंशन के सिस्टम को बंद करते हुए हमने बैंक के खातों से मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन देने को कहा। मार्च के महीने में हमारे करीबन छह बैंक (विघ्न) स्पीकर सर, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि बैंकों के माध्यम से जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को नहीं मिली, वह बकाया पेंशन 30 अप्रैल, 2012 तक ब्याज समेत हमारे सभी बुजुर्गों को दे दी जायेगी।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, इसमें कोई शक नहीं कि ओल्ड ऐज पेंशन का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बाधायें लगाई जा रही हैं यह सब मेरे हिसाब से गलत हैं। एक आदमी किस बात के लिए इन्कम सर्टिफिकेट खुद अटैस्ट करके दे ? इसके साथ जो दो लाख रुपये की कंडीशन लगाई गई है इसकी तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ स्वाभिमानी बुजुर्ग लोग तो पेंशन लेना ही नहीं चाहते लेकिन जो 60 साल से ऊपर हैं और पेंशन लेना चाहते हैं उनको पेंशन दो चाहे वो कोई भी हो। यह तो बुजुर्गों के सम्मान की बात है उसमें हमें किसी प्रकार की कोई बाधा या कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। जो बुजुर्ग 60 साल पूरे कर चुका है वह पेंशन का अधिकारी हो जाता है। जो सर्विस करता है उसको भी 60 साल तथा 58 साल के बाद पेंशन मिलती है। पेंशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी खामी है वह यह है कि आज 40-40 साल की उम्र के व्यक्ति भी पेंशन ले रहे हैं। यह चैक करवाने की जरूरत है और अगर चैक किया गया तो ऐसे मामलों की परसैंटेज फिफ्टी-फिफ्टी की होगी। असली सम्मान बुजुर्गों के लिए हमारा यही होना चाहिए कि 60 साल का जो भी व्यक्ति है उसे यह सम्मान पेंशन मिले। स्पीकर सर, जो बैंक सिस्टम है इसमें भी एक एक्सपिरियंस आया है कि फोटो किसी का और नाम किसी का। इस कारण बुजुर्गों को काफी दिक्कत आई है। यह तो बिल्कुल फुल प्रूफ मसला होना चाहिए और बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आये। हर गांव से 15-15 ऐसे उदाहरण आये हैं कि बैंक में नाम किसी का है और फोटो किसी का है। बुजुर्ग बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, तीन-तीन, चार-चार महीने तक उसका कोई हल नहीं निकल पाता। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है और हमें इसको बहुत अच्छी तरह से हल करना चाहिए क्योंकि ये बुजुर्गों के सम्मान की बात है । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वे मुझे इस विषय के बारे में अपने सुझाव लिखकर भिजवा दें ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, I will ask you to reply. Let him finish.

श्री आनंद सिंह दांगी : बहन जी, आप मुझे लिख कर दें, मैं आपकी मदद करूंगा। जो बात आपने लिख ली हैं वह सारी बातें हम मानने वाले नहीं हैं क्योंकि यह बुजुर्गों के सम्मान की बात है उनको बेइज्जत करने की नहीं। हम कहीं उनको बैंक में भेज रहे हैं, कहीं उनसे इन्कम सर्टिफिकेट ले रहे हैं यह क्या बुजुर्गों के लिए सम्मान की बात है ? यह बिल्कुल साफ बात है न तो बैंक सिस्टम होना चाहिए, न सैल्फ इन्कम सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक साठ साल का बुजुर्ग है, राशन कार्ड उसके पास है, वोटर कार्ड है, सारी चीजें उसके पास हैं तो इनके हिसाब से उनकी उम्र वैरीफाई करके, फार्म भरवाकर उसको पैंशन देनी चाहिए। बैंक सिस्टम में पैंशन वितरण में बहुत ज्यादा समस्या है जब पंचायत के द्वारा लोगों को पेंशन का वितरण सही ढंग से हो रहा है तो बैंकों की हैल्प क्यों ली जा रही है जबकि उससे हमारे बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बुजुर्ग 80 साल का है कोई 90 साल का है और कोई तो बिल्कुल डैथ डोर पर है यह बैंक में जाकर कैसे पेंशन लेगा। अत: यह बिल्कुल साफ है कि जब पेंशन सिस्टम भी एक पंचायती सिस्टम है तो पेंशन वितरण भी पंचायती ढंग से होना चाहिए तथा जो लोग इसके हकदार हैं उनको बढ़िया तरीके से पेंशन देनी चाहिये ताकि उनको धक्के खाने के लिये बाध्य न होना पड़े।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, वैसे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने तो शुरू में ही बुजुर्गों के सम्मान में सम्मान राशि 500 से बढ़ाकर राशि 700 रुपये की थी। उसमें कुछेक दिक्कतें सामने आई। मंत्री महोदया अखबारों के माध्यम से भी इस बारे में बात करती हैं । हम लोग गांव में ही रहते हैं इसलिए मैं 100 % गांव के बीच की बात आपके समक्ष रखना चाहती हूं। जो बैंक के माध्यम से पेंशन की बात थी वह गलत साबित हुई है। बुजुर्गों से बैंकों में नही जाया जाता, वे हारकर कहते हैं कि पेंशन मिले तो मिले न मिले तो न मिले, धक्के खाने नहीं जायेंगे। बैंक के कर्मचारी पेंशन घर देने आएंगे यह बात भी पूरी तरह से विफल रही है। जैसा मेरे माननीय साथी ने बात कही है कि पिछले 6-7 महीने से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली है तो जो यह पैंशन नहीं मिली है उस पेंशन को न दिये जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, यदि नहीं की जा रही है तो क्यों नहीं की जा रही है ? और कब तक यह पैंशन उन बुजुर्गों को मिल जाएगी ? मेरा सुझाव यह है कि बुढ़ापा पेंशन सरपंचों के माध्यम से ही बांटी जाती रही थी इसलिए अगर भविष्य में भी उनके हाथों से ही बांटी जाए तो ही अच्छा होगा। हालांकि ऐसे भी केसिज सामने आए हैं कि कई बार सरंपच भी पेंशन का मिसयूज करते हैं। जो लोक एक्सपायर हो जाते हैं कुछ समय तक उनके नाम की पेंशन वे अपने पास रख लेते हैं। सरकार को इस तरह के केसिज की भी निगरानी रखनी चाहिए लेकिन फिर भी यह पेंशन सरपंचों के माध्यम से ही दी जानी चाहिए ताकि वे बुजुर्गों को उनके घर यह सम्मान राशि देकर आएं। यह मेरा सुझाव है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, 1992 में भी इस पेंशन पर बहुत सी पाबंदी लगाई गई थी, ताकि वृद्धावस्था पेंशन को काट दिया जाए। जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में पढ़कर सुनाया। 1992 में जो पाबंदियां लगाई गई थीं, उन सबको 2001 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, हटा दिया गया था। सारी टर्म्ज एंड कंडीशंज हटाकर वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में इसे नोटिफाई कर दिया गया। उसमें भी उन्होंने 50 हजार इन्कम की कंडीशन हो या 2 लाख की हो, सब हटा दी थी। पहले जैसे कई बार कटु अनुभव इस मामले में हुए, वह इस बार भी हुए होंगे। इनके समक्ष पेंशन को बांटने की समस्या रही और उसको देखते हुए पहले पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन मैनुअली कर दिया फिर बैंकों के माध्यम से कर दिया बहुत से बुजुर्गों ने तो यह भी कहा कि अंगूठे और पंजों के निशान तो अपराधियों के लगवाए जाते हैं, हमारे क्यों लगवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री राम पाल माजरा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बुढ़ापा दो तरह का नहीं होता। बुढ़ापा एक ही तरह का होता है चाहे वह 60 साल का बुजुर्ग हो या 70 साल का हो। एक को पेंशन 500 रुपये दी जाती है और दूसरें को 700 रुपये दी जाती है। 60 साल वाले को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और 70 साल की आयु वाले बुजुर्ग को 700 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, क्या सरकार का इस वृद्धावस्था सम्मान पेंशन को बराबर करने का कोई विचार है। सर इसके अलावा जो एक परख कमेटी बनाई है उसमें स्क्रीनिंग की जाती है तो कई लोग मौके पर नहीं मिलते। डाक्टर और आफीसर्ज को ये क्लीयर कट आर्डर दे रखे हैं कि उनका नाम उस लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाए। पेंशन की परख की दोबारा से निगरानी की जा रही है। मैंने ये दो प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, ओल्ड ऐज पेंशन के बारे में हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने और पूरे सदन ने बहुत ज्यादा चिन्ता व्यक्त की है। ओल्ड ऐज सम्मान पेंशन के लिए बुजुर्गों का कोई अपमान न हो यही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास रहा है। बुजुर्गों के मान-सम्मान को बरकरार रखते हुए हरियाणा प्रदेश ने ऐसी प्रणाली शुरू की है जिसको बैंकों के माध्यम से देने का प्रयास किया है। जैसा कि हमारी सम्मानित सदस्या बहन अनिता जी ने एक बात कही वह बिल्कुल ठीक है कि गांवों और शहरों में बुजुर्गों को पेंशन सही समय पर न मिलने की वजह से बहुत सी दिक्कतें हरियाणा में आई हैं जिसके कारण हरियाणा में रोड जाम हुए लेकिन सरकार ने बैंकों में जो सेविंग्ज अकाउंट खोले हैं और बुजुर्गों को जो हम मैन्युअल पेंशन दे रहे हैं उसके बावजूद जो हमने सेविंग्ज अकाउंट खोले हैं वह एक ऐतिहासिक कदम सरकार का रहा है। हर बुजुर्ग के नाम पर सेविंग्ज अकाउंट खोल दिये गये। अब वे अपनी पेंशन उस खाते में नहीं डलवाना चाह रहे या जो भी कारण है इसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस समय सरकार मैन्युअल पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। जिन-जिन जिलों में इस प्रकार की दिक्कत आई वहीं पर मैन्युअल पेंशन को शुरू किया है।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। तभी तो आप दोबारा से शुरू कर रहे हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बैंकों की बात है कई गांवों में बैंक भी नहीं हैं। कई-कई गांवों के बाद बैंक नजर आता है। इसलिए यह बैंक सिस्टम बिल्कुल गलत है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Let the Hon'ble Minister reply please.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं रामपाल माजरा जी से कहना चाहूंगा कि पहले मंत्री जी का जवाब सुन लें उसके बाद अगर किसी बात की जिज्ञासा रह जाए तो वे उस बात को बाद में बता सकते हैं । (विघ्न)

Mr. Speaker : Majra Ji, I will ask you to speak again but let complete her reply (विघ्न) माजरा जी पहले मिनिस्टर को रिप्लाई तो देने दें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो कालिंग अटैंशन मोशन आया है उसके लिए सभी सदस्यों को बहुत चिन्ता है। इसके लिए बहुत बढ़िया रिप्लाई सदन के पटल पर रखा गया है। जिसमें बहुत सारी क्यूरिज हैं। एक तो सैल्फ अटैस्टेशन, दूसरा ऐज का सैल्फ अटैस्टेशन और तीसरा गांव के बैंकों में किसी बुजुर्ग को जाना नहीं है बल्कि बैंकों के कॉरसपौंडैंट उनको घर आकर पेंशन देंगे इसमें दिक्कतें थोड़ी जरूर आई हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, let her to complete the reply please.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, केवल दस मिनट का समय लगेगा मैं इस बारे में क्लैरीफिकेशन जरूर देना चाहूंगी कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन के बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है कि कितने से कितना हमने कर दिया है। कुछ नये लाभार्थियों की पहचान के लिए हमने जो सिम्पलीफिकेशन किया है या ऐसे कुछ गलत पेंशनर्स करीब सात प्रतिशत जो 30 लाख के लगभग थे जिन्होंने अपने खाते नहीं खुलवाये या जो डैथ केसिज थे इसको माननीय उच्च न्यायालय भी मॉनीटर कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी शिकायतें आई कि डैथ केसिज में भी पेंशन जाती रही है चाहे उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लैवल के अधिकारी दोषी थे या सरपंच दोषी थे या म्युनिसिपल काउंसलर दोषी थे उन सबके खिलाफ कार्यवाही की गई। उनके खिलाफ केस तक रजिस्टर करवाये गये क्योंकि इस तरह की समस्या बार-बार आ रही थी कि पेंशन का गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको देखते हुए इस योजना में पारदर्शिता लाने और इस योजना को जन साधारण की पहुंच में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नये लाभार्थियों की सत्त प्रक्रिया कंटीनुअस पहचान-पत्र के लिए हमने बहुत उपाय किए। पात्रता शर्तों को आसान करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से समझा कर आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप खण्ड विकास अधिकारी के पास और शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी में म्यूनिसिपल कमेटी के सचिव के पास और नगर निगमों में नगर निगम के सचिव के पास अपने फार्म प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी कोई टीम वहां पर सर्वे के लिए नहीं जाएगी। इस आवेदन में आप स्वयं एक सिम्पल फार्म को लेने के बाद जब भी आप 60 साल के हो जायेंगे तब आप उस फार्म को भरकर हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में या ब्लॉक डिवल्पमैंट आफिसर के दफ्तर में जमा करवायेंगे। हमारे जिले के डी.एस.डब्ल्यू. हैं उनके पास यह फार्म जायेगा। जो व्यक्ति 60 साल का हो जायेगा तब स्वयं उसकी पेंशन शुरू हो जायेगी। हरियाणा में जितने भी हमारे आज की डेट में पेंशनर्स हैं जो अभी मौजूद हैं उन सबकों हमने बहुत ही ट्रान्सपेरेंसी करते हुए और बहुत ज्यादा पारदर्शिता बरतते हुए हमारी विभाग की जो वैबसाइट है www.Socialjustice.hry.gov.in.com यह पूरी की पूरी लिस्ट उस पर है। जिस व्यक्ति को अपने वार्ड की, गांव की, बुजुर्ग की जानकारी चाहिए वह उस पर ले सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक-आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम अपने प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं । (विघ्न) जो सिग्नेट्रीज हैं वही पूछ रहे हैं परन्तु हमारी बात का जवाब नहीं आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनें तो सही, जवाब आ रहा है। मंत्री जी बाद में अपनी सारी बात कहेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकार ने पूरी तरह पारदर्शिता बरतते हुए जो एज में छोटे थे या डैथ केसिज में गलत पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन काटने का प्रयास किया है ताकि गलत व्यक्तियों के हाथों में पेंशन न जाए। सरकार ने पेंशन वितरण के काम का सरलीकरण किया है। हमने कमेटीज का गठन भी किया है। हमने जिला लैवल पर भी यह कहा है कि कमेटीज का गठन किया गया है और अगर किसी को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत जिला अधिकारी या डी.सी. को जरूर दें ताकि इस सिस्टम का सरलीकरण किया जा सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये बुजुर्गों का अपनाम कर रहे हैं। मंत्री जी जो जवाब दे रही हैं वह ठीक नहीं है इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वॉक-आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is replying. (Noise & Interruption)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, सीधा जवाब नहीं दे रही हैं बल्कि गोल मोल जवाब आ रहा है इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य और शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य कालिंग अटैंशन मोशन पर मंत्री द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता हेतु आय सीमा निश्चित करने की उनकी दलील को स्वीकार न करने के विरोध में एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट कर गए)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भण)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बताना चाहूंगी कि जितने हमारे सम्मानित सदस्य उठकर गए हैं उनको हमने गलत लाभार्थियों की लिस्टें दिखाई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह वॉक-आउट करने का मसला नहीं है। यहां इस मामले पर हैल्दी डिस्कशन हो रही है। बैंक के माध्यम से पेंशन नहीं मिलनी चाहिए इस बारे में हम भी बोल रहे हैं तो फिर इस बात पर वॉक-आउट करना केवल नम्बर बनाने वाली बात है। What is the meaning of this ?

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आपकी बात ठीक है। यह वाक-आउट का विषय नहीं है। this is not a matter of walk out. (Noise & Interruption) ये वाक-आउट का विषय नहीं था। ये वॉक-आउट कर रहे हैं ये इनकी मर्जी है । (शोर एं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, आज ये इस चीज के खिलाफ हैं जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मात्र 300 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी और वह भी केवल एक महीना ही दी थी। 100, 200 और 300 रुपये बुजुर्गों को देकर उनका अपमान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इनके साथियों ने किया है। मार्च, 2005 में हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने 2005 में 300 रुपये पेंशन को 500 रुपये करने का काम किया। फिर 500 के बाद उसको 550 किया गया और हमारे जो लाभार्थी 1999 से लगातार 10 वर्षों से पेंशन ले रहे थे उनको 700 रुपये पेंशन देने का काम इस सरकार ने किया है। इसके अलावा एक मुश्त 501 रुपये की राशि शाल के लिए या डोगा और पगड़ी के लिए सरकार ने सम्मान स्वरूप देने का काम किया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इंडियन नेशनल लोकदल का वॉक-आउट टोटल है या पार्शियल है क्योंकि इनके 5 सदस्य अंदर बैठे हैं और बाकी के सदस्य वॉक-आउट किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इनकी पार्टी के लोग इनकी बात को नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : ये इस बात को जानते हैं कि यह वॉक-आउट करने का विषय नहीं था, लेकिन खबर कैसे बनेगी ? ये वॉक-आउट करके केवल खबर बनाना चाहते हैं। दांगी साहब ने भी ठीक ही कहा है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता होना चाहिए कि ये क्यों वॉक-आउट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पता नहीं ये किस बात पर वॉक-आउट करके गए हैं। जो वॉक-आउट करके गए हैं उनको ही नहीं पता तो मुझे क्या पता कि ये वॉक-आउट क्यों करके गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य दांगी साहब ने भी कहा कि यह सबके लिए चिन्ता का विषय है। सरकार को भी इस बारे में चिन्ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्वयं बैंकों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और जिले के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की। सभी फाइनैंशियल कमीशनर्ज, प्रिंसीपल सैक्रेटरीज की जिलावार ड्यूटी यह देखने के लिए लगाई है कि वे जाकर देखें कि बैंकों के माध्यम से पेंशन देने में क्या दिक्कत आ रही है। हमने आज इस सदन के पटल पर इस बात को माना है क्योंकि बैंकों के माध्यम से पेंशन देने में हमें भी दिक्कत आ रही थी इस वजह से हमने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों के खाते में पेंशन जमा करवाने की पूरी कोशिश की है। हमने म्यूनिसिपल कमेटीज के खाते में पेंशन जमा करवाने की कोशिश की है ताकि गांव के गांव में ही हमारे बुजुर्गों को सम्मान पेंशन विधिवत तरीके से मिल सके। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों ने खुद अपने लोगों को सड़कों पर जाम लगाकर बिठाया हुआ है। इनके पास सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं है और केवल यही कारण आज इनके वॉक-आउट करने का है।

12.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने क्लैरीफाई कर दिया है कि विपक्ष के साथी नॉन ईश्यू को ईश्यू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। I again repeat as my learned Minister has said. (Interruption) Sir, they have staged a walk-out. Why are they standing there? Why should they intervene ? (Interruption) Minister has already clarified that there is no requirement of certificate of income. As you fill up your name, father's name, address, income and profession in the application form, you can say what is your income. What is wrong with that ? I ask myself and I answer that there is nothing wrong. विपक्ष के साथी बिल्कुल मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। ये लोग वैचारिक और मानसिक तौर पर भ्रमित हैं। इनकी पार्टी की पूरी विचारधारा भ्रमित है इसलिए मेरे साथी भी भ्रमित हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन के लिए कोई इन्कम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन फार्म है उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रैस, आयु लिखनी होती है और उसमें जो इन्कम कंडीडेट की होती है वह लिखनी होती है। किसी तरह का इन्कम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। मेरी विपक्ष के साथियों से प्रार्थना है कि वे नॉन ईश्यू को ईश्यू न बनायें। इससे हरियाणा के लोग भ्रमित नहीं होंगे। इसका जवाब जनता ने इन्हें रतिया में दिया, हिसार चुनाव में दिया, 2005 के चुनावों में दिया और 2009 के चुनावों में दिया। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, *****

Mr. Speaker : Without my permission nothing is to be recorded (Interruption) विपक्ष के सदस्य जो वॉक-आउट करके आ गये इस पर एक बड़ा उम्दा शेयर है जो आपको समझ में आयेगा :--

क्या खूब पर्दा था, चिलमन से सटे बैठे थे,

साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं । (हंसी)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल सैशन की सीटिंग 6.30 बजे समाप्त होनी थी लेकिन आपने 6.00 बजे ही सीटिंग का समय बढ़ाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, रूल्ज एण्ड प्रोसीजर के मुताबिक भी सैशन की जो सीटिंग दोपहर बाद शुरू होगी वह 6.30 बजे समाप्त होती है लेकिन आपने 6.00 बजे ही सीटिंग का समय बढ़ाना शुरू कर दिया।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, आपको तो पूरी स्पीच दिलवाई गई थी।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, कल आपने ही मुझे कन्टीन्यू करने के लिए कहा था उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

सरकारी संकल्प

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an official resolution.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I beg to move—

> This House places on record its appreciation and congratulates the Indian Hockey Team for its excellent performance and victory in qualifying Games for London Olympics. This House particularly places on record its appreciation of two Haryana Players Sandeep Singh and Sardara Singh for their outstanding individual performance and for their team spirit. This House also places on record its appreciation for the laudable awards and encouragement announced by the Government of Haryana for the entire Indian Hockey Team and particularly for the two players from Haryana.

I also want to bring to the notice of this House with your permission that the Government of Haryana and the Hon'ble Chief Minister of Haryana, Ch. Bhupinder Singh Hooda, has very generously announced immense encouragement for the Indian Team and they are like this. दो लाख 51 हजार रुपये चाहे वे किसी प्रांत के भी खिलाड़ी हों, पूरे हिन्दुस्तान की हॉकी टीम के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एनाउंस किये हैं। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) इसके अतिरिक्त 11-11 लाख रुपये संदीप सिंह और सरदारा सिंह के लिए अनाउंस किए हैं जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी हाकी टीम के स्टार प्लेयर हैं। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) इसके अतिरिक्त जो क्वालीफाई मैच फ्रांस के साथ हमारे देश के खिलाड़ियों ने 8-1 के अंतर से जीता था उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने जितने भी गोल किए उनके हर गोल पर 5 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने एनाउंस किए हैं। उसमें संदीप सिंह ने 8 में से 5 गोल अकेले ने किए जिस पर हम सभी को फख्र है। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपये प्रति गोल यानी 25 लाख रुपये संदीप सिंह को देने एनाउंस किए हैं। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) हरियाणा के एक बेटे ने टोटल आठ गोल में से पांच गोल बनाये। इस प्रकार से 25 लाख रुपये की राशि उसको हरियाणा सरकार केवल गोल्ज़ करने के लिए देगी। इसके अलावा irrespective of the State that you belong to फाईनल क्वालीफाईंग गेम्ज़ तक जितने भी गेम्ज़ हुए उस में जिस खिलाड़ी ने भी जितने गोल बनाये उसके हिसाब से हर गोल पर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार ने एक लाख रुपये की राशि सभी खिलाड़ियों को देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से केवल संदीप सिंह को 47 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई क्योंकि उसने पांच गोल क्वालीफाईंग में बनाये, 11 गोल उसने और बनाये और 11 लाख उसको हरियाणा का खिलाड़ी होने के नाते मिले इस प्रकार से 47 लाख रुपये की राशि अकेले हमारे स्टार प्लेयर श्री संदीप सिंह को मिली है। इसी प्रकार

सरदारा सिंह जी को भी दिये, एशियन गेम्ज़ में भी हरियाणा की सरकार ने 30 लाख रुपये की राशि इण्डियन हाकी टीम को दी थी और 10 लाख रुपये की राशि हमारे खिलाड़ी श्री सरदारा सिंह जी को भी दी थी। आज अगर इस देश का तिरंगा झण्डा जिस पर हम सबको नाज़ है, जो आपके सामने यहां पर है आज जब वह किसी प्रतिसपर्धा में ऊपर जाता है तो हर बार उसके नीचे जो खिलाड़ी खड़ा होता है वह हरियाणा की माटी का सपूत होता है। ये पूरा हाउस उनको बधाई देता है।

Mr. Speaker : Shri Ajay Singh Chautala Ji, are you second it ?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : जी हां सर, हम इसका समर्थन करते हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : सर, जिस तरह से आप कहेंगे हम उसी तरह से बोलेंगे। न तो हम हाउस की वैल में जाना चाहते हैं और न ही वॉक-आउट करना चाहते हैं लेकिन हमें बोलने का मौका दिया जाये। सर, ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष केवल सरकार की आलोचना करने के परपज़ से ही हाउस में आता है। सरकार जो अच्छे काम करती है हम उसकी सराहना भी करते हैं। सरकार ने हाकी के पलेयर्ज़ को इतने अवार्डस दिये हैं चाहे संदीप सिंह को दिये और चाहे सरदारा सिंह को दिये और चाहे वे हर प्लेयर को दिये और चाहे सारी टीम को दिये मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं यह प्रशंसा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी नॉन क्रिकेट गेम्ज़ हैं वे सारी दबली जा रही हैं। क्रिकेट का जलवा इतना ज्यादा हो गया है कि बाकी की गेम्ज़ का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। हरियाणा सरकार ने यह एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो खिलाड़ियों को ईनाम देने की बात कही है। जो ध्यानचंद स्टेडियम में खेल हुए और उन खेलों में हमारी हाकी की टीम ने लन्दन ओलम्पिक के लिये क्वालीफाई किया। सर, जब मैदान में हमारा तिरंगा लहराता है तो चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को इनाम देकर एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी हाकी की महिला टीम थी चाहे वह रनर-अप ही क्यों न रही हो उनको भी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ इनाम दिया ही जाना चाहिए। इण्डियन हाकी टीम में शाहाबाद मारकण्डा की लड़कियां हैं जहां पर हमने अपनी सरकार के समय एस्ट्रोटफ भी बनाकर दिया था जो कि पहले अम्बाला छावनी के लिए मंजूर हुआ था लेकिन शाहाबाद की लड़कियों की गेम को देखते हुए मैंने अम्बाला कैंट से सैक्रीफाईस करके शाहाबाद के लिए एग्री किया जिसके लिए श्री ओम प्रकार चौटाला जी ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने उनको कहा कि आप उसे शाहाबाद में बना दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस रनर-अप टीम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनको भी कुछ न कुछ दिया ही जाना चाहिए क्योंकि हाकी में बहुत ज्यादा पोटैंशियल है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री विज ने सुझाव दिया है यह बिल्कुल सही है हम इनसे पहले ही महिला हाकी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने के बारे में विचार कर रहे हैं। हम उनको मान-सम्मान देने के लिए कोई न कोई इनाम जरूर देंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : विज जी, क्या आप लीडर ऑफ दी हाउस के इतना कहने के बाद भी बोलना चाहते हैं ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जितनी भी नॉन क्रिकेट गेम्ज़ हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कोई पालिसी बनाई है। आपने भी

[श्री अनिल विज]

यह कहा था कि उस पालिसी के बारे में बताया जाये। मैं भी यही चाहता हूं कि सभी नॉन-क्रिकेट गेम्ज़ को प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए। जिस प्रकार से इस गेम में कितने पैनल्टी कार्नर लगाये गये। वे बड़ी खेल भावना से खेले। मैं उनकी खेल भावना को सैल्यूट करना चाहता हूं। अगर वही खेल भावना हम यहां भी अपना लें तो प्रदेश की बहुत तरक्की होगी। मैं जब भी कोई पैनल्टी स्ट्रोक लगाने की कोशिश करता हूं तो आप मुझे रोक देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is irrelevant. You are political and your resolution like this is political.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House places on record its appreciation and congratulates the Indian Hockey Team for its excellent performance and victory in qualifying games for Landon Olympics, 2012. This House particularly places on record its appreciation of two Haryana players Sandeep Singh and Sardara Singh for their outstanding individual performance and for their team spirit. This House also places on record its appreciation for the laudable awards and encouragement announced by Government of Haryana for the entire Indian Hockey Team and particularly for the two players from Haryana.

Mr. Speaker : Question is—

That this House places on record its appreciation and congratulates the Indian Hockey Team for its excellent performance and victory in qualifying games for Landon Olympics, 2012. This House particularly places on record its appreciation of two Haryana players Sandeep Singh and Sardara Singh for their outstanding individual performance and for their team spirit. This House also places on record its appreciation for the laudable awards and encouragement announced by Government of Haryana for the entire Indian Hockey Team and particularly for the two players from Haryana.

I want to add here that the Leader of the House. The Chief Minister has given an assurance that the runners up team will also be considered for award and this is already in the consideration of the Government of Haryana. Now on this resolution does this House unanimously resolve this ?

Voices : Yes Sir.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The motion is carried and the congratulations and appreciations of this House will be conveyed to the Indian Hockey Team and the federation. Thank You.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा-

बाबा भीम साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण बारे

Mr. Speaker : Hon'ble Members, immediately after rising of the Assembly today, we will be unveiling the portrait of Baba Bhim Sahib Ambedkar Ji at the back of the Chair. So, you are requested to be present here at the point in time.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on the Govenor's will resume. Col. Raghbir Singh may continue.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी स्पीच बीच में बची हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपकी स्पीच खत्म हो गई थी। कल आप 35 मिनट बोले थे। आपको बजट पर दुबारा बुलवायेंगे।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी को पिंच हो और विघ्न पैदा हो।

Mr. Speaker : Alright, you will speak on Budget.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ******* (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत बढ़िया लैजिस्लेटर हैं और मैं आपका कंट्रीब्यूशन बजट पर लेना चाहूंगा । O.K. I allow you to speak for five minutes only.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पशुपालन पर जोर दिया गया है। यह ठीक है कि दूध की उपलब्धता का जो टारगेट था वह हासिल कर लिया है लेकिन कैग की रिपोर्ट यह कहती है कि 2008 से लेकर 2011 तक पशुपालन से संबंधित कोई भी संस्थान नहीं खोला गया। प्रदेश में जो पशु जनगणना हुई है उसके मुताबिक 82 हजार मुर्राह नस्ल की भैंसें कम हुई हैं। इसके अलावा खच्चर, घोड़े और ऊंट आधे रह गये हैं। इतना ही नहीं 400 पंचायतों को एक करोड़ रुपये के कटड़े दिये गये थे उनका कोई रिकार्ड नहीं है कि वे दिये भी गये थे या नहीं। यह सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं यह तो मैं कैग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से निष्पादन अभिकरणों में 20.47 करोड़ रुपये के व्यय का कोई विवरण नहीं है। 35.20 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिये गये । इसी प्रकार से 1188 लाभ भोगियों को बीमा पॉलिसी के तहत जो बीमा राशि मिलनी थी उनमें से 281 लाभ भोगियों को वह राशि नहीं मिली। 1100 दुग्ध डेरियां बनाई जानी थी जिनमें से केवल 445 ही बन पाई हैं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से चार सितारा होटलों का तो वैट कम कर दिया और उनकी फीस कम कर दी है। स्पीकर सर, यह बात सारा प्रदेश जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था जिसमें सभी नदियों को जोड़ने की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सतलुज, यमुना लिंग नहर बनाने की कुछ आशा बनती है क्योंकि न तो कोर्ट में कोई केस पैंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इस नहर को बनाने के लिए भारत सरकार को आदेश दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, on a point of order. सर, पिछले सात साल से माननीय सदस्य की यही स्पीच हम सुनते आ रहे हैं। हम इनको हर बार समझाते हैं। Sir, there is a constitutional reference made by Government of India at the asking of Government of Haryana pending before a Constitutional Bench of the Supreme Court of India. If constitutional reference is not pendency of the case then execution application

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Shri Randeep Singh Surjewala]

filed by Government of Haryana is also pending. ये सरासर असत्य बोल रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, दो केसिज पैंडिंग हैं। इनको कभी पूरी बात की जानकारी होती नहीं, कभी अपने पूरे तथ्य लेकर आते नहीं। हर बार मैं इस विषय के बारे में समझाता हूं, उसके बाद हर बार उसी विवाद को लेकर कोई नया सदस्य खड़ा हो जाता है। सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध किया । ये विपक्ष के वही लोग हैं जिन्होंने राजीव-लौंगोवाल एकॉर्ड ने जब हरियाणा स्टेट को पानी देने की बात कही तो इन लोगों ने काले झंडे दिखाए। उसको साईमन कमीशन की संज्ञा दी। अब इन्हें इस बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामपाल माजरा : सर, बारिश ज्यादा होने के कारण बाढ़ आ गई। उसके बाद कुछ सिविल वर्क्स होने थे। सर, यमुनानगर का मैंने जिक्र किया लेकिन सिंचाई मंत्री जी ने यह कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ई.आई.सी. से इस बारे में टेलीफोन पर बात की और उनसे पूछा कि वहां पर जो ब्लॉक बनने थे उनके बारे में श्री राम लैबोरेट्रीज से रिपोर्ट मंगवाई थी कि क्या इन ब्लॉक में सीमेंट लगाई गई है या नहीं तो इस बारे में क्या रिपोर्ट आई है ? उन्होंने कहा कि नहीं, श्री अनूप सिंह और श्री अनिल कुमार अग्रवाल, चीफ इंजीनियर्स की इस बारे में एक कमेटी बनाई है जो इस बात के लिए जांच करेगी कि बाढ़ रिलीफ के लिए जो पैसा दिया गया है वह पैसा किस प्रकार से यूटीलाईज किया गया है उस पैसे का सही उपयोग हुआ है या नहीं। क्योंकि वहां पर यह पैसा ठीक ढंग से खर्च नहीं किया गया और इस कारण से एक बहुत बड़ा घोटाला वहां पर हुआ है। सर, इसी प्रकार से हमारे कैथल जिले में भी बाढ़ आई थी जिसके कारण हांसी बुटाना नहर आर.डी. 52000 से लेकर आर.डी. 55000 के बीच में 175 से लेकर 200 फुट लम्बी दूरी की नहर टूट गई थी। जिसकी मरम्मत पर पौने दो करोड़ रुपये खर्च किए गये। इसकी मरम्मत पर पैसा खर्च करते समय नेगोसिएशन करने में ही बहुत भारी घपला किया गया जिसके कारण इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। इतना ही नहीं स्पीकर सर, पोकलिन नाम की मशीन ली गई और इस मशीन को 1800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हायर किया गया जबकि इसका मार्किट रेट केवल मात्र 1300 रुपये प्रति घण्टा था और उसके समय में भी हेरा-फेरी की गई। स्पीकर सर, इसी प्रकार से कैग की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि स्टील की गलत थोक विक्रय मूल्य सूची होने के कारण ठेकेदार को 62 लाख 25 हजार रुपये अधिक भुगतान कर दिया गया। हांसी बुटाना नहर के ऊपर साईफन बनाने के लिए 5.35 करोड़ रुपये की हानि हुई है। सर, कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फतेहाबाद में रिचार्ज बोरवैल पर 89 लाख रुपये खर्च किये गये और वे बोरवैल चले भी नहीं और यह सारा पैसा व्यर्थ में चला गया। इसी तरह से जल-आपूर्ति में टर्म्ज इन्गेजमैंट के आधार पर चार-पांच हजार लोगों को काम पर लगा दिया और 2244 पार्ट टाईम पम्प अटैंडैंट लगाए गए। 737 माली लगा दिए स्पीकर सर, इन नियुक्तियों के लिए कोई ऐडवर्टाइजमैंट नहीं की गई कि वे कान्ट्रैक्ट पर लगाये गये हैं। उनको घर से बुलाया गया और काम पर लगा दिया और यहीं से सूधी भेज दी कि इतने आदमी लगा दिए गये हैं। सर, इतना ही नहीं आज प्रदेश में किस प्रकार से हजारों अवैध कालोनियां पनप रही हैं। पहले भी यह सुनने में आ रहा था कि 1600 कालोनियों को रेगुलराईज करने के लिए एक रेजोलूशन आ रहा है। उस रेजोलूशन को लाने से पहले ही हर शहर में सैंकड़ों कालोनियां काट दी गई हैं। सर, हरियाणा में Regulation of Property Dealers and Consultants Act, 2008 है। इस एक्ट के तहत कोई नाम मात्र के लोग ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि इसकी इम्पलीमैंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रही है। सर, इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं इन्हीं के इशारों पर ही ये कालोनियां काटी जाती हैं अन्यथा तो कोई किसी को गिव एण्ड टेक करने नहीं देता। सर, हरियाणा प्रदेश में ये कालोनियां इतने लार्ज स्केल

पर काटी गई हैं और ऐसा करके गरीब लोगों को फंसाने का काम किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की कालोनियां काटने पर बैन लगना चाहिए।

Mr. Speaker : Majra Ji, your time is over, please resume your seat.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय ****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded without my permission.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय ****

Mr. Speaker : Yes, Col. Reghbir Singh Ji, I call upon you to speak.

कर्नल रघबीर सिंह (बाढड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया उसके मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो बिजली विभाग ऐसा विभाग है जिससे हर एक विभाग जुड़ा हुआ है। हर एक सदस्य ने बिजली विभाग के बारे में बात की है क्योंकि बिजली विभाग एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। मैं समझता हूं कि आज बिजली विभाग ट्राईल एंड एरर मैथड पर चल रहा है। आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले मौजूदा सरकार एक स्कीम लेकर आई थी जोकि एच.वी.डी.एस. सिस्टम यानी हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अन्दर सरकार ने करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिये। जब इन्होंने लूना माजरा के अन्दर ट्रायल के ऊपर 255 ट्रांसफोर्मर लगाये जिनकी कॉस्ट तीन करोड़ इक्सठ लाख थी। उससे पहले वहां पर लाइन लॉस 60 प्रतिशत चल रहा था और उसके बाद में 72 प्रतिशत हो गया। आज भी उसी सर्कल के अन्दर 68 प्रतिशत लॉस चल रहा है। इस ट्रायल एरर मैथड की वजह से आज बिजली विभाग की दोनों कम्पनियों का घाटा 7000 करोड़ के करीब चल रहा है जबकि इन दोनों कम्पनियों ने 15000 करोड़ से भी ज्यादा लोन लिया हुआ है जिसका इंट्रस्ट देने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है यह स्थिति इनकी आज बनी हुई है। लाईन लौसेज तो ये दिखाते ही हैं बड़ी सुविधा के बाद जब बिजली विभाग कहता है 20 परसैंट है, 22 परसैंट है, 25 परसैंट है लेकिन इनके यू.एच. के अन्दर 11 के.वी. के 208 ऐसे फीडर हैं जिनके अन्दर लाईन लौसेज 50 प्रतिशत से भी ज्यादा चल रहा है और 400 फीडरों में 30 से 50 परसैंट लाईन लौसेज चल रहा है। आज की लाईन लौसेज की स्थिति ऐसी है कि कमीशन कह रहा है कि उत्तर हरियाणा के अन्दर 34 परसैंट लाईन लौसेज चल रहा है और जबकि दक्षिणी हरियाणा के अन्दर 25 परसैंट लाईन लौसेज चल रहा है जोकि चिन्ता का विषय है। यमुनानगर थर्मल प्लांट के अन्दर इन्होंने चाईनीज मशीनरी लगाई है उसके अन्दर एक यूनिट बन्द पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी झज्जर के अन्दर जो 1200 मैगावाट का प्लांट लगाया गया है उसमें फिर इन्होंने चाईनीज मशीनरी का इस्तेमाल किया है। नई मशीनरी होते हुए तो पी.एल.एफ. 90 परसैंट होना चाहिए लेकिन आज अफसोस की बात है कि 40 परसैंट पर वह प्लांट चल रहा है आज ऐसी हालत इस बिजली विभाग की बनी हुई है। मुझे नहीं पता कि इस बिजली विभाग का क्या होगा लेकिन सरकार को भी और बिजली मंत्री को भी इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए कि हम किस तरीके से इस घाटे को पूरा कर सकेंगे, किस तरह से योजना बनाये कि इस लाईन लौसेज को कम किया जा सके। यह जो ट्रायल इन एरर मैथड चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। एच.वी.डी.एस. के ट्रायल मैथड पर हजारों रुपये खर्च हो चुके हैं और आज काम बन्द कर दिया गया। आज हर महकमा चाहे वो एग्रीकल्चर का हो वह भी बिजली विभाग पर निर्भर है। सन् 2000 के अन्दर 70 हजार ट्यूबवैल कनैक्शन पैंडिंग पड़े थे लेकिन साल, छह महीने

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं की गई।

[कर्नल रघबीर सिंह]

के अन्दर पूरे ट्यूबवैल कनैक्शन दे दिये गये थे। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उसको ठेका प्रथा के अधीन कर दिया गया है। स्पीकर सर, आज किसान को एक ट्यूबवैल कनैक्शन लेने के लिए डेढ़ से दो लाख रुपये देने पड़ते हैं क्योंकि पहले तो 7 हजार रुपये प्रति पोल के देने पड़ते थे लेकिन अब तो इन्होंने एक सर्कुलर नं. D. 12/2011 दिनांक 16-5-2011 को पेश कर दिया है जिसके तहत एक किसान को ट्यूबवैल कनैक्शन लेने के लिए ट्रांसफोर्मर का पैसा भी देना पड़ेगा तथा पोल के स्पैन के पैसे भी देने पड़ेंगे। इसके मुताबिक यदि किसान को एक पोल का कनैक्शन लेना है तो उस पर भी एक लाख रुपये खर्चा आता है जोकि उसे ठेकेदार को देना पड़ता है, यदि उसको 6 से 7 पोल का ट्यूबवैल कनैक्शन लेना है तो 2 लाख रुपये खर्च हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हाउस में विराजमान हैं इन्होंने झोझू में एक जन सभा में घोषणा की चूंकि जमींदार के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है इसलिए जो स्पैन के 7 हाजर रुपये हैं इनका आधा सरकार देगी लेकिन उस घोषणा को आज तक लागू नहीं किया गया और उसे लागू करने की बजाय एक सर्कुलर इशु कर दिया कि ट्रांसफार्मर के पैसे जमींदार देगा। स्पीकर सर, सरकार के ऐसे फैसलों से आज जमींदार की कमर टूटती जा रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि 2011 का वह सर्कुलर वापस लिया जाए। इसके अलावा थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की स्थिति ऐसी है कि कोयले की कमी पड़ती है तो पानीपत से कोयला भेजते हैं। आज के दिन पानीपत से कोयले का रैक भेजने पर 12 लाख रुपये का खर्च आ रहा है इसीलिए विभाग का घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं एक वाक्या भी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार मैं पंचकूला सिविल अस्पताल में गया हुआ था वहां मुझे उस समय की स्वास्थ्य मंत्री मिली, उन्होंने कहा कि कर्नल साहब जब आप चेयरमैन थे तो बिजली अच्छी मिलती थी, अब अच्छी बिजली क्यों नहीं मिलती, इसका कारण क्या है। तो मैंने कहा कि आपकी सरकार है आपको ही इस बारे में पता होगा। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, मैंने कहा कि आपका प्रशासन पर कन्ट्रोल नहीं है और दूसरे आपका सिस्टम ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज सिस्टम ठीक करने की जरूरत है अगर सिस्टम को ठीक न किया गया तो बिजली निगम टूटने के कगार पर खड़ा है। बिजली विभाग पर ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं इरीगेशन के बारे में बात करना चाहूंगा और कुछ बातें अपने हल्के के बारे में पूछना चाहूंगा। नहरों के बारे में हर आदमी कहता है कि हमारे यहां की नहरों में पानी नहीं आया। मुझे नहीं पता चल रहा कि नहरें क्यों बनाई गई थीं। बधवाना माइनर 20 साल पहले बनाई गई थी लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया है। एक तो मैं यह चाहूंगा कि जिसने यह नहर बनाई थी उस अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। उस पर हुए खर्च की रिकवरी किससे करेंगे ? इस मामले की इंक्वायरी भी करवाई जाए। सिस्टम के अपग्रेडेशन की भी जरूरत है। पॉवर हाउसिज को भी अपग्रेड किया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्नल साहब, आप कृपया एक मिनट में कंक्लूड करें।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की सड़कों के निर्माण के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने दो साल पहले इस हाउस में 15 सड़कों का जिक्र किया था इनमें चांगरोड़ से ढाणी छिल्लर, मौडी से खेड़ी सनसनवाल, लाड से नान्धा, बलकारा से ढाणी छिल्लू, मांडी पिरानू से जेवली, बिन्दरावन से पिचौण, हड़ौदी से उमरदास, हड़ौदा से मांडी हरिया, मांढी हरिया से पिचौणा कलां, नौरंगवास से ढाणी गुज्जर, हुई से जेवली, गोपी से कारी रूपा, लाड़ से ढाणी नान्धा, कलियाणा से पीर बाबा। इन 15 सड़कों के बारे में कहा था लेकिन इनमें से एक पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए 15 रोड्स की रिपेयर के लिए अनुरोध किया था एक तो दादरी से ढाणी फौगाट पातूवास, इसके लिए मुझे डी.ओ. भी मिला है लेकिन इन रोड्स पर भी रिपेयर का काम नहीं किया गया है।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दादरी से ढाणी फौगाट पातूवास ये सभी सड़कें मंजूर हो गई हैं और इन पर कल से काम भी शुरू हो गया है, इनका टैण्डर मंजूर हो गया है। इन सड़कों को मैंने अपनी लिस्ट में दिया था। ये सारी की सारी मंजूर हो गई हैं और काम भी शुरू हो गया है। कल ये मेरे साथ चलें तो मैं इनको मौके पर जाकर दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप इन्हें साथ ले जाकर दिखा आना। कर्नल साहब, आप एक मिनट में अपनी बात कनक्लूड करें।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने अपने हल्के में चकबंदी के लिए दो साल पहले सवाल लगाया था कि 15 गांवों में चकबंदी पूरी नहीं हुई है तो इन्होंने उस पर सदन में जवाब दिया था कि सन् 2011 तक उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा लेकिन चकबंदी का काम आज तक भी पूरा नहीं हुआ है इन गांवों के नाम लाड, रामबास, खोरड़ा, उमरवास, काकड़ौली, हट्टी जगरामबास, बेरला, भाईकलां खुर्द, पिचौपा खुर्द, बिन्द्रावन, लाडावास, गोकल, झोझू खुर्द, होडी व निहालगढ़ है। इनमें चकबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द कन्सोलिडेशन कराई जाए। आज गांवों में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में मैंने कुछ मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी।

Mr. Speaker : Col. Sahib, you have made a very good speech but your time is over. Come to the last point.

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भूतपूर्व सैनिकों की 5-6 मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थीं। उनमें पहली मांग यह थी कि मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए जो 14 प्रतिशत रिजर्वेशन है उसको बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए। हुडा में प्लॉट के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 8 प्रतिशत रिजर्वेशन है उसको बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाए, मैंने यह कहा था कि दूसरे राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स की पूरी तरह से छूट है उसको अपने राज्य में भी लागू किया जाए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने तो वित्त मंत्रालय कप्तान साहब को पूरा सौंप रखा है इसलिए आप कप्तान साहब को बतायें वहीं देंगे जो देना है। इस प्रकार से तो भूतपूर्व सैनिकों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वित्त मंत्रालय उस समय कप्तान साहब के पास था और आज चट्टा साहब के पास है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार न कहकर भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय न लेते हुये आपने मुझे बोलने को समय दिया इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं।

श्री जयतीर्थ (राई) : स्पीकर साहब, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दरअसल, हमारी सरकार की विकास और कल्याणकारी नीतियों की चारों तरफ से सराहना हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार ने पिछले सात सालों में जो अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र हों, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि संबंधी कोई भी क्षेत्र हो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी सरकार ने तरक्की न की हो। हरियाणा प्रान्त वर्ष 1966 में पंजाब से अलग हुआ था उस समय हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त था और पंजाब प्रान्त की पोजीशन हमारे प्रान्त से बहुत अच्छी थी। अभी पिछले इलैक्शन का समय चल रहा था उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने एक चुनाव सभा में बोलते हुए यह कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि आज पंजाब हरियाणा से विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने यह स्वयं माना है कि पंजाब हरियाणा से पीछे चला गया है और हरियाणा बहुत आगे है। (व्यवधान)

Mr. Speaker : Not to be recorded anything said like this.

श्री जयतीर्थ : स्पीकर साहब, वर्ष 2010-2011 में गेहूं उत्पादन में शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी सरकार को सर्वश्रेष्ठ कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है जिसमें एक करोड़ रुपये प्रशस्ति पत्र और ट्राफी इनाम में मिले हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं मैं उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं लैंड एक्विजीशन के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। इसके बारे में जो राज्यपाल महोदय ने चर्चा की है वह किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए देश में पहली बार नई भूमि अधिग्रहण नीति अप्रैल, 2000 में बनाई गई जोकि 5-5-2005 से लागू की गई **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय, चेयर पर पदासीन हुए)** और उसमें फ्लोर रेट 2005 में निर्धारित किया गया था उसको बढ़ाकर दोबारा से वर्ष 2007 में संशोधित किया गया। उस नीति को वर्ष 2010 में फिर से संशोधित किया गया और फ्लोर रेट को तीन जोन से बढ़ाकर पांच जोन में किया गया।

श्री मोहम्मद इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, इनके गांव में किसान धरने पर बैठे हैं। (विघ्न)

श्री जयतीर्थ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राई हल्का दिल्ली से शुरू होता है और उसके आगे स्पीकर साहब का हल्का आता है। मेरे हल्के में पिछली सरकार ने राई और जठेड़ी गांवों की जमीन यह कहकर एक्वायर की थी कि यहां एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाई जाएगी। किसानों की जमीन, सवा लाख, डेढ़ लाख और एक लाख 70 हजार रुपये के हिसाब से एक्वायर कर ली गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आने के बाद जो मंडी बनाने का प्रोग्राम था वह इन्होंने ड्रॉप कर दिया और वहीं जमीन उद्योगपतियों को प्लॉट काट-काट कर बेच दी गई। करोड़ों रुपये में वे प्लॉट बेचे गए। किसानों से यह कहकर जमीन छीन ली गई कि आपके यहां एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाई जाएगी और आज वहां इंडस्ट्रियल प्लॉट काटकर उद्योगपतियों को बेच दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि किसानों के साथ धोखा किया गया । (विघ्न)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जो बात कह रहे हैं इसके साथ-साथ यह तो बता दें कि वह कौन सी जमीन है तभी हम उसका जवाब देंगे। ये बार-बार गलतब्यानी देकर हाउस को गुमराह न करें। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के लिए माननीय सदस्य ने कितनी जमीन एक्वायर करवाई और उस जमीन के किसानों को क्या रेट दिए गए इसके बारे में भी बताएं।

श्री जय तीर्थ : उपाध्यक्ष महोदय, ये सुने तो सही, मैं बताउंगा । राई गांव में पिछली सरकार ने सवा लाख और डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन एक्वायर की थी राई और जठेड़ी गांव के आस-पास 8 गांवों की जमीन हमारी सरकार ने राजीव गांधी एजूकेशन सिटी बनाने के लिए एक्वायर की थी और किसानों को 45 लाख रुपये तक प्रति किले के हिसाब से रेट दिए गए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय किल्ले का क्या रेट था और आज किल्ले का क्या रेट है ये माननीय सदस्य कम्पैरेटिव स्टेटमैंट भी हाउस को दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयतीर्थ : उपाध्यक्ष महोदय, 45 लाख 15 हजार रुपये प्रति एकड़ का रेट किसान को दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) हर किसान को हुडा में रैजीडैंशियल या कमर्शियल प्लॉट और 33 साल तक रोयल्टी देने का काम किया गया।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जैसा माननीय सदस्य जमीन अधिग्रहण रेट के बारे में बता रहे थे तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि खुद विधायक के गांव में किसानों को

22 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा मिला है और उसी जमीन को HSIIDC ने 28 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेचा है। यह रिकार्ड की बात है।

श्री जयतीर्थ : उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत स्टेटमैंट है। हमारे बड़खालसा गांव में 282 एकड़ जमीन राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के लिए एक्वायर की गई। हमारे गांव का खेती का जो रकबा है वह दो गांवों में पड़ता है। ये दो गांव हैं सेवली और बड़खालसा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि सेवली गांव में जो रकबा है उसमें टोटल जमींदारों ने 45 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा उठा रखा है। बड़खालसा में 47 आदमियों ने मुआवजा उठा लिया है और बाकी उठाने वाले हैं।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, तभी इनके गांव में लोग धरने पर बैठे हैं।

श्री जयतीर्थ : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी पार्टियों ने अपने कुछ आदमियों को उकसाकर धरने पर बैठा रखा है। उन्होंने महज खबर बनाने के लिए धरने पर अपने आदमियों को बैठा रखा है। मेरे गांव के आदमियों का धरने से कोई वास्ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सेवली गांव के किसान यहां धरने पर बैठे हैं उनमें से 90 प्रतिशत किसान मुआवजा उठा चुके हैं। जो लोग धरने पर बैठे हैं उनमें से ज्यादातर की तो जमीन एक्वायर भी नहीं हुई। ये लोग तो बहकावे में आकर धरने पर बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की भूमि अधिग्रहण पॉलिसी की न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सराहना हो रही है और इस पॉलिसी का अनुसरण किया जा रहा है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ट्रेजरी बैंचिज के सदस्य माननीय साथी की बात से सहमत नहीं है ? यदि सहमत हैं तो मेजें क्यों नहीं थप-थपा रहे ?

श्री जयतीर्थ : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली उत्पादन का जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के उत्पादन में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़ौतरी हुई है। वर्ष 2010 में खेदड़, हिसार स्थित 1200 मैगावाट की राजीव गांधी ताप बिजली परियोजना की दो इकाइयों के चालू होने से राज्य के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। जिस पर तकरीबन 4297 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसी तरह से झज्जर में स्थापित हो रहे इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट की 500 मैगावाट की पहली इकाई 4 मार्च, 2011 को शुरू हो चुकी है और दूसरी इकाई की 21-10-2011 को सिंक्रोनाईजेशन हो चुकी है। इस पर टोटल 7892 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि रोहतक के कबूलपुर और दीपालपुर गांवों में 400-400 मेगावाट के सब-स्टेशन लगाये जायेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर पर और राई हल्के की जनता की तरफ से आभारी हूँ। इससे हमारे हल्के की बिजली की समस्या पूरी तरह से दूर हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है इस क्षेत्र में भी प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। हमारा सोनीपत जिला आज एजूकेशन हब बनने जा रहा है। हमारे यहां राई में छोटू राम टैक्नीकल यूनिवर्सिटी, मुरथल में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, कुण्डली में नैशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फूड टैक्नोलोजी बनाये जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर पर और राई हल्के की जनता की तरफ से आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त नैशनल लॉ इन्स्टीच्यूट भी राई में बनाया जायेगा जो कि बहुत बड़ी बात है इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। इसके अतिरिक्त राई क्षेत्र के अंदर ही मुरथल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक स्किल्ड डिवैल्पमैंट के लिए कालेज खोला जायेगा जिसमें जो बच्चे 8वीं पास करने के बाद पढाई छोड़ देते हैं उन्हें स्किल्ड ट्रेनिंग दी जायेगी इसके लिए भी मैं

[श्री जयतीर्थ]

माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर पर और राई हल्के की जनता की तरफ से आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के बच्चे हॉयर एजूकेशन के लिये विदेशों में या साउथ में जाते हैं और वहां पर लाखों रुपये मां-बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने पड़ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी एजूकेशन सिटी का जो प्रोजैक्ट बनाया है यह हुड्डा साहब का ड्रीम प्रोजैक्ट है। इसके बनने से जो बच्चे हॉयर एजूकेशन के लिए विदेशों में या साउथ में जाते थे उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारे बच्चों को विदेशों में जाने की बजाय यहीं अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश में खिलाड़ियों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल नीति भी बनी है और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। जो खिलाड़ी जितना बड़ा पदक लायेगा उसे उतनी ही बड़ी नौकरी मिलेगी। हमारी सरकार की योजना है कि "पदक लावो, पद पावो"। खिलाड़ी जितना बड़ा पदक लायेगा उसे उतना ही बड़ा पद मिलेगा। यह हमारी सरकार की पॉलिसी है जिसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज भी हमारे हाउस ने जो प्रस्ताव पास किया है और संदीप सिंह व सरदारा सिंह को ईनाम देने की जो घोषणाएं हुई हैं जिनके तहत 47 लाख रुपये संदीप सिंह को देने के साथ-साथ सरदारा सिंह को भी ईनाम देने की बात कही गई है मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके लिए सरकार को बधाई भी देता हूं। कुछ समय पहले ऐसा होता था कि हमारे अच्छे-अच्छे खिलाड़ी जब पदक तो लेकर आते थे लेकिन तब उनको कोई नौकरी नहीं मिलती थी तो वे अपराध के रास्ते पर चल पड़ते थे। आज हमारी सरकार ने 361 खिलाड़ियों को डी.एस.पी., इंस्पैक्टर, सब-इंस्पैक्टर और भी कई अलग-अलग तरह की नौकरियां दी हैं। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं । इसके अलावा भी सरकार ने कई और ईनामों की योजनायें भी बनाई हैं जिसके लिए मैं सरकार की सराहना करते हुए बधाई देता हूं। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे राई हल्के में मोती लाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल है उसमें 4 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से सिर्फ इन खेलों के विकास के लिए एक इंडोर हॉल बनाया गया है। इसके अलावा हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे मोती लाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल, राई में 3 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से एस्ट्रोटफ का ग्राउंड बनाया गया है जिससे हमारे एरिया में हाकी के खेल को बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए सरकार का बहुत आभारी हूं। डिप्टी स्पीकर सर, हमारी सरकार स्पोर्टस को बढ़ावा देने के लिए हर उस गांव में स्पोर्टस स्टेडियम बना रही है जहां की पंचायत जरूरत के अनुसार 4 एकड़ या 6 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। सरकार की योजना है कि उस गांव में एक खेल स्टेडियम बनाया जायेगा। मेरे अपने हल्के के चार गांवों में इस प्रकार के खेल स्टेडियम बनाये जा चुके हैं और पांचवें गांव में कुश्ती का हाल बनाया जा रहा है। हमारे गांव में राजीव गांधी खेल स्टेडियम बना है। (शोर एवं व्यवधान) मेरे राई हल्के में खेवड़ा, नारा, हलालपुर, औरंगाबाद और खेड़ी मनाजा गांवों में स्टेडियम बने हैं और खेड़ी मनाजात में कुश्ती हाल बनाने की योजना सरकार के लैवल पर चल रही है। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने 196 खेल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई थी जिनमें से 138 स्टेडियम तो सरकार द्वारा बना दिये गये हैं। डिप्टी स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि वर्ष 2005 से लेकर अब तक 605 करोड़ रुपये की लागत से 29 रेलवे ओवरब्रिज बनाये गये हैं और 869 करोड़ रुपये की लागत से 25 रेलवे ओवरब्रिज का काम अब चल रहा है। डिप्टी स्पीकर सर, हमारा सोनापत जिला हरियाणा सरकार का आभारी है कि हमारे सोनीपत में एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक आर.ओ.बी. बनाने की इस सरकार ने मंजूरी दी है। मैंने जब से होश सम्भाला था जब मैं हिन्दु स्कूल में पढ़ता था तो हमारा स्कूल इस रेलवे लाईन के दूसरी ओर पड़ता था इसलिए हमें इस रेलवे क्रॉसिंग को

पार करके जाना पड़ता था। उसके बाद जब हम कालेज में आये तो वह कालेज भी इस रेलवे लाईन के दूसरी ओर पड़ता था इसलिए कालेज में भी इस रेलवे लाईन को क्रॉस करके जाना पड़ता था और कालेज छोड़ने के बाद जब हम वकील बने तो हमारी कोर्ट भी इस रेलवे लाईन के दूसरी तरफ पड़ती थी इसलिए हमें कोर्ट जाने के लिए भी इस रेलवे लाईन को क्रॉस करके जाना पड़ता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8-8, 10-10 घंटे इस रेलवे फाटक को पार करने में लग जाते थे। हमारी बहन कविता जैन यहां पर नहीं है वे जिस दिन से सोनीपत में ब्याही आई हैं और जिस दिन से वे एम.एल.ए. बनी हैं तब से वे इसकी डिमांड करती रही हैं कि इस फाटक पर पुल का निर्माण करवाया जाये। हमारी सरकार ने वहां पर आर.ओ.बी. बनाने की योजना को मंजूरी दे दी और इस आर.ओ.बी. पर लगभग 40 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय हमारे बीसवां मील की सड़क को स्टेट हाईवे बहालगढ़ तक चौड़ा किया गया है। उस पर बहुत भीड़ रहती थी। उस पर एक रेलवे क्रॉसिंग छतैहरा पड़ती थी जहां पर दिन में कई-कई घण्टे ट्रैफिक जाम रहता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस परेशानी को दूर करते हुये वहां पर भी आर.ओ.बी. मंजूर कर दिया। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये।)** अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जी.टी. रोड़ पर बहालगढ़ क्रॉसिंग सोनीपत जिले और हमारे हरियाणा प्रांत को यू.पी. से जोड़ती है। इस क्रॉसिंग पर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता था कि बगैर पुलिस की सहायता के वहां से क्रॉस नहीं किया जा सकता था। चण्डीगढ़ से दिल्ली तक वैसे तो सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाये जा चुके थे, केवल बहालगढ़ ही बचा था। माननीय मुख्य मंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारी इस परेशानी को समाप्त करते हुये इसको भी मंजूरी दे दी।

श्री अध्यक्ष : दहिया साहब, आप कन्कल्यूड कीजिए।

श्री जयतीर्थ : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा मेरे अपने हल्के में 8 सब-सैन्टर इसी साल खोले गये हैं जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी पंचायतें आज आगे ही आगे बढ़ती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी जिस मेहनत और लगन के साथ हमारे प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं उनकी लगन और उत्साह के लिए मैं दो लाईन कहना चाहता हूं:--

सीढ़ियां उनके लिए होती हैं, जिन्हें छत पर जाना है,

आसमां पर हो जिनकी नजर उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती सोनिया गांधी, यू.पी.ए. चेयरपर्सन और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन से इस हरियाणा का जो 36 बिरादरी का, हर वर्ग का, हर क्लास का अपनी कल्याणकारी नीतियों से भला किया है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। जहां तक मेवात की बात है मेवात के अन्दर अभी-अभी एक मैडिकल कालेज नल्हड़ के अन्दर बनाया जा रहा है वहां पर इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ था, वह मेवात के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मीठे पानी की व्यवस्था सोनिया जी ने खुद वहां पहुंच कर एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे मेवात के अन्दर मीठा पानी मिल सके।

श्री नसीम अहमद : माननीय स्पीकर सर, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मैं आपकी अनुमति से जो मैम्बर साहब ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से नल्हड़ में जो मैडिकल कालेज बनाया जा रहा है, ये माननीय सदस्य जी को शायद पता न हो कि पहले इसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन्द्री में बनाना चाहते थे लेकिन मेवात के लोग संघर्ष कर उसको नल्हड़ में लेकर आए।

श्री अध्यक्ष : अब जहां बना रहे हैं आप उसके खिलाफ हैं क्या ?

श्री नसीम अहमद : नहीं सर।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है बैठिए।

श्री जगबीर सिंह मलिक : जो काम करने वाले की कदर करना नहीं जानता उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है। कम से कम इनको मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस बात के लिए इन्होंने धन्यवाद किया है कि नल्हड़, मेवात में मैडिकल कालेज खुला है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : मेरे काबिल सदस्य जो इस सरकार से पहले 6 साल जो सरकार रही है यदि उसने सारे काम कर दिये होते तो आज उनको बार-बार ये सुनने को नहीं मिलता कि मेवात पिछड़ा इलाका है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जहां तक सिरसा की बात है उसमें डैवल्पमैंट के जो काम हुए शायद पिछली सरकार ने नहीं किये थे जो इस सरकार ने सिरसा के डैवल्पमैंट के लिए किए हैं। एक-एक को यहां गिनाने लगूं तो यहां समय बहुत लग जाएगा आपने थोड़ा समय दिया है। चाहे सिरसा में ओवर ब्रिज की बात हो चाहे, सिरसा में आर.ओ.बी. की बात हो, चाहे सिरसा में इरिगेशन की बात हो। गोहाना की बात कहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं । गोहाना के अन्दर एक मैडिकल कालेज दिया और नोरदर्न इण्डिया में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, गोहाना के अन्दर आर.ओ.बी. भी दिया । गोहाना के अन्दर एक रेलवे लाइन दी, जो सोनीपत से जीन्द को जाती है। इस से बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री दे नहीं सकते जो इन्होंने एक कांस्टीच्यूएंसी को दिया है। इस सबके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक-एक समस्या को हल किया है, और मैं सबसे पहले एक किसान वर्ग की बात करता हूं जो लोग किसान हितैषी होने का दावा करते थे। सात साल पहले जो सरकार थी उस समय मुआवजा क्या था और कुंडली मानेसर हाईवे के लिए जो जमीन अढाई लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर होनी थी जिसका मुआवजा भी आ चुका था लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री महोदय, ने केन्द्र सरकार को लिखा कि हम इसका मुआवजा ढ़ाई लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं लेगें हम इसका मुआवजा बढ़ाकर लेंगे और उस समय 17 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जमीदार की जमीन का मुआवजा ठीक मिले और जहां तक पॉलिसी 2011 में 6 जोन बनाकर जो लैंड एक्वीजिशन पॉलिसी बनाई गई है इसकी प्रशंसा हर स्टेट में हुई है। हर जगह ये लागू किया जाना चाहिए ऐसी बात आई है और इस नई पॉलिसी के अन्दर नो लिटिगेशन बोनस 20 प्रतिशत जोड़ा गया है। इसके अलावा रिहैबलीटेशन ऑफ दी डिस्पलेस्ड परसन इस पॉलिसी में दिया गया है उनको प्लॉट दिए जाएंगे। इसके अलावा जिस गांव की जमीन होगी उस पैसे में से दो प्रतिशत राशि उस गांव की डैवल्पमैंट के लिए खर्च होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की जमीन एक्वायर होने के बाद भी उसको 21000 रुपये 13.00 बजे प्रति एकड़ की रॉयल्टी मिलेगी। आप यह देखिये एक आदमी अपनी प्रापर्टी को बेच देता है या उसको दे देता है तो उसके बाद भी लगातार 33 साल तक उसको रॉयलटी देना, यह मुख्यमंत्री जी

ने कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए पॉलिसी बनाई। इसके अलावा जमींदारों को क्रॉप लोन 11 परसैंट इंट्रस्ट पर नहीं बल्कि 4 परसैंट पर देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसका सुझाव प्रधानमंत्री को दिया गया और वह स्कीम लागू होने पर आज हरियाणा का किसान 4 परसैंट ब्याज पर पैसा ले रहा है। पहले किसान को पांच एकड़ जमीन होने पर ट्रैक्टर लेने के लिए लोन मिलता था लेकिन आज उसे एक एकड़ जमीन होने पर भी ट्रैक्टर लेने के लिए लोन मिल जाता है। इसके अलावा जमींदार की जमीन पर कोई लोन है तो उस लोन की रिकवरी के लिए अब उसकी जमीन की कोई ऑक्शन नहीं होगी बल्कि दूसरे तरीकों से किसान से उस लोन की वसूली होगी। इसके साथ ही पहले जो किसान को जेल में बन्द करने का काला कानून था अब उसको भी समाप्त कर दिया गया है अब किसान को अरैस्ट भी नहीं किया जायेगा।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, जो लोन की बात कही गई है वह सरासर असत्य है। आज बैंकों में किसानों को लोन नहीं मिल रहा है। आज किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। यह लोन वाली बात कहकर सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं और कुछ नहीं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : नायर जी, यह वाहा वाही लूटने की बात नहीं बल्कि यह हमारी सरकार की उपलब्धि है।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा डिपार्टमैंट है। सर हम बराबर लोन दे रहे हैं अगर कोई एग्जांपल हो कि लोन एप्लाई किया है और उसे नहीं दिया गया तो हमें बतायें ?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं भी कोपरेटिव से जुड़ा हुआ हूं, एक बैंक का चेयरमैन भी हूं, मैं आपको कितने ऐसे उदाहरण दूं कि जिनमें बैंक ने लोन नहीं दिया।

श्री सतपाल : अजय जी, आप उदाहरण नहीं आप तो केवल मुझे बता दीजिये। You are the Chairman of the Cooperative Bank. You send me in writing what you means, स्पीकर सर, मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को कोआपरेटिव बैंक में अजय जी जैसे चेयरमैन मिल गये। At least you guide me properly. What is in it, you tell me. Nobody has any complaint against me upto now.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : सांगवान जी, मैं आपके मातहत नहीं हूं मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं।

श्री सतपाल : अजय जी, आप मातहत तो मेरे ही हो क्योंकि वो बैंक मेरे ही अण्डर है चाहे मातहत हो या न हो that is another thing.

श्री अध्यक्ष : अजय जी, सांगवान साहब आपसे गाईडैंस ही मांग रहे हैं कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं ?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वह तथ्यों से परे है। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें बैंकों ने लोन नहीं दिया।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हर एक बैंक का एक टारगेट होता है कि कितने पैसे कब दिये जायेंगे और यदि बैंक सिस्टम टाईम से पहले ही उस टारगेट को पूरा कर देता है तो साल के अन्त में बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है और इस परिस्थिति में यदि किसी को बैंक से लोन न मिल पाये तो यह कहना गलत है कि बैंक ने पैसे नहीं दिये।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई आदमी बैंक लोन अप्लाई करता है और सारी कंडीशंज पूरी होने के बाद भी उसे लोन नहीं मिला हो तो उसका मुझे एक भी उदाहरण बता दें तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, आप बैठिये यह कह रहे हैं कि अगली बार आयेंगे तो ऐसे उदाहरण साथ लायेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां एग्रीकल्चर इंप्लीमैंटस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी है वहां सीड्स पर, जिप्सम पर और कृषि से संबंधित हर एक काम पर भी बहुत ज्यादा सब्सिडी दी है उसके परिणामस्वरूप हरियाणा कृषि का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी है जो केवल मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का ही परिणाम है। मेरे आदरणीय साथी श्री राम पाल माजरा जी ने कृषि के बाद पशुधन के बारे में भी एक बात कही है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, पशु चिकित्सा के लिए हिसार में स्थापित की जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने पशुओं का बीमा और जो पशुपालक हैं जो सोसायटी बनाये हुए हैं उनका भी बीमा करके उनके रेट में इजाफा करके पशुधन को इस लायक बना दिया है कि आज हरियाणा की मुर्राह भैंसें विदेशों में जाती हैं और यहां तक कि पिछले दिनों अखबार में भी आया था कि हमारे यहां का एक झोटा एक करोड़ रुपये में बिका है। इतनी बड़ी तबदीली आ रही है। यह तबदीली सिर्फ हमारी सरकार की नीतियों की वजह से आई है। (शोर एवं व्यवधान) अब मैं बिजली उत्पादन के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं विपक्ष के साथियों से यह भी जानना चाहूंगा वे यह बताएं कि उन्होंने बिजली के उत्पादन के लिए कौन से कारखाने लगाये थे ? जो लोग आज 24 घंटे बिजली चाहते हैं उन्होंने अपनी सरकार के समय में इस दिशा में क्या कदम उठाए, यह भी बताएं। यह तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हुआ है। वर्ष 2004-05 में जब मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी तो उस समय बिजली का उत्पादन केवल मात्र 1587 मेगावाट था, आज वर्ष 2012-13 में 5000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त उपलब्ध है, यह सब मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली का ही परिणाम है। (शोर एवं व्यवधान) वर्ष 2004-05 में जो पर डे बिजली की उपलब्धता थी वह 578 लाख यूनिट थी, आज बढ़कर वह 1056 लाख यूनिट हो गई है। इस प्रकार से अब जो नयी चीनी मिलें लगाई जा रही हैं, उनमें भी बिजली के प्रोडक्शन के लिए काम चल रहा है। नये सब स्टेशनों के निर्माण का काम चल रहा है और पिछले सात वर्षों में काफी काम हुआ है वैसे तो हरेक की इच्छा पूरी नहीं हो सकती लेकिन हमारी सरकार ने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पहले किसान ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए तरसते थे, आज इस सरकार ने 5 लाख 31 हजार 848 कनैक्शन दिये हैं। इसके अलावा हमारी सरकार की अच्छी खेल नीति के कारण हरियाणा के श्री भगत सिंह को खेल रत्न पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति ने दिया है उससे बड़ी कोई और उपलब्धि प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मामूराम (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार वाहवाही लूट रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नं. 19 के क्रमांक नं. 42 पर यह लिखा गया है कि मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काफी पैसा दिया गया है और सब-प्लॉन के अन्तर्गत 2593.29 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह अनुसूचित जाति

और पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग को जो इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी शगुन योजना का पैसा दिया जा रहा है। आप किसी जिले के आंकड़े ले लीजिए वे सभी एक साल से पैंडिंग पड़े हैं। लोक मारे-मारे फिर रहे हैं और सरकार वाहवाही लूट रही है। जब हम जिला कल्याण विभाग में जाते हैं तो वहां पर यह जवाब मिलता है कि बजट नहीं आया है और जो अधिकारी इस बात को बता देता है तो डॉयरेक्टर या एफ.सी. रैंक के अधिकारी उस अधिकारी को चार्जशीट कर देते हैं। वे उस पर यह कहते हैं कि आप उनको महकमें के बारे में बताते क्यों हो। इस प्रकार लोगों की अनदेखी की जा रही है। मेरे हल्के नीलोखेड़ी की सारी की सारी सड़कें टूटी हुई हैं मैंने पिछले सत्र के दौरान एक प्रश्न भी लगाया था उस समय माननीय मंत्री श्री सुरजेवाला जी ने यह कहा था कि तरावड़ी से नीलोखेड़ी तक और बादशाहपुल तक की सड़कें 31-3-2012 तक बन जायेंगी, लेकिन आज तक उस सड़क पर एक रोड़ा तक भी नहीं लगा है। यहां सदन में आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन सड़कों का कोई काम नहीं हुआ है। ये सड़कें हैं गोन्दर से गुनियाना, गोन्दर से डाचर, निर्सिंग से डाचर, जाम्बा से किरमच, समानाबाहु से बड़सालू, कुचपुरा से सींघड़ा होते हुए मोतिया, सीतामाई से भुखापुरी, सांवत से हैबतपुर, कारसाडोड से साकरा, रमाणा रमाणी से बोहलाखालसा, नीलोखेड़ी से कारसाडोड, तरावड़ी से रमाणा रमाणी, शामगढ़ से तरावड़ी। सारी सड़कें वहां पर टूटी पड़ी हैं और इनमें गढ्ढे पड़े हुए हैं। वहां पर एक भी रोड़ा आज तक नहीं लगा है और न ही किसी सडक की रिपेयर हुई है। सरकार सदन में आश्वासन दे देती है लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात मैं अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं। सी.एच.सी., तरावड़ी में कोई भी एक्स-रे की मशीन नहीं है। जहां तक तरावड़ी के ओवरब्रिज की बात है वह भी टेढ़ा-मेढ़ा बनाया गया है। नीलोखेड़ी के ओवरब्रिज का सर्वे किया गया था लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं किया गया है जिसके कारण वहां के लोगों को आने-जाने में असुविधा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं शिक्षा के मामले में कुछ कहना चाहूंगा। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने शिक्षा के बारे में गवर्नमैंट कालेज खोलने के लिए एक प्रश्न लगाया था जिस पर मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि नीलोखेड़ी यहां से 15 किलोमीटर पर है। जबकि गांव 40-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। निगदु गांव करनाल से 40 किलोमीटर दूरी पर है और निर्सिंग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में कोई समाधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर एक सरकारी कालेज बनना चाहिए।

Mr. Speaker : Thank you, very well said.

श्री नरेश कुमार (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में ख्याति प्राप्त विकास पुरुष के नाम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जाने जाते हैं जो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर सरकार चला रहे हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर और सबकी मान-सम्मान की रक्षा करते हुए आज जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अन्दर आगे बढ़ रही है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मैं दो लाईनें बोलना चाहूंगा। हमारी सरकार कृषि को उच्चतम प्राथमिकता देती है और किसान भाइयों की रोजमर्रा की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप कृषि की हर फसल के लिए भाव बढ़ाये जाते हैं। फसलों का उचित मूल्य दिया जाता है। वर्ष 2005 से पहले हरियाणा प्रदेश के अन्दर एक सरकार सफर कर रही थी जिसमें हर आदमी दु:खी था और प्रदेश में हाहाकार मची हुई थी। लोग मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघरों और वर्चों में जाकर यहां तक कहते थे कि हम भेहली बांटेंगें जब इस सद्दाम राजे का अन्त होगा और हरियाणा खुले आसमान के नीचे सुख की सांस ले सकेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तो चौटाला जी का नाम ही नहीं लिया इन्होंने तो सद्दाम राजे कहा है। ये सद्दाम राजे के नाम पर क्यों उत्तेजित हो गए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप भी जानते हैं और यह सच्चाई है, जिसको हर कौम मानती है, हर धर्म मानता है और हर मजहब मानता है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना है। अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे और सारा हाउस भी सहमत होगा। (शोर एवं व्यवधान) पहले मुसलमानों में जब कोई मौत हुआ करती थी तो तीजा हुआ करता था। जिस तरह इसाइयों में बाइबल, हिन्दुओं में गीता और सिक्खों में गुरूग्रंथ पढ़ा जाता है। हमारे मुसलमानों में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। तीन दिन तक कुरान शरीफ को पढ़कर पूरा किया जाता है तो तीजा हुआ करता था। तीजे में उस समय भुने हुए चने बांटे जाते थे, बतासे बांटे जाते थे। हमारे यहां एक बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई और प्रश्न उठा कि कुरान शरीफ कौन पढ़ेगा ? अन्त में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मेरे जैसे का नम्बर पड़ गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, यह आपका प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री नरेश कुमार (बादली) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान 252.41 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। (शोर एवं व्यवधान) सरकार ने गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाए हैं। चालू पिराई सीजन के दौरान राज्य सरकार द्वारा सुझाया गया गन्ने का मूल्य अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए क्रमश: 231 रुपये, 226 रुपये और 221 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। (विघ्न)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर पूरा नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दो वरना इनकी आत्मा भटकती रहेगी।

Shri Randeep Singh Surjewala : There are continuous running commentaries. There is no point of order. (Interruption) You have to discipline the House, Sir, How can he rumple upon the rights of the Hon'ble Member of this House ? (Interruption). This is not permissible, Sir. (Interruption). Speaker Sir, Hon'ble Member will get time to speak (Interruption).

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं सत्य बात कर रहा हूं कि जो तीजा होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। नरेश शर्मा जी, आप कंटीन्यू करें।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान 252.41 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। सरकार ने गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि चालू पिराई सीजन के दौरान राज्य सरकार द्वारा सुझाया गया गन्ने का मूल्य अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए क्रमश: 231 रुपये, 226 रुपये और 221 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्वांयट ऑफ पर बोलने के लिए अलाउ करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोलें। आप जो बात कह रहे हैं यह प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Whatever said without my permision not to be recorded. Yes, Mr. Naresh, Please continue.

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि पहले की सरकारों ने किसान द्वारा कर्ज न दिए जाने पर किसानों को जेलों में डाल दिया जाता था उस काले कानून को समाप्त किया और प्रदेश के किसानों को मान-सम्मान दिया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि पहले जो किसान लोन नहीं चुका पाते थे उन्हें पकड़कर जेलों में डाला जाता था। उस समय किसानों पर बड़ी ज्यादती की जाती थी और जेल में रोटियों का खर्चा भी वसूला जाता था। (शोर एवं व्यवधान) उस समय जो लोग किसानों को बेइज्जत करते थे आज वे किसानों के हितों की बात करते हैं। उस समय जब किसान अपने अधिकारों की रक्षा और हकों की बात करते थे तो इन पर गोलियां चलाई जाती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, प्लीज आप बैठें। अब आप बजट पर बोलना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, ऐसी-ऐसी सरकारें हरियाणा में रही कि जब चुनाव का समय आता था उस समय किसानों के पास जाते थे और किसान हितैषी होने की बातें करते थे। उस समय वे वादा करते थे कि आप लोग हमें वोट दो हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। न मीटर होगा और न ही मीटर रीडर होगा। किसान उनके बहकावे में आकर उन्हें वोट दे देते थे और उन लोगों की सरकार बनने के बाद जब किसान उनके पास आते थे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mohd. Ilyas Ji, please resume your seat.

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब किसान उनके पास आकर उनका वादा याद दिलाते थे कि आपने कहा था कि बिजली मुफ्त दी जायेगी तो वे लोग किसानों पर गोलियां चलवाते थे। वे लोग वादा भूल जाते थे और किसानों की हत्या करवा देते थे। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रेस पर चर्चा चल रही है। एक माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में रनिंग कमेंटरी हो रही है (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथी आपसे बगैर पूछे खड़े हो रहे हैं। यह कोई लाफ्टर चैनल थोड़ी है, यह हरियाणा विधान सभा का सदन है। यहां पूरी ब्यूरोक्रेसी, पत्रकार और जनता भी बैठी है। विपक्ष के साथी बीच-बीच में रनिंग कमेंटरी शुरू करके एक माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। विपक्ष के साथियों को सबकी बात सुननी चाहिए और माननीय सदस्य को बोलने देने चाहिए।

Mr. Speaker : Yes point be well taken.

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, ----------

श्री अध्यक्ष : आपने प्वायंट ऑफ आर्डर रेज नहीं किया, प्लीज आप बैठे।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की पुनर्वास नीति भी देश में प्रथम है। हमारी पुनर्वास नीति की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहना की जाती है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव का समय आता है उस समय हमने दूसरे राज्यों में नेताओं को यह कहते हुए सुना है कि हमारे समर्थन में वोट दो हम भी अपने प्रदेश में सरकार बनने पर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की तरह विकास नीतियां लागू करेंगे और उसी तरह से भूमि अधिग्रहण नीति लागू करेंगे। आज चाहे किसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो वे सरकारें हरियाणा की पॉलिसीज का बड़े गर्व के साथ अनुसरण करती हैं और वे कहते हैं कि हम भी प्रदेश में हुड्डा साहब की तर्ज पर विकास कार्य करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण होती है उन्हें प्लाट भी अलॉट किए जाते हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विज, आप कृपया करके बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, इसके अलावा जैसा कि सरकार द्वारा नॉन लिटीगेशन राशि देने का प्रावधान किया गया है। जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपने दरियादिली दिखाकर कल विज साहब को माफ कर दिया लेकिन वे आज भी मैम्बर्ज के साथ टीका-टिप्पणी और इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो यह अशोभनीय है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विज साहब को और रामपाल माजरा जी दोनों को हाउस का सलीका समझाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत होती है उन किसानों को आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लाट आबंटित किये जाते हैं और प्रभावित परिवारों को, उनके आश्रितों को चौधरी भूपेन्द्र हुड्डा की सरकार रोजगार देती है। पहले हमने देखा है कि हमारी जमीन एक्वायर होने के लिए दफा चार का नोटिस आया था। यह जमीन बेशकीमती जमीन थी और सरकार उसे कौडियों के भाव में हमसे छीनने का काम कर रही थी। जब हम सरकार के आकाओं से मिले और हमने उनसे जब यह जानना चाहा कि हमारी जमीन किस परपज़ के लिए और किस काम के लिए ली जा रही है तो उस समय हमें धक्के मारकर बाहर फैंक दिया गया था लेकिन हमें कारण नहीं बताया गया था। उस समय भूमि अधिग्रहण की जो राशि वह मात्र 2.60 लाख रुपये प्रति एकड़ थी। वही जमीन आज एक्वायर

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हुई है तो उस जमीन की मुआवजा राशि हमें 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हुई है। इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आने से राम राज्य की स्थापना हुई है और हमारे जैसे लाखों किसानों की जान बची है। हरियाणा प्रदेश में आज अगर कोई परेशान है तो वे हैं जो हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटते थे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी किल्लत थी क्योंकि पहले की सरकारों ने प्रदेश में बिजली का कोई भी कारखाना नहीं लगाया था। हरियाणा सरकार को बिजली की समस्या विरासत में मिली थी। सरकार द्वारा बिजली उत्पादन और सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली की आपूर्ति में भी भारी वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2004-05 के दौरान प्रतिदिन औसतन 578 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी वह अब बढ़कर 1009 लाख यूनिट प्रतिदिन पर पहुंच गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 2.36 लाख परिवारों में से 1.94 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन परियोजनायें अच्छी प्रगति में हैं। आज महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट में 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और 600 मेगावाट की दूसरी यूनिट को 11 जनवरी, 2012 को सिंक्रोनाईज किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, आज अगर कोई हरियाणा प्रदेश में दुखी है तो वे लोग हैं जो जनता से झूठे वायदे करते थे और कहते थे कि न मीटर होगा न मीटर रीडर होगा। अगर दुखी है तो कुर्सी के काटे हुये लोग दुखी हैं लेकिन उनको यह भी पता होना चाहिए कि कुर्सी तो जनता ने देनी है और वह उनको मिलने वाली नहीं है। स्पीकर सर, मैंने तो अभी शुरू ही किया था और मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण शायद सभी कुछ कहना सम्भव नहीं है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Mr. Speaker : Now the Hon'ble Chief Minister will give reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है चाहे वह कोई भी फील्ड हो। चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, चाहे कृषि विकास दर की बात हो या पर-कैपिटा इन्कम की बात हो, चाहे पर-कैपिटा इनवैस्टमैंट हो, हर फील्ड में आज हरियाणा अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की चर्चा सारे देश में है। आज हम इस जगह पर पहुंचे है यह हमारी सरकार की नीतियों, दृष्टिकोण और हमारी दूरदर्शिता का ही नतीजा है। हमने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिससे हर आदमी को फायदा पहुंचे। मैं इस बात के लिए सभी हरियाणावासियों को बधाई देता हूं क्योंकि इसमें सभी का योगदान है। इस विकास में हर हरियाणावासी का हाथ है। आज देश में हरियाणा की हर फील्ड में एक अलग पहचान है। मैं हरियाणावासियों की ओर से कहना चाहता हूं कि :-

हम तो दरिया हैं, हमें हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चलेंगे, रास्ता बन जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का धन्यवाद करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं क्योंकि हरियाणा में जो-जो कार्य हुये हैं उन सब में हमको उनका

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

नेतृत्व प्राप्त हुआ है और हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछले जो हमारे विपक्ष के साथी है और मैं भी विपक्ष में रहा हूं और अब पक्ष में भी हूं, मुझे भी विपक्ष का लम्बा तजुर्बा है। हम जब भी विपक्ष में रहे तो हमने एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजीशन की भूमिका निभाई । जब यह चर्चा शुरू हुई और हमारे विपक्ष के नेता ने अपना भाषण शुरू किया तो उससे मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि उनकी परफॉरमैंस और कंडक्ट खास तौर पर जिस प्रकार का रहा यह कोई कंस्ट्रक्टिव ओपोजीशन की लीडरशिप वाला मुझे नहीं लगा और इससे मुझे निराशा हुई। अध्यक्ष महोदय, जब भी बजट सत्र या मानसून सत्र होता है तो उससे कुछ दिन पहले ये बड़े-बड़े ब्यान अखबारों में देने शुरू कर देते हैं कि जब बजट सत्र होगा या असैम्बली का सैशन होगा तो देखना उसमें क्या होगा। सरकार को ऐसे घेरेंगे, वैसे घेरेंगे। यह होगा, वह होगा लेकिन होता कुछ नहीं है खुद घिरकर बैठ जाते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बोलते रहे मैं नहीं बोला। मेरा श्री अशोक कुमार अरोड़ा से निवेदन है कि वे तो स्पीकर रहे हैं उनको तो कम से कम बीच में नहीं बोलना चाहिए। श्री अशोक कुमार अरोड़ा और श्री रामपाल माजरा जी को बीच में बोलने की आदत पड़ गई है। यह अच्छी आदत नहीं है अच्छी आदत है सुनने की आदत। इनको सुनना भी सीखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब चौटाला जी का भाषण सुना तो मायूसी हुई। मैं सोचता कि बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव बात कहेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल से रिकार्ड उठाकर देखें तो वही चुने हुये मुहावरे, वही कटाक्ष, वही तरीका और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इनके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि :-

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,

चीरा तो कतरा खून का न निकला।

अध्यक्ष महोदय, ये बोलते तो हैं लेकिन ये भी सदस्य हैं। बहुत सारे और लोग भी बोलते हैं। इस बारे में मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता हमारे बड़े भाई हैं, इनके बारे में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि -

तुझको कुछ लोगों ने सिर आंखों पर बिठा रखा है,

वरना क्या तेरी हकीकत है, जानते हैं हम।

अध्यक्ष महोदय, हर बार ही वही बात दोहराना ठीक नहीं है। मैं इस सदन का ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता लेकिन कुछ जरूरी बातें अवश्य कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के नेता ने आज चर्चा की, जिस प्रकार से यहां बातें उठाई और सबसे पहले जैसे मैंने कहा। ये हर बात शुरूआत इस बात से करते हैं कि किसान की हालत खराब है, दयनीय है, किसान को पानी नहीं मिल रहा, किसान को बिजली नहीं मिल रही, कहीं कहेंगे उद्योगपति परेशान हैं, आम आदमी की स्थिति दयनीय है। मैं समझता हूं कि आम आदमी तो खुश है, ऐसा लगता है कि ये अपनी स्थिति का बखान यहां लोगों का या आम आदमी का या किसान का नाम लेकर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने पंजाबी में कहावत भी सुनी होगी कि गालां कड्डे सासु नूं, ले ले नां भरांवां दा। बादा लोगों का करते हैं और बखान अपनी स्थिति का करते हैं क्योंकि हर बात में देखें, बहुत सारी बात इन्होंने यहां पर कहीं। आप देखें पहले किसान के बिजली-पानी की बात कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि अगर किसान को बिजली पानी ना उपलब्ध हो तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2010-11 में 166.29 लाख टन अनाज की पैदावार हुई है जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इतनी

पैदावार बिना बिजली पानी के कैसे होगी ? इनकी सरकार के समय में वर्ष 2001 और 2002 में यह उत्पादन 132.99 लाख टन था, अब इतना उत्पादन कैसे बढ़ा, क्या बिना बिजली और पानी के बढ़ गया ? आप खुद सोच सकते हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 2011-12 में भी इस बारे में रिकार्ड टूटने का मुझे पूरा भरोसा है और ऐस्टीमेटिड जो पैदावार है, वह 172.5 लाख टन होने की उम्मीद मेरे को है। दूसरा खुशहाली का पैमाना किसान का फूड ग्रेन प्रिक्योरमैंट है। अध्यक्ष महोदय, लोकदल-भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा अनाज की खरीद वर्ष 2001-2002 में की, जब कि उस समय पैदावार 79.85 लाख टन थी, जब कि 2011-12 में हमारे समय में ये जो खरीद या प्रिक्योरमैंट हुई, वह 98.60 लाख टन है। हमारे आंकड़े बोलते हैं, सच्चाई का खाता खुलता है, वह आपके सामने है। मैं इसमें और कुछ कहना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात इन्होंने कही। बिजली का जहां तक सवाल है, वर्ष 2005 में औसतन प्रतिदिन 578 लाख यूनिट बिजली प्रदेश में दी जाती थी जबकि 1009 लाख यूनिट औसतन प्रतिदिन पॉवर सप्लाई आज हम कर रहे हैं। साल 2004-05 में एग्रीकल्चर कन्जूमर को कुल 291 लाख यूनिट बिजली एवरेज डेली बेसिज पर दी गई थी। उसकी तुलना में 2012 तक हम 394 लाख यूनिट पॉवर एवरेज डेली बेसिज पर खेती के उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। साल 2004-05 में हाईएस्ट डेली पॉवार सप्लाई 787 लाख यूनिट थी, अब यह 1403 लाख यूनिट से भी ज्यादा हो गई है। 2004-05 में जो पॉवर जनरेशन कैपेसिटी 1587 मेगावाट थी, वह अब बढ़कर 4390 मेगावाट हो गई है। हमारे कुछ प्लांट आपरेशनल हो गए हैं और कुछ जल्दी होने जा रहे हैं जिससे इसमें और भी इजाफा किया जायेगा। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा चल रहा है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, ----------

Mr. Speaker : The Hon'ble Chief Minister is speaking please be seated. (Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, कृष्ण लाल पंवार जी का प्वायंट ऑफ आर्डर है, आप किस तरह इन्हें डिसअलाउ कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, प्वायंट ऑफ आर्डर है ही नहीं (शोर एवं व्यवधान) बिना पूछे खड़े होने से प्वायंट ऑफ आर्डर थोड़े ही बन जाता है, आप बैठ जाईए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने काफी प्रोग्रैस की है और उसका पैमाना लाईन लॉसेज़ से दिया जाता है। 2004-05 में लाईन लॉसेज़ में 39.61 प्रतिशत थे जोकि अब घटकर 25.22 प्रतिशत रह गये हैं और इसको आगे भी घटाने का हमारा प्रयास और संभावनायें हैं। इसी प्रकार से जहां तक बीज का संबंध है 2011 में 2.55 लाख क्विंटल बीज सप्लाई किया गया जबकि जरूरत सिर्फ 1.3 लाख क्विंटल की थी। इसी प्रकार हम खाद व पानी की सप्लाई भी करते हैं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि व्हीट की 2011 में रिक्वायरमैंट 9,27,000 क्विंटल थी जबकि हमारे पास उपलब्धता 12,56,950 क्विंटल है इसी प्रकार हर फसल के लिए हमारे पास रिक्वायरमैंट से ज्यादा बीज उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आलू की बात कही, यह बात ठीक है कि जब आलू पैदा करने वाला किसान, आलू का भाव नीचे गिरने की वजह से परेशान था तब हमारे को भी तकलीफ हो रही थी। जब आलू का भाव नीचे गिरा तो कुछ किसान मुझसे मिले और उसी समय हमने आलू पर मार्किट फीस जो 2 प्रतिशत थी उसे घटाकर 1 प्रतिशत करने का फैसला किया। अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कोशिश की कि आलू का विदेशों में निर्यात खुल जाये और कांट्रैक्ट फार्मिंग कार्यक्रम के अंतर्गत मदर

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
डेयरी, दिल्ली द्वारा 10,000 क्विंटल, पैप्सीको, पंजाब पटियाला द्वारा 1,50,000 क्विंटल और मैट्रो पंजाब द्वार 1,000 क्विंटल आलू साढ़े चार रुपये प्रति किलो से लेकर साढ़े पांच रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया जो अब तक एक रुपये कुछ पैसे प्रति किलो की दर से बिक रहा था। अध्यक्ष महोदय, आज ही मलेशिया से एक कम्पनी आई है जिसने पांच लाख क्विंटल आलू को साढ़े पाव रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने के लिए ऑफर दी है और इस कम्पनी ने कल एक तारीख को पीपली मंडी व शाहबाद के किसानों के साथ वार्ता भी की है तथा आलू, प्याज, टमाटर व लहसुन के नमूने देखकर भविष्य में व्यापार की इच्छा व्यक्त की है और आज एम.ओ.यू. साईन हो रहा है (विघ्न)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष जी, आप कैसे डिसअलाऊ कर सकते हो। हम बोलते हैं तो आप 10-10, 15-15 आदमी खड़ा कर देते हो। हम यह सहन नहीं करेंगे। हम वॉक आउट करते हैं। आपको अलाऊ करना ही पड़ेगा (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बहुत ज्यादा जोर व गुस्से से बोल रहे हो। बैठे-बैठे कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं होता। This will not be allowed. I will not allow (Interruption)। आप मुझे धमका रहे हो। मैं किसी से धमकता नहीं हूं (विघ्न)। क्या कोई आदमी खड़ा होकर बोलने लग जाये वह प्वायंट ऑफ आर्डर होता है। पहले बैठे-बैठे कहा जाता है कि प्वायंट ऑफ आर्डर है then I will allow लेकिन बिना परमिशन के उठकर यदि कोई बोलता है तो this will not allow (interruption). आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब को सुनना ही नहीं चाहते।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इन्होंने वॉक आउट तो करना ही होता है। इनकी पेसैंस पांच मिनट होती है। छठे मिनट तो यह लोग कभी बैठे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह लोग चेयर को कैसे aspersion cast कर सकते हैं। इनकी पोल जैसे-जैसे खुलेगी यह भागने लगेंगे। यह तो हर बार भागते हैं जब इनकी पोल खुलती है। अभी तो इनकी पोल खुलनी शुरू ही हुई है (विघ्न)।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप प्वायंट ऑफ आर्डर को डिसअलाऊ करें, यह आपका अधिकार है पर आप उसको पूरी तरह से सुनें तो सही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर प्वायंट ऑफ आर्डर बनता होगा तो मैं अलाऊ करूंगा। राम पाल माजरा जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी हर समय खड़े रहते हैं उनको सदा के लिए खड़े होने की सजा मिली हुई है क्या ? अध्यक्ष महोदय, इनके नेता कोई बात करें, वह बात बनती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस सदन की कार्यवाही को चलाने की अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जब कोई भी सदस्य प्वायंट ऑफ आर्डर रेज करे तो पहले बैठे-बैठे उसको कहना चाहिए कि मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है न कि वह सदस्य खड़े होकर बोलना शुरू करे दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है कि किसान का आलू और प्याज इस बार बाजार में पिटा है और इन्होंने कहा कि हमने इसलिए इसको मार्किट फीस में रियायत दी है। मैं कहना चाहूंगा कि आलू की फसल जब किसान के हाथ से

निकल जाती है तब उसके रेट बढ़ जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी जिससे कि आलू और प्याज का भी स्पोर्ट प्राईज सरकार तय करे जिससे किसान को लूट से बचाया जा सके।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोलते हुए बिजली उत्पादन के आंकड़े दिये कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट का और झाड़ली में 1320 मेगावाट का महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, मुख्यमंत्री जी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट में हरियाणा का कितना शेयर है और झाड़ली वाले प्लांट में कितना शेयर है और झाड़ली वाला प्लांट सरकार लगा रही है या प्राइवेट है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो 1500 मेगावाट क्षमता का प्लांट है उसमें 750 मेगावाट शेयर हमारा है और 750 मेगावाट अर्थात् 50 परसैंट शेयर दिल्ली का है, 50 परसैंट हमारा हरियाणा प्रदेश का शेयर है और जो 1320 मेगावाट का प्लांट है वह प्राइवेट कम्पनी लगा रही है और उसमें से 100 परसैंट बिजली हरियाणा प्रदेश को मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपने पहली बार बैठकर प्वायंट ऑफ आर्डर मांगा है इसलिए मैं आपको इजाजत देता हूं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा ही सिम्पल सा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आलू प्याज के भाव के संबंध में डील करने के लिए किसी कम्पनी को इंगेज किया गया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उसका फायदा किसान को मिलेगा या व्यापारी को मिलेगा ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जब तक आलू का ऐक्सपोर्ट नहीं खुलेगा तब तक हमारे किसान को उसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी। जब बाहर से कंपिटीटर आएंगे, तभी किसान को उसका पूरा और उचित भाव मिल सकता है। अभी पिछले दिनों किसान का आलू पिट गया था और उसका रेट एक या डेढ़ रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो गया था। भाव तो तभी मिलेगा जब बाहर से कोई कम्पनी खरीदने के लिए तैयार होगी। आज वह कम्पनी बाहर से आई है उसकी वजह से आलू का भाव बढ़ा है। वह कम्पनी इस साल के लिए और अगले साल के लिए भी ऐग्रीमैंट करने के लिए तैयार है। मार्किटिंग बोर्ड से उसका एम.ओ.यू. साइन होगा। इसी प्रकार से यहां पर गन्ने के भाव की बात कही गई। यू.पी. का जहां तक सवाल है, वहां चुनाव से पहले गन्ने का हरियाणा से कुछ ज्यादा भाव दिया गया है। विपक्ष के मेरे साथियों ने जो बात यहां उठाई है उसके बारे में वह साथ ही यह भी बताएं कि जो भाव दिया गया है क्या वह भाव सभी गन्ना उत्पादकों को मिल गया है ? उनको गन्ने की कीमत मिल गई या पेमेंट हो गई आज तक इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। इनकी सरकार के समय में गन्ने की पेमेंट किसानों को नहीं हुई थी। नारायणगढ़ शुगर मिल की पेमेंट हमारी सरकार आने के बाद कराई गई थी। जब किसान पेमेंट लेने के लिए जाते थे तो उन पर ये घोड़े दौड़ा दिया करते थे। इस बारे में सारे सदन को मालूम है। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय वर्ष 2001 में गन्ने का भाव क्या था अरली वैरायटी का भाव उस समय 110 रुपये प्रति क्विंटल था, वर्ष 2002 में भी 110 रुपये प्रति क्विंटल था, वर्ष 2003 में गन्ने का भाव 110 रुपये प्रित क्विंटल था और वर्ष 2004-05 में गन्ने का भाव 117 रुपये प्रति क्विंटल था। उसके बाद जब वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने गन्ने की अगेती फसल के लिए पहले 135 रुपये प्रति क्विंटल किया, उसके बाद 138 रुपये प्रति क्विंटल किया, वर्ष 2008 में 170 रुपये प्रति क्विंटल किया और वर्ष 2009-10 में 185 रुपये प्रति क्विंटल किया और उसके

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

बाद 25 रुपये प्रति क्विंटल उस पर बोनस भी दिया। उसके बाद वर्ष 2010-2011 में हमने गन्ने का भाव 220 रुपये प्रति क्विंटल किया और वर्ष 2011-2012 में 231 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव हम दे रहे हैं। ये माननीय सदस्य अपने समय का रिकार्ड देखें और फिर बात करें। गन्ने का सबसे ज्यादा भाव हमारी सरकार ने दिया है यह सारा सदन जानता है। उसके बाद इन्होंने बाजरे की खरीद की बात की और कहा कि इन्होंने एक-एक दाना खरीदा था चाहे वह सड़ा हुआ ही क्यों न था। राजस्थान और पंजाब का बाजरा भी इन्होंने खरीदा। सभी को मालूम है कि बाजरा जल्दी खराब हो जाता है. इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने 1999-2000 में बाजरे का एक भी दाना नहीं खरीदा, वर्ष 2000-2001 में भी इन्होंने एक भी दाना नहीं खरीदा और वर्ष 2002-2003 में भी इनकी सरकार ने बाजरे का एक भी दाना नहीं खरीदा। उसके बाद वर्ष 2003 में इन्होंने बाजरे को 505 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने वर्ष 2007-2008 में 600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजरा खरीदा, वर्ष 2010-2011 में 880 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजरा खरीदा और वर्ष 2011-2012 में 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजरा खरीदा गया जो भी बाजरा आया वह हमारी सरकार ने खरीदा। ये पंजाब और राजस्थान के सड़े हुए बाजरे की खरीद की बात कह रहे हैं। क्या मालूम क्यों खरीद रहे थे ? यह बात तो ये ही बता सकते हैं। इन्होंने हरियाणा के किसानों का बाजरा बिल्कुल भी नहीं खरीदा और ये बात करते हैं कि राजस्थान और पंजाब के बाजरे की खरीद की।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 880 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजरे की खरीद की बात कह रहे हैं जबकि हरियाणा के किसानों का बाजरा 600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा गया है। इन्होंने 880 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा कहां पर खरीदा है इसके बारे में ये सदन में आंकड़े प्रस्तुत करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-2011 में 880 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 73,653 क्विंटल बाजरा खरीदा गया और वर्ष 2011-2012 में 980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदा गया है वह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथियों ने लैंड एक्विजीशन की बात कही है। आज पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनियां में हमने एक उदाहरण पेश किया है। दुनिया में शायद लैंड एक्विजीशन की पॉलिसी ऐसी कहीं भी नहीं आई जो किसानों को उचित भाव भी दे और एन्यूटी भी दे, सिर्फ हरियाणा सरकार ही ऐसी पॉलिसी लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि समय के अनुसार जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमने जमीन के फ्लोर रेट भी फिक्स किए हैं जिन्हें समय-समय पर हम बढ़ाते भी रहे हैं। जहां तक किसान का सवाल है खाली फ्लोर रेट नहीं बल्कि हमने कलैक्टर रेट जो भी मार्किट में हाईएस्ट रेट होता है वह रेट हमने किसान को दिया है और साथ में एन्यूटी भी दी है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं एक उदाहरण सदन में पेश करना चाहता हूं। इनके समय में पानीपत रिफाईनरी के लिए 756 एकड़ भूमि एक्वायर की गई थी उन किसानों को इन्होंने 3,50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था जबकि हमारी सरकार आने के बाद पानीपत रिफाईनरी के लिए 671 एकड़ भूमि एक्वायर की गई जिसका मुआवजा हमने 19 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है जोकि छः गुणा ज्यादा दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है। चौटाला साहब के समय की सरकार का एक उदाहरण मैं सदन के सामने दोहराना चाहता हूं कि किस प्रकार किसानों को इनकी सरकार के समय में लूटा गया था। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि समय के साथ जमीन के भाव बढ़ जाते हैं लेकिन अप्रैल, 1997 में आई.एम.टी., मानेसर

में 1750 एकड़ भूमि का एवार्ड हुआ था। जिसका मुआवजा लगभग साढ़े 6 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया था। इसके बाद इनकी सरकार आई और जुलाई, 2003 में 172 एकड़ जमीन आई.एम.टी. के लिए एक्वायर की गई जिसका मुआवजा 6 लाख 35 हजार रुपये दिया गया यानि कि मुआवजे का रेट घटाया गया। 6 साल के बाद जो जमीन एक्वायर हुई उसका मुआवजा बढ़ाने के बजाय कम दिया गया है। आई.एम.टी., मानेसर के लिए दिसम्बर, 2003 में 598 एकड़ जमीन का इन्होंने अवार्ड किया जिसका मुआवजा इन्होंने 5 लाख 36 हजार रुपये प्रति एकड़ तय किया यानि और घटा दिया गया। इसके बाद मई, 2004 में 657 एकड़ जमीन का अवार्ड हुआ जिसका मुआवजा 4 लाख 74 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया जिसको सुनकर दिल रोता है। अध्यक्ष महोदय, मुआवजा बढ़ते हुए तो सुना है लेकिन इन्होंने तो घटाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया मुआवजा घटता गया। यह सब आपके सामने है और यह किसानों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है ? यह मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं बल्कि मैं आंकड़े बता रहा हूं। हमने मानेसर में 456 एकड़ जमीन का अवार्ड किया जिसका मुआवजा हमने 18 लाख 45 हजार रुपये के हिसाब से दिया। पंचगांव में 1128 एकड़ जमीन का अवार्ड हुआ जिसका मुआवजा 80 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने दिया। आई.एम.टी., मानेसर पटौदी रोड पर 53 एकड़ जमीन का अवार्ड हुआ जिसका मुआवजा हमने एक करोड़ 8 लाख 5 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया। आंकड़े खुद बोलते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने लगभग 3800 एकड़ जमीन पूरे हरियाणा में एक्वायर की है जिसमें बरवाला, राई, रोहतक, झज्जर, पानीपत और मानेसर आदि शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि--

हमारी बज्म और उनकी में फर्क इतना है कि

वहां चिराग यहां दिल जलाए जाते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल सही जानते हैं, आपका पैमाना बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एवरेज कम्पनसेशन हमारी सरकार के द्वारा जो आई है वह 57 लाख रुपये आई है और एनुयटी अलग है। इनकी सरकार में एवरेज कम्पनसेशन 2004-05 में 5 लाख 8 हजार रुपये आई है। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 57 लाख रुपये और कहां 5 लाख 8 हजार रुपये यानि आंकड़े सब कुछ बोलते हैं। सिरसा म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर चौधरी मैमोरियल ट्रस्ट में किसी ने जमीन गिफ्ट की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी के लिए 80 हजार रुपये प्रति एकड़ का भाव लगाया यानि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को लूटने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत सी हैं लेकिन मैं ज्यादा समय खराब न करते हुए कहना चाहूंगा कि यहां सबने एस.ई.जैड. के बार में बात की। इन्होंने कहा कि एक एस.ई.जैड HSIIDC ने लगाया और उसका नोटिफिकेशन 29 जनवरी, 2003 को इनकी सरकार के दौरान हुआ। उस नोटिफिकेशन को मैं ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं। इसमें इन्होंने लिखा है - That land specified below is needed by the Government at the public expenses or a public purpose namely for setting up of industrial complex to be in the planed and developed as SEZ panel phase-1, in Village Khandsa, Nursingpur, Mohamadpur Jharsa, Badoli Khurd and Harshru Ghari, Harshru Teh. and District Gurgaon by HSIIDC. यह इनके समय की बात है 14.00 बजे और उस जमीन का मुआवजा हमारी सरकार आने के बाद हमने दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद रिलायंस कम्पनी की प्रपोजल आई कि वे 25 हजार एकड़ जमीन में एस.ई.जैड बनाना चाहते हैं। विपक्ष के साथी कभी उसके समर्थन में आ जाते हैं और कभी विरोध करते हैं। (विघ्न)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम समर्थन में कब आये ? मुख्यमंत्री जी *** बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अजय सिंह जी ने जो यह अनपार्लियामैंटरी शब्द कहा है यह रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड निकलवाकर देख लिया जाये कि इन्होंने यह कहा था कि जस समय एस.ई.जैड की बात आई उस समय हम यह समझते थे कि लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को रैवेन्यू मिलेगा इसलिए हम इसका समर्थन करते थे। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है, आप चाहे निकलवाकर देख लें। अब यह कह रहे हैं कि इन्होंने एस.ई.जैड का कभी समर्थन नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है कि जिस समय एस.ई. जैड सैंशन किया गया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का यह ब्यान था कि लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और हजारों करोड़ रुपये का रैवेन्यू स्टेट को मिलेगा। उस एस.ई.जैड के नाम पर पिछले 6 साल के अर्से में एक भी रोजगार नहीं मिला है। वह एस.ई. जैड अब समाप्त कर दिया गया है। जिस एच.एस.आई.आई.डी.सी. की जमीन का जिक्र किया गया वह जमीन तो सरकार कम्पनी से वापिस ले रही है लेकिन जिन किसानों की जमीन रिलायंस ने 20-22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ठगी थी उस जमीन को आज वे करोड़ों रुपये के भाव बेच रहे हैं। आज किसानों को उस जमीन के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। जबकि शर्त यह रखी गई थी कि एक प्लाट मिलेगा। आज उन किसानों की जमीन का क्या हो रहा है ? वह हजारों एकड़ जमीन दूसरी कम्पनीज को बेची जा रही है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for fifteen minutes.

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : OK, the time of the sitting of the House is extended for fifteen minutes.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता हर बारी वही लफ्ज और वही तरीका यूज कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकार ने कोई जमीन नहीं खरीदी। झज्जर के जिस एस.ई.जैड की ये बात कर रहे हैं इन प्रिंसीपल हमने एप्रूव किया था वह एस.ई. जैड कभी नोटिफाई नहीं हुआ। वहां पर इण्डस्ट्रीज लगेंगी और लग भी रही हैं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की पॉलिसी बदलने के कारण पूरे देश में ही एस.ई.जैड. नहीं लगे क्योंकि एस.ई.जैड. पर मैट बना दिया। मैट का मतलब यह है कि अगर एस.ई. जैड लगे तो जो टैक्सीज हैं वे केन्द्र को भी और राज्य सरकार को नहीं

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मिलते हैं लेकिन रोजगार जरूर पैदा होते हैं। मिनिमम आलटरभेटिव टैक्स की पॉलिसी वे लेकर आये और उसी के मुताबिक कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्विटी का सवाल है जिस जमीन की नोटिफिकेशन एस.ई.जैड. के लिए इनके समय में हुई थी उस जमीन की हमने पूरे प्रोजैक्ट में 10 प्रतिशत एक्विटी रखी थी। वह प्रोजैक्ट कामयाब नहीं हुआ इसलिए हमने अपनी वह जमीन वापस लेने का आग्रह किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि कोई और होता तो इसमें कानून की लड़ाई लड़ते रहते लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक मैं समझता हूं रिलायंस कम्पनी वह जमीन वापस करेगी। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन रिलायंस कम्पनी ने खरीदी है जिसका ये बार-बार जिक्र कहते हैं उससे सरकार का कोई वास्ता नहीं है। वह जमीन रिलायंस ने किसानों से खरीदी है। हमने कम्पनी वालों को कहा है कि तुम किसानों को एन्यूटी दो और बिना किसी कानूनी पाबंदी के उन्होंने किसानों को एन्यूटी देनी शुरू कर दी इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय बुढ़ापा पेंशन की बात भी बहुत से सदस्यों ने उठाई। इस बारे में सुबह भी काफी चर्चा हुई। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में 14.68 लाख बुढ़ापा पेंशन के बैनीफीसीरिज थे अब वे 21 लाख हो गये इस तरह से इसमें 43 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। यह बात ठीक है कि इस बारे में कई जिलों से शिकायत मिली है कि बहुत सारी पेंशन काटी जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में किसी ने पी.आई.एल. डाल रखी है कि कुछ ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं जो बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। अभी मैंने आदेश दिया है कि ठीक है हम हाई कोर्ट की पालना करेंगे लेकिन सुओमोटो सीधी किसी की पेंशन नहीं काट सकते। तब तक सभी को पेंशन मिलती रहेगी जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती और उस पर निर्णय नहीं होगा। उसके बाद जो पात्र नहीं है उसी की पेंशन कटेगी। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने प्रदेश के कर्जे में दबे होने की बात भी कही कि प्रदेश पर कर्ज निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान के तहत किसी भी राज्य की बोरोइंग लिमिट केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय तय करता है। इस लिमिट का सीधा संबंध ग्रोस स्टेट डोमैस्टिक प्रोडक्ट से नापा जाता है कि जो कर्जा स्टेट ले आया वह स्टेट कर्जे का समय पर भुगतान कर भी सकती है या नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि वर्ष 2000-01 में डैट लाईबिलिटीज़ 13,552 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष 2004-05 में बढ़कर 23,320 करोड़ रुपये हो गई थी। इस प्रकार से चौटाला जी के समय में डैट लाईबिलिटीज़ 68.43 परसैंट बढ़ गई थी जबकि हमारे समय अर्थात् वर्ष 2005-10 तक यह डैट लाईबिलिटीज़ सिर्फ 49.3 परसैंट है। इस प्रकार से इनके समय में काफी एक्सीड़ था यानि वर्ष 2005 का 26,265 करोड़ रुपये का डैट वर्ष 2009-10 में 39,230 करोड़ रुपये हो गया। सबसे महत्वपूर्ण और नोट करने वाली बात यह है कि इनकी डैट लाईबिलिटीज़ जी.एस.डी.पी. की परसैंटेज़ हमसे कहीं अधिक थी। इस सम्बन्ध में मैं सारे आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर वर्ष 2001 से शुरू किया जाये तो वर्ष 2001 में अगर इनकी डैट लाईबिलिटीज़ जी.एस.डी.पी. से लगाये जाये तो वह 23.81 थी, इसी प्रकार से वर्ष 2002 में 25.75 थी और वर्ष 2002-03 में 25.8, वर्ष 2003-04 में 26.9 और वर्ष 2004-05 में 24.34 थी। इसके विपरीत जी.एस.डी.पी. के हिसाब से हमारी डैट लाईबिलिटीज़ वर्ष 2005 में 24.12 प्रतिशत, वर्ष 2006-07 में 21.37 प्रतिशत थी। इसी प्रकार से देखा जाये तो हमारे समय में डैट लाईबिलिटीज़ निरन्तर घटती आ रही है। जैसे वर्ष 2007-08 में 18.90 प्रतिशत, वर्ष 2008-09 में 17.43 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 में 17.67 प्रतिशत थी अर्थात् वर्ष 2005-10 तक डेट लाईबिलिटीज़ 49.3 प्रतिशत थी। इसी प्रकार से जो वर्ष 2010-11 के रिवाईज्ड एस्टीमेट्स में डैट लाईबिलिटीज़ परसैंटेज़ में आ रही है वह 17.58 प्रतिशत है और इसी प्रकार से वर्ष 2011-12 के बजट एस्टीमेट्स में 17.4 प्रतिशत

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

है। अध्यक्ष महोदय, इस सबके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि वर्ष 2000 से 2005 तक के दौरान चौटाला जी की सरकार द्वारा कुल 26 हजार 73 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया जबकि इसके विपरीत वर्ष 2005 से 2010 तक के अगले पांच सालों में हमारे द्वारा 18,548 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। इस सबको आप तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। अगर किसी सरकार द्वारा कर्ज़ा लिया जाता है तो वह विकास के लिए लिया जाता है। वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक के दौरान जो कैपिटल एक्सपैंडीचर 8,308 करोड़ रुपये था वह अब हमारे समय में बढ़कर 17,725 करोड़ रुपये हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमने 113 प्रतिशत की बढ़ौतरी कैपिटल एक्सपैंडीचर में दी है ताकि इससे प्रदेश के असैट्स क्रियेट हों। हर साल का मेरे पास पूरा ब्यौरा है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण और नोट करने वाली बात यह है कि हमारा कैपीटल एक्सपैंडीचर वर्ष 2005-10 के दौरान कर्ज़े से अधिक है यानि हमारे समय में कर्ज़ा कम है और कैपीटल एक्सपैंडीचर ज्यादा है जबकि इसके विपरीत चौटाला जी के समय में कर्ज़ा ज्यादा था और कैपीटल एक्सपैंडीचर कम था। किसी भी सरकार की सक्सैस को नापने का यह पैमाना है। स्पीकर सर, अब आप प्लान एक्सपैंडीचर के बारे में देख लें। वर्ष 2004-05 में प्लांड एक्सपैंडीचर केवल 2108 करोड़ रुपये था और वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर 13,400 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार से इसमें 6 गुणा की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 से लेकर 2005 के दौरान जो expenditure incurred on Plan था वह 9,325 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2005-10 के दौरान 29,713 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार से इसमें 222 परसैंट की ग्रोथ है। इस सम्बन्ध में साल भर की एक्चुअल फीगर्ज़ मेरे पास हैं। (विघ्न)

वॉक आउट

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या प्वायंट ऑफ आर्डर है ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि हमारा जो डैट बढ़ रहा है उसके बारे में जी.एस.डी.पी. की परसैंटेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताई है लेकिन हमारी जो प्लान बढ़ रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके हिसाब से जी.एस.डी.पी. की परसैंटेज़ भी बतायें।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है यह तो क्वेश्चन है। It is a question. (Noise & Interruption) O.K. it's alright. Please take your seat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जो प्लान का अमाउंट है वह सब-बजट पर आता है इसलिए जब सदन में बजट आयेगा तो इनकी बात का जवाब अपने आप आ जायेगा। मैंने आपको आंकड़ों के साथ इनकी सरकार के समय की हकीकत बताई है। इनको तो यह भी मालूम नहीं है कि इस बात की चर्चा बजट पेश होने के बाद की जानी चाहिए इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब बजट पेश होगा तो आप इनको इसकी चर्चा करने का मौका दे दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, *******

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Mr. Vij, no sitting commentary please. Not to be recorded.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, न तो आप हमें बोलने के लिए अलाऊ कर रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब ही दिया है इसलिए एज़ ए प्रोटेस्ट हम वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य श्री अनिल विज को उनके प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए समय न दिये जाने के कारण सदन से वॉक-आउट कर गये)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इनके समय में एवरेज एक्सपैंडीचर ग्रोथ 4.8 प्रतिशत थी और हमारे समय में एवरेज एक्सपैंडीचर ग्रोथ 35.7 प्रतिशत है। इनका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसी प्रकार से एक्सपैंडीचर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर नजर डाली जाये तो 2004-05 में 817 करोड़ रुपये था जो अब 2011-12 में बढ़कर 4708 करोड़ रुपये हो गया है जो कि 476 परसैंट की बढ़ौतरी है। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि कर्जा कहां जा रहा है। कर्जा तो सबके सामने एक्सप्लेन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के दौरान करंट प्राइसिज पर जी.एस.जी.पी. 51375 करोड़ रुपये थी जो 2011-12 में बढ़कर 309326 करोड़ रुपये हो गई है जो कि 500 परसैंट से अधिक की बढ़ौतरी है। 1999-2000 के दौरान पर केपिटा इन्कम ऑन करन्ट प्राइसिज 23222 रुपये थे और अब यह बढ़कर 109227 रुपये हो गई है अर्थात् 370 परसैंट की बढ़ौतरी हुई है जो कि देश में सबसे अधिक है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सबका सहयोग और समर्थन मांगता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का सदन की तरफ से धन्यवाद करते हुये इतना ही कहूंगा कि :-

मंजिल उनको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता, हौंसलों में उडान होती है।

धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is----

"That an Address be presented to the Governor in the following terms :----

'That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd February, 2012.'

The motion was carried.

वर्ष 2011-12 के लिये अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2012-2013 (Second Instalment).

Finance Minister (Sardar H.S. Chattha) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates 2012-2013 (Second Instalment).

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Rao Dharam Pal, Chairperson of Estimates Committee will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2012-2013 (Second Instalment).

Rao Dharam Pal (Chairperson, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2012-2013 (Second Instalment).

वर्ष 2011-2012 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, discussion and voting on Supplementary Estimates 2012-2013 (Second Instalment) will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper (No. 1 to 3, 5, 7 to 11, 13 & 14, 16 to 25, 28, 30, 32 & 33, 35 to 38, 40 and 42) will be deemed to have been read and moved together and a general discussion on the supplementary demands is permitted. The Members are, however, requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding ₹5,07,45,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 1 - Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹6,36,35,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 2 - Governor and Council of Minister.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹4,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 3 - General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹55,71,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 5 - Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,41,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 7 - Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 8 - Building & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 9 - Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹105,33,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 10 - Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹17,33,55,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 11- Sports and Youth Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹9,17,13,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 13 - Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,87,52,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 14 - Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 16 - Labour.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹3,13,56,000/- for revenue expenditure and ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 17 - Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure and ₹2,82,70,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 18 - Industrial Training.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,98,09,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 19 - Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 20 - Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹53,01,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 21- Women and Child Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,63,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 22 - Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹426,75,50,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 23 - Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹5,05,02,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 24 - Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,56,72,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 25 - Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,56,19,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 28 - Animal Husbandry and Dairy Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹3,14,65,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 30 - Forests and Wild Life Department.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹124,37,15,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 32 - Rural & Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹3,41,67,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 33 - Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹6,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 35 - Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹15,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 36 - Home.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹4,42,78,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 37 - Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹510,54,12,000/- for revenue expenditure and ₹19,22,01,000/-for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 38 - Public Health and Water Supply.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹269,43,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 40 - Energy and Power.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹5,43,99,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 42 - Administration of Justice.**

(No Member rose to speak).

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹5,07,45,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 1 - Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹6,36,35,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 2 - Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹4,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 3 - General Administration.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹55,71,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 5 - Excise & Taxation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,41,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 7 - Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 8 - Building & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 9 - Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹105,33,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 10 - Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹17,33,55,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 11- Sports and Youth Welfare.**

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹9,17,13,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 13 - Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,87,52,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 14 - Urban Development.**

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 16 - Labour.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹3,13,56,000/- for revenue expenditure and ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 17 - Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure and ₹2,82,70,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 18 - Industrial Training.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,98,09,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 19 - Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 20 - Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹53,01,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 21- Women and Child Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,63,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 22 - Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹426,75,50,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 23 - Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹5,05,02,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 24 - Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹2,56,72,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 25 - Industries.**

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹1,56,19,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 28 - Animal Husbandry and Dairy Development.**

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹3,14,65,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 30 - Forest and Wild Life Department.**

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹124,37,15,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 32 - Rural & Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹3,41,67,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 33 - Co-operation.**

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹6,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 35 - Tourism.

That a Supplementary sum not exceeding ₹15,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 36 - Home.

That a Supplementary sum not exceeding ₹4,42,78,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 37 - Elections.

That a Supplementary sum not exceeding ₹510,54,12,000/- for revenue expenditure and ₹19,22,01,000/-for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 38 - Public Health and Water Supply.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹269,43,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 40 - Energy and Power.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹5,43,99,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 42 - Administration of Justice.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 5th March, 2012.

*14.15 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday the 5th March, 2012).

50092—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY